हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

[illegible] मार्च, 2013

खण्ड [illegible], अंक [illegible]

अधिकृत विवरण

विषय सूची

[illegible]

हरियाणा विधान सभा

सोमवार , 14 मार्च, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : यह सदन 11 मार्च, 2011 को जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न विनाशकारी सुनामी से मारे गये निर्दोष लोगों के असामयिक एवं दु:खद निधन पर अपना गहरा शोक प्रकट करता है।

जापान के इतिहास का यह अब तक का सबसे भयंकर भूकम्प माना जा रहा है और इससे उत्पन्न सुनामी चक्रवात से जापान के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हज़ारों निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ-साथ वहां आवासीय क्षेत्रों में हुई भारी क्षति के अतिरिक्त जापान के आधारभूत ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यह सुनामी चक्रवात कई किलोमीटर तक अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को अपने साथ बहा कर ले गया।

इस सुनामी चक्रवात से जापान के लोगों पर जो कहर बरपा है उसका शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। असहाय दु:ख की इस घड़ी में हरियाणा प्रदेश की समूची जनता उनके साथ है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है और सुनामी चक्रवात से पीड़ितों के शीघ्र पुनर्वास की कामना करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह की धर्मपत्नी एवं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेजवीर सिंह की माता श्रीमती कमला देवी के 11 मार्च, 2011 को हुए दु:खद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ० रघुवीर सिंह कादियान की ताई जी श्रीमती शन्नो देवी पत्नी स्वर्गीय श्री फतेह सिंह के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।

यह सदन पानीपत जिले के गांव चमराड़ा के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरत सिंह के 13 मार्च, 2011 को हुए निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डॉ० अजय सिंह चौटाला (डबवाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल 11 मार्च, 2011 को जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न विनाशकारी सुनामी से मारे गये निर्दोष लोगों के असामयिक एवं दु:खद निधन पर अपना गहरा शोक प्रकट करती हैं।

जापान के इतिहास का यह अब तक का सबसे भयंकर भूकम्प माना जा रहा है और इससे उत्पन्न सुनामी चक्रवात से जापान के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ-साथ वहां आवासीय क्षेत्रों में हुई भारी क्षति के अतिरिक्त जापान के आधारभूत ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यह सुनामी चक्रवात कई किलोमीटर तक अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को अपने साथ बहा कर ले गया। इसके अलावा वहां के परमाणु संयंत्रों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

इस सुनामी चक्रवात से जापान के लोगों पर जो कहर बरपा है उसका शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। असहाय दु:ख की इस घड़ी में मैं, हमारी पूरी पार्टी और हरियाणा प्रदेश की समूची जनता उनके साथ हैं।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और सुनामी चक्रवात से पीड़ितों के शीघ्र पुनर्वास की कामना करता हूं।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह की धर्मपत्नी एवं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेजवीर सिंह की माता श्रीमती कमला देवी के 11 मार्च, 2011 को हुए दु:खद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के सदस्य डॉ० रघुवीर सिंह कादियान की ताई जी श्रीमती शन्नो देवी पत्नी स्वर्गीय श्री फतेह सिंह के दु:खद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से जिला पानीपत के गांव चमराड़ा के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरत सिंह के 13 मार्च, 2011 को हुए निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जिस दिन जापान में यह त्रासदी हुई, उसी दिन शाम को मैंने जापान के एम्बैसडर से बात करके हरियाणा के लोगों की तरफ से सहानुभूति जाहिर कर दी थी क्योंकि जापान के लोगों का बहुत सारा निवेश हरियाणा प्रदेश में है।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैन्ट) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से 11 मार्च, 2011 को जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर आए भीषण भूकम्प से उत्पन्न विनाशकारी सुनामी से मारे गये निर्दोष लोगों के असामयिक एवं दु:खद निधन पर अपना गहरा शोक प्रकट करता हूं।

जापान के इतिहास का यह अब तक का सबसे भयंकर भूकम्प माना जा रहा है और पिछले डेढ़ सौ वर्षों के बाद इस प्रकार का भूकम्प वहाँ पर आया है और उससे सुनामी चक्रवात उत्पन्न हुआ है जो जापान के साथ-साथ आसपास के देशों को भी प्रभावित कर सकता है। इस चक्रवात से वहाँ के

फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर भी बहुत बड़ा खतरा आ गया है और उसकी एक यूनिट में विस्फोट भी हुआ है। उस विस्फोट होने की वजह से लगभग 10 किलोमीटर रेडियस में लाखों लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा लेकिन खतरा अभी तक बना हुआ है। अभी उस प्लांट की 3 नम्बर यूनिट का भी टैम्प्रेचर बढ़ता जा रहा है। उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका है और उसमें रेडियो ऐक्टिविटी के बढ़ने का भी बहुत बड़ा खतरा अभी सबके सामने मंडरा रहा है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और सुनामी चक्रवात से पीड़ितों के शीघ्र पुनर्वास की कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह की धर्मपत्नी एवं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेजवीर सिंह की माता श्रीमती कमला देवी के 11 मार्च, 2011 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से जिला पानीपत के गांव चमराड़ा के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरत सिंह के 13 मार्च, 2011 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसे शोक प्रस्ताव जो उच्चकोटि के लोगों से राष्ट्र का निर्माण करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और राजनैतिक लोगों से जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, से संबंधित होते हैं तथा जब देश और दुनिया में ऐसी त्रासदी आती है तो उससे सारी दुनिया पर बुरा असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हमारी जो इकॉनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा इन्वैस्टमैंट जापान की है। इसलिए इस तरह की सुनामी आने का मुझे भी बहुत अफसोस है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं। मैं परम्परा की बात करना चाहता हूं क्योंकि आज के दिन जो ऑकेजन है इसको कोई राजनीतिक तौर पर अदरवाईज न ले, मेरी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा शोक प्रकट करने का तरीका है, वह ठीक नहीं है। एक बार सदन के लिए प्रस्ताव मूव हो जाता है चाहे वह मुख्य मंत्री जी पेश करते हैं या कोई मंत्री पेश करते हैं। उसके बाद जो उसको सैकिंड करते हैं उनको उसको अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से सैकिंड करना चाहिए न कि उसी बात को कहे कि 'यह सदन'। 'यह सदन' तो जो प्रस्ताव को मूव करने वाला होता है वह कह सकता है। उसके बाद जो प्रस्ताव रखे तो यह कहे कि मैं मेरी पार्टी की तरफ से इसको पेश करता हूं, या लोगों की तरफ से पेश करता हूं। मैं इसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। इसको हमें इस तरीके से पेश करना चाहिए। मान लीजिए मैं खड़ा हूं अगर मैं यह पढ़ूं कि 'यह सदन' तो यह उसी का रिपीटीशन करूंगा और उसी प्रस्ताव को पढ़ूं तो इससे वेस्टेज ऑफ टाईम है और दूसरी बात जो डीसैंसी की है, वह बात उसमें नहीं रहती है। इसलिए उसी बात को रिपीट करने से अच्छा है कि जो अपने कमैंट्स हैं, वे दिये जायें। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सुझाव है। बाकी माननीय सदस्यों की अपनी मर्जी है कि वे उसको मानें या न मानें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the obituary references made by the Hon'ble Chief Minister and the Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other members of the House. I feel deeply aggrieved on the sad and tragic death of thousands of persons killed in disastrous and infurious Tsunami in Japan. All of us have already read about it in the newspapers and I also seen on television. Humanity has suffered a lot and human-beings are helpless in such acts of God and we have no other alternative except to bear such natural calamities.

I also feel sorrow on the sad demise of Smt. Kamla Devi, wife of former Speakar of Haryana Vidhan Sabha, late Shri Ishwar Singh and mother of Shri Tejveer Singh, Ex-MLA. Smt. Shanno Devi, wife of Late Shri Fateh Singh, Aunt of Shri Raghubir Singh Kadian, member of Haryana Vidhan Sabha, Smt. Kamla Devi and Smt. Shanno Devi were pious and social ladies. Shri Surat Singh was a great freedom fighter and social worker. Shri Surat Singh, was a great freedom fighter of Panipat. He served the nation during the hard days of freedom struggle.

Hon'ble Members, since as said by Hon'ble Chief Minister, Japan is one of the big investors in Haryana, it is a matter of special concern and, as said, that the Ambassador of Japan has been conveyed the sentiments by the Hon'ble Chief Minister.

I pray to Almighty to give peace the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families and the concerned Embassy.

Now, a suggestion has come from Prof. Sampat Singh, I will consider it how to go about it.

Now, I request all of you to kindly stand up for two minutes to pay obeisance to the departed souls.

(At this stage, all the members of the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Question Hour.

Opening of Government Girls College in Safidon Constituency

*617. **Shri Kali Ram :** will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that there is no Government College for Girls in Safidon Constituency, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open the aforesaid College alongwith the time likely to be taken for opening the said College?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal, Matanhail) : Yes, Sir. There is a proposal under consideration of the Government to open a Government girls college in Safidon.

श्री कलीराम पटवारी : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह कन्या महाविद्यालय कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा और इसका नाम क्या होगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : स्पीकर साहब, मैं अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि वैसे तो सफीदों में इस समय हमारे पास गवर्नमैंट कालेज जो कि कोएड कालेज भी है, उसमें आर्ट, साईंस और कामर्स की क्लासिज आलरेडी चल रही हैं। सफीदों के कुछ लोग माननीय गवर्नर साहब से मिले थे और उनसे अपनी प्राब्लम बताते हुए कहा था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर गवर्नमैंट कालेज नहीं है। His Excellency the Governor साहब ने सफीदों में जाकर कालेज का नींव पत्थर रखा है। हमारे विभाग द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद अब यह मामला सी०एम० साहब के पास पैंडिंग है। जैसा मैंने आश्वासन दिया है कि एक इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी एजुकेशन सोसायटी, सफीदों है, उन्होंने कुछ फंड्स भी रेज किए हैं। वे हमें बिल्डिंग बनाकर देंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि कालेज का सैशन हम वर्ष 2011-2012 से शुरू कर देंगे। दूसरे इन्होंने जो कहा कि कालेज का नाम क्या होगा, सर सरकार इस कालेज को बनाकर देगी तो नाम के बारे जब कालेज ऐग्जिस्टैंस में आ जाएगा, तब बात करेंगे। इस समय कालेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 27 फरवरी, 2010 को इस कालेज का शिलान्यास किया था। वह लगभग 13 एकड़ जमीन नगरपालिका की है, बाकी उसमें कुछ दानी सज्जनों ने दान दिया है, लेकिन उसमें एक दो सज्जन ऐसे हैं जो उस कालेज का नाम अपने नाम पर रखवाना चाहते हैं इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता था कि उस कालेज का नाम सरकार के नाम से होगा या किसी प्राइवेट नाम से होगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने स्पष्ट किया है कि यह सरकारी कालेज होगा जो कि सरकार बनाएगी। मैचिंग ग्रांट के साथ-साथ जो ऐजुकेशन सोसायटी है उसके लोगों ने भी काफी सारा पैसा दान में दिया है। खुद गवर्नर साहब ने अपने निजी कोष से 10 लाख रुपया दिया है। वहां के एम०पी० श्री जीतेन्द्र सिंह मलिक ने भी उसके लिए 10 लाख रुपया दिया है, श्री टी०एस० गर्ग, रिटायर्ड इंजीनियर-इन-चीफ ने अपनी वाइफ लेट श्रीमती सरला के नाम से 25 लाख रुपया दिया है। इंदिरा प्रियदर्शिनी कन्या एजुकेशन सोसायटी ने भी इसमें करीबन 65 लाख रुपये की राशि खुद कलैक्ट करके दी है। जो म्युनिसिपल कमेटी की लैंड है, जहां पर गवर्नमैंट गर्ल्स कालेज, सफीदों खोला जाएगा, वह हमारे डिपार्टमैंट के नाम से हो जाएगी। हम 2011-12 में यह कालेज शुरू कर देंगे। जहां तक माननीय सदस्य नाम के लिए इनसिस्ट कर रहे हैं। हम तो एजुकेशन हब बनाने की बात कर रहे हैं। सफीदों पानीपत के नजदीक लगता है वहां पर एक गवर्नमैंट कालेज है जहां आर्ट्स एंड कॉमर्स की क्लासिज चल रही हैं। गवर्नमैंट कालेज, गोहाना भी मात्र 40 किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी ये आश्वासन दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसका फाउंडेशन रखा गया है। मैं सदस्य को कहना चाहूंगी कि हम वहां पर जो कालेज बनाएंगे वह गवर्नमैंट कालेज के नाम से बनाएंगे। वहां एक तो श्री टी०सी० गर्ग ने अपनी वाइफ के नाम से दान दिया है और जिन्होंने सोसायटी के माध्यम से फंड दिया है उनके नाम से हम वहां कोई न कोई लाइब्रेरी बना देंगे। (विघ्न)

श्री अनिल धंतोड़ी : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में कालेज खोलने की बात चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में हरियाणा में बहुत सारे कालेज बनाए हैं। मेरा जिला कुरुक्षेत्र जो इस हरियाणा प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध व ऐतिहासिक जिला है और मेरी कांस्टीच्यूएंसी नेशनल हाइवे नंबर-1 पर लगती है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे क्षेत्र के अंदर सरकार का कोई सरकारी कालेज खोलने का विचार है, यदि है तो बताएं और यदि नहीं है तो मेरा निवेदन है कि वहां सरकारी कालेज खोला जाए ?

Mr. Speaker : It is a supplementary or a request?

Shri Anil Dhantori : Sir, both supplementary as well as a request.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने शाहाबाद में कालेज खोलने के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की चर्चा की जो कि एक पावन पवित्र जिला है वहां पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके तहत बहुत से कालेज भी हैं। जहां तक शाहबाद की बात है शाहबाद के साथ लगते कुरुक्षेत्र जिले में हमारे 6 ऐडिड कालेज हैं और शाहबाद कांस्टीच्यूएंसी में भी दो ऐडिड कालेज हैं, उसमें एक एम०एन० कालेज है और दूसरे आर०ए० कन्या महाविद्यालय है। जो गवर्नमैंट ऐडिड प्राइवेट कालेज हैं उनको 4 करोड़ 67 लाख 12 हजार रुपये सरकार की तरफ से ग्रान्ट के रूप में दिये जा रहे हैं, इसलिए शाहबाद में कालेज खोलने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, I see as many as 15 hands have been raised. Madam Minister, can you construct as many colleges? Please reply for all others also.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि पूरे हरियाणा में कालेजिज खोलने की बहुत डिमाण्ड इस बार विधान सभा के पटल पर रखी गई है। जो कि यह दर्शाता है कि हरियाणा में शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस बार बजट में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रोविजन किया गया। साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जहां हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने की बात करते हैं वहीं हरियाणा प्रदेश में एलीमेंटरी, सकैण्डरी और हायर एजूकेशन को भी स्ट्रैंग्थन करने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वाकई इस समय स्कूल और कालेजिज खोले जाने से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज स्टूडेण्ट्स को शिक्षा में मिली हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Members, please be silent.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा तरक्की की है। हमारी सरकार आने के बाद पूरे हरियाणा में 20 से भी ज्यादा कालेजिज खोले गए हैं। इसके अलावा प्राईवेट ऐडिड कालेजिज को सरकार की तरफ से 190 करोड़ की ऐड दी गई है। इसी प्रकार प्राईवेट युनिवर्सिटी ऐक्ट के तहत भी कई प्राईवेट युनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी की यह सोच है कि वही समाज और वही प्रदेश तरक्की करेगा जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : Only one supplementary I allow Mr. Mohd. Iliyas. (Interruption) Hon'ble Members, if it is a request for construction of college, then you may send it in writing to the Minister.

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, सारा हाउस जानता है कि मेवात डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। मेरे हल्के पुन्हाना में जहां कि मैं नुमाइंदगी करता हूं वहां न बच्चियों का कालेज है और न बच्चों का कालेज है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये हाउस में बड़े-बड़े हुंकार भर रहे

हैं क्या पुन्हाना में कोई सरकारी कालेज खोलने का सरकार का विचार है, अगर है तो यह कालेज कब तक खोला जायेगा। मंत्री महोदया, कृपया बताने का कष्ट करें ? (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Nasim Ahmed Ji, you may also ask the supplementary question because I will ask the Hon'ble Minister to reply in one go. (Interruption) Mohd. Iliyasji, you are a senior Member. You can send your request in writing. नसीब साहब, अब आप क्वेश्चन पूछें।

श्री नसीब अहमद : अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा देने की बात कही जा रही है। आज भी मेवात को पिछड़ा हुआ मानते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेवात में आज तक लड़कियों का कालेज क्यों नहीं खोला गया ? अगर वहाँ पर कालेज खोला जायेगा तो कब तक खोला जायेगा ? (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगी कि . . . . . .

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं . . . . .

Mr. Speaker : Mr. Gurjar do you want to ask a supplentary question before the Minister replies ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर : जी हां सर।

Mr. Speaker : Alright, you can ask. She will rely to your question also.

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई डिमाण्ड नहीं है। मैं सिर्फ माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं, क्या मंत्री जी उनको गम्भीरता से लेते हैं ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is not a relevant question. (Interruption)

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Not to be recorded whatever Mr. Gurjar is saying. (Interruption) Please keep silent, Hon'ble Minister is replying.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगी कि जहां कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होती है उसी समय तुरन्त सी०एम० एनाउंसमैंट्स पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमैंट्री मेवात जिले को लेकर आई है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

मैं कहना चाहूंगी कि यह कालिंग अटैंशन मोशन मेवात जिले में एजूकेशन को लेकर पहले ही आ चुका है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी अब आफताब अहमद के यहां गए थे तो वे नूंह में एक गवर्नमैंट गर्ल्ज कालेज की घोषणा करके आए थे कि यह कालेज अतिशीघ्र खोल देंगे। अध्यक्ष महोदय, नगीना में गवर्नमैंट कालेज चल रहा है। तावडू में भी गवर्नमैंट कालेज है। मेवात में इस समय गवर्नमैंट एडिड प्राइवेट कालेज भी हैं। डिग्री कालेज नूंह में आर्ट्स, कॉमर्स और साईंस की पढ़ाई करवाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, सैल्फ फाइनांस के जो स्कूल और कालेज मेवात में शुरू किए गए हैं उनकी तो बहुत लम्बी लिस्ट है। अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं यह लिस्ट पढ़ दूंगी।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

Step to Prevent Floods

*623. **Shri Phool Singh Kheri:** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Guhla-Cheeka Constituency is affected by floods every year; and

(b) if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to protect the aforesaid Constituency from floods?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) No, Sir. This area is flood prone when there is heavy rainfall in the catchment area of River Ghaggar. Water spreads due to limited cunette capacity of the river course.

(b) The Government has taken following steps :—

(i) Construction of Kaushalya Dam.

(ii) Strengthening of left marginal bund of River Ghaggar in Guhla Cheeka area.

(iii) Desilting of the river bed at critical locations of Gulha-Cheeka area.

(iv) Pitching of bunds has been done recently.

(v) 10 No. flood protection schemes costing Rs. 15.5 crores approximately have been approved on 27th January, 2011 for flood proofing of Guhla Cheeka area.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

भाई फूल सिंह खेड़ी : अध्यक्ष महोदय, गुहला चीका निर्वाचन क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। किसानों की हजारों एकड़ फसल बरबाद हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए या फिर क्या उपाय किए जाने की संभावना है ?

श्री अध्यक्ष : इसका रिप्लाई तो मंत्री जी बता चुके हैं। (विघ्न) मंत्री जी आप हिन्दी में रिप्लाई दे दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो इनके एरिया में फ्लड से बचाने के लिए आलमोस्ट हर साल हम पैसा खर्च करते हैं। 2006 में 70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, 2007 में 75 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, 2008 में 2 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 2010 में 5 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बरसात के दौरान घग्घर नदी और मारकंडा नदी में फ्लड की वजह से काफी मात्रा में पानी आया और उसकी वजह से काफी जगह पर इनमें ब्रीचिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, बी०एम०एल० हांसी बुटाना लिंक कैनाल जो है उसकी आर०डी० 45000 से ऊपर हम 10 करोड़ रुपये की लागत से एक बांध बना रहे हैं ताकि वह दोबारा से न टूटे। 27 लाख रुपये की लागत से गांव भटेण और शिव माजरा में स्टोन पीचिंग करेंगे। एक गांव कसूरा उरलाना है जहां 32 लाख रुपये की लागत से स्टोर पीचिंग करेंगे। उरलाना में जो आर०डी० 51300 से लेकर 51600 है उस पर हम 39 लाख रुपये खर्च करेंगे। इसी प्रकार से स्लो पीचिंग के काम हम करेंगे। घग्गर पर आर०डी० 170500 से 118500 पर एक करोड़ 14 लाख रुपये खर्च करेंगे। इसी प्रकार जो पटेला नदी है उसकी जो ऐग्जिस्टिंग सैक्शन है, उसकी वाइडनिंग भी करेंगे और उस पर 59.65 लाख रुपये खर्च करेंगे। अध्यक्ष महोदय, टटियाना और कुशल माजरा सदेरी के नीचे से इनलैट बनाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पानी के आने से अंडर ग्राउंड चैनल्ज बंद हो गये थे, उसके ऊपर 38 लाख रुपये खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त घग्गर के नीचे साईफन लगाया जायेगा जिस पर 1.52 लाख रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार से टोटल 11.44 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

श्री धर्म सिंह छोकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे समालखा विधान सभा क्षेत्र का राणा माजरा से सीम्बलगढ़ तक करीब 35 कि०मी० एरिया यमुना से लगता है। वहां पर हथवाला से लेकर सीम्बलगढ़ का बांध पिछले 10-12 साल से टूटा हुआ है। वहां पिछली बार काफी बाढ़ आई थी जिसके कारण लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। क्या सरकार का वहां पर दोबारा से बांध बनाने का कोई प्रावधान है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य प्रश्न से अलग सवाल है। इस बारे में माननीय साथी मुझे लिखकर दे दें, हम एग्जामिन करवा लेंगे। वैसे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने 650 करोड़ की स्कीम फ्लड प्रोटैक्शन के लिए बनाई है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1.52 करोड़ की लागत से बी०एम०एल० का एक पुल और बनाया जाएगा। वहां जो पहले पुल बनाया गया उस समय इस प्रकार का सर्वे नहीं करवाया गया कि वह पुल घग्गर से आने वाले पानी के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो दोबारा से पुल बनाया जायेगा इसमें ऊपर से क्रौसिंग देंगे या किस प्रकार से किया जायेगा।

Mr. Speaker: This is a very speculative question.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि घग्गर का जो साईफन है वहां पर कंक्रीट की अंडर ग्राउंड वाल बनायेंगे और ऊपर पीचिंग करेंगे। इस पर 1.52 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। हम उसकी वाईडनिंग भी कर रहे हैं और कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं ताकि वह ज्यादा पानी लेने में सक्षम हो सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ मैंने स्वयं उस इलाके में जाकर देखा था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स ने कोशिश की कि यह दोबारा से ब्रीच न हो। घग्गर में काफी पानी आया था इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम कार्य कर रहे हैं कि ताकि आगे दोबारा से वहां पर ब्रीच न हो।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीछे जो बाढ़ आई उसकी वजह से यमुना नगर जिले में किसानों की फसल तो बरबाद हुई ही उसके साथ-साथ किसानों की बहुत सी जमीनें भी यमुना नदी में चली गई। जिन किसानों की जमीन यमुना नदी में चली गई क्या सरकार उनको मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फसल खराब होने की बात है उसके लिए गिरदावरी होती है और मुआवजा दिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी मुआवजा रिवाईज भी किया है।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन किसानों की जमीन नदी में चली गई, उनके बारे में प्रश्न किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो ज़मीनें कट कर नदी में चली जाती हैं उनकी एसैसमैंट करके 6000 रुपये से लेकर 12000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अम्बाला से लेकर करनाल-पानीपत तक जहां-जहां भी स्टड्स टूट गये थे उनको भी ठीक करवायेंगे। इसके लिए बाकायदा हमने आई०आई०टी० रुड़की से ड्राईंग भी मंगवाई है।

Misuse of Plastic Material for Packing

***394. Shri Aftab Ahmed :** Will the Environment Minister be pleased to state the details of measures taken by the Government for checking the misuse of plastic material for packing of goods available in the market?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

The following measures have been taken by the State Government to check the misuse of plastic material, including packing :

(i) The scope of restrictions on manufacturing, stocking, distribution, sale and usage of plastic carry bags in the State has been enlarged by imposing a complete ban since 3rd January, 2011.

(ii) Usage of plastic articles namely plates, cups, tumblers, spoons, forks and straw has been banned in the Municipal limits of Thanesar/Kurukshetra, Pehowa towns, Gram Panchayat Morni, precincts of Mata Mansa Devi

Temple, Panchkula, Sheetla Mata Temple, Gurgaon, Public Parks, National Parks and Wildlife Sanctuaries.

(iii) Containers made of recycled plastics for storing, carrying, dispensing or packing of food stuffs have been banned since January, 2009.

(iv) Littering of public places like parks, playgrounds, recreational places, tourist centres, religious places etc., with plastic articles is not permitted.

(v) Awareness programmes were organized to sensitize stake holders including school children and general public about the harmful effects of use of plastic carry bags/articles and promoting use of alternate materials such as cloth/jute bags.

(vi) Advertisements were issued in newapapers, radio jingles broadcast, hoardings displayed for creating mass awareness.

(vii) 1452 challans were issued against the violators in January-February, 2011 after the issuance of notification dated 3rd January, 2011.

(viii) 4 defaulting manufacturing units of plastic carry bags were closed.

In additon, the Ministry of Environmentand Forests, Government of India has banned manufacturing, stocking, distribution, sale and usage of sachets using plastic material for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala vide notification dated 4th February, 2011.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने के नतीजे आज हमारे सामने आ रहे हैं उसी तरीके से प्लास्टिक भी एक मैनेस है क्योंकि इससे नालियां और सीवरेज जाम हो जाते हैं और इसकी वजह से शहर में बहुत गंदगी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सरकार ने नया कानून प्लास्टिक बैग्ज पर प्रतिबंध लगाने का बनाया है इसमें किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है ? क्या इसमें स्ट्रिन्जेन्ट किया गया है ताकि समाज में प्लास्टिक बैग्ज पर रोक लगा सकें ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये जो प्लास्टिक का उपयोग है इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले हमने 30 से 40 माईक्रोन तक के कैरी-बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रयोग हरियाणा प्रदेश में अलाऊड किया हुआ था लेकिन फिर हमने यह पाया कि लोग इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं और प्लास्टिक का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है जिससे नालियां चौक हो रही थीं और हमारी वॉटर-बॉडीज़ भी खराब हो रही थी। इसके बाद हमने यह निर्णय लिया कि सरकार को इस दिशा में कुछ सख्त कदम उठाने चाहिएं। इसी के तहत हमने हरियाणा में कैरी-बैग्स के निर्माण और इस्तेमाल पर 3 जनवरी, 2011 को पूरी तरह से रोक लगा दी। उसके बाद जहां-जहां इस प्रकार की अनियमिततायें पाई गईं उन पर श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग जुर्माना किया गया जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जुर्माने की लिमिट हमने 25 हजार से 50 हजार रुपये तक रखी, रीटेल और वैण्डर्ज पर यह लिमिट 2500 रुपये से 5000 रुपये रखी और जो इंडीविजुअल वॉयलर्ज़ थे उनको 250

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

से 500 रुपये तक जुर्माना करते हैं। जनवरी-फरवरी, 2011 के दौरान हमने 1452 चालान किये हैं, 1 जनवरी, 2010 से लेकर 31 दिसम्बर, 2010 तक हमने 914 चालान किये हैं। वर्ष 2009-10 में हमने 837 चालान किये हैं। प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगाने के लिए हमने एक विशेष अभियान चला रखा है जिसके तहत एस०डी०एम०, तहसीदार, नायब-तहसीलदार, बी०डी०ओ० जैसे लोकल लेवल के ऑफिसर्ज़ को भी हमने चालान करने की पॉवर्ज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा यह मानना है कि जब तक इस बारे में समाज के अन्दर अवेयरनैस नहीं आयेगी तब तक प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को छोड़ने के प्रति पब्लिक में जागरुकता बढ़े इसके लिए हमने विभिन्न स्तर पर अवेयरनैस प्रोग्राम चलाये हैं। स्कूलों में अवेयरनैस कैम्प लगाये हैं, इंडस्ट्रिलिस्ट्स से भी इस बारे में बात की है। मैं यह मानता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि जब तक पब्लिक में अवेयरनैस नहीं आयेगी तब तक पूरी तरह से बात नहीं बनेगी। सरकार तो कानून बना सकती है और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कर सकती है जो हम अपने स्तर पर अच्छी तरह से कर रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने स्टॉकिस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के कितने चालान किये हैं? सैकण्डली जनरली यह देखा गया है कि छोटी दुकानों, रेहड़ी वालों, केले बेचने वाले, अमरूद बेचने वालों और पैटी शॉपकीपर्ज़ के चालान तो किये जाते हैं लेकिन वे सारे के सारे कैरी बैग्स आते कहाँ से हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टॉकिस्टों और मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स के चालान होने चाहिएं और पैटी शॉप्स के चालान नहीं होने चाहिएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, हरियाणा ने फरीदाबाद में चार डिफॉल्टिंग यूनिट्स के चालान किये हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये पॉलीथीन आते कहां से हैं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं वही बताने जा रहा हूं। हमने दिल्ली के अन्दर इस प्रकार की 13 यूनिट्स को आईडैंटीफाई किया है जिनमें ये पॉलीथीन बनाये जाते है। इसके साथ-साथ राजस्थान के अन्दर भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हालांकि राजस्थान में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण तौर पर बैन है। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर बैन लगाने के लिए हमने दिल्ली और राजस्थान सरकार को भी लैटर लिखे हैं कि ये जो आपके यहाँ पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आप इन पर बैन लगायें। इन यूनिट्स पर बैन लगाने के लिए हम सैन्ट्रल पॉल्यूशन बोर्ड से भी सम्पर्क साधेंगे। मैं समझता हूं कि इस मामले में जितने प्रयास हमने किये हैं उतने प्रयास किसी अन्य गवर्नमैंट ने नहीं किये हैं। आगे भी हम इस बारे में कारगर प्रयास करते रहेंगे। जो हमारे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भी मैंने विशेष तौर पर हिदायतें दी हैं। मैंने खुद उन्हें लैटर लिखे हैं। मैं स्वयं भी इस बारे में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश जी से भी जाकर मिला हूँ।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, why don't you extend this power to the MLAs also, they will see how many of them can challan it. They will not challan any of their constituents. Will next question please.

Depleting Under-ground Water Level

*492. **Smt. Sumita Singh:** Will the Agriculture Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to solve the problem of depleting under-ground water level?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): Sir, a statement containing the steps being taken by the Government to solve the problem of depleting under-ground water level is placed on the Table of the House.

Statement

Steps being taken by the Government to solve the problem of depleting under-ground water level —

The State Government has declared Year-2011 as "Water Conservation Year" and a number of steps are being taken for saving water and arrest the depletion of under-ground water level.

(A) Agriculture Department -

The Agriculture Department has taken the following steps for solving the problem of depleting under-ground water level -

(1) "Haryana State Preservation of Sub Soil Water Act, 2009" has been enacted which prohibits sowing and transplanting of paddy before 15th of May and 15th of June respectively. The ibid Act was notified on 18th March, 2009.

(2) The Department has introduced a State Plan Scheme from the year 2005-06, namely, "Accelerated Recharge to Ground Water" to recharge the ground water in water deficit areas of the State. Under this scheme, 418 Rain Water Harvesting structures have been constructed till March, 2010. A target of construction of 40 rain water harvesting structures has been fixed for the year 2010-11.

(3) The Department is also implementing National Watershed Development Project for Rain-fed Areas (NWDPRA), Flood Prone River (Ghaggar) and Sub Mountainous schemes under which activities like water harvesting structures, gully plugging, check dams, percolation embankments etc. are taken up. An amount of Rs. 846 lakh has been spent under the above schemes to treat an area of 7,604 hectares during 2009-10 whereas a budgetary provision of Rs. 747 lakh has been made for 2010-11 under these schemes out of which an amount of Rs. 354.50 lakh has been spent so far for treating an area of 3439 hectares.

(4) The Department is encouraging the farmers to adopt Drip and Sprinklers for irrigation to economize the use of irrigation water. For the promotion of Sprinkler System, subsidy @ 50% of the cost or Rs. 7,500 per hectare is being provided. So far, 1,04,758 sprinkler sets have been installed since the inception of the scheme in the State. An amount of Rs. 28.56 crore was given as subsidy during 2009-10 for promotion of sprinklers in the State. A total of 9,675 sprinklers were installed during the previous year whereas

[सरदार परमवीर सिंह]

an amount of Rs. 50 crore has been earmarked for the current year 2010-11 for installation of 16,000 sprinkler sets. Drip irrigation system is also being promoted on pilot basis in cotton (350 hectares) and sugarcane (150 hectares) during the current financial year.

(5) In order to prevent seepage and evaporation losses, the Department is providing subsidy to the farmers @ 50% of the cost or a maximum of Rs. 60,000 per beneficiary for laying Underground Pipe Line System (UGPL). An amount of Rs.3,815 lac has been spent for laying UGPL system in 39581 hectares till 2009-10 since the inception of the scheme in 2002-03. An amount of Rs. 45 crore has been earmarked for UGPL during 2010-11 for covering 46000 hectares in the State.

(6) Land leveling with Laser Levelers is being promoted which saves about 20% of irrigation water and improves crop production. Govt. has procured 120 Laser Levelers which are being run on custom hiring basis. A total of 14282 hectares has already been leveled during 2010-11 upto February, 2011. A total of 60 Laser Levelers have been supplied on subsidy (@50% of the cost of machine or Rs. 50,000/- whichever is less under RKVY scheme during 2010-11 upto February, 2011 whereas a total of 134 Laser Levelers have been supplied on subsidy from 2007-08, when the scheme was started, to 2009-10.

(7) Zero-tillage technology is being promoted which saves about 15% of irrigation water. A total of 1290 Zero-tillage machines have been supplied on subsidy (@50% of the cost of machine or Rs. 15,000/- whichever is less under RKVY scheme during 2010-11 up to February, 2011.

(8) Massive Awareness Campaign has been launched to educate the farmers regarding conservation of groundwater and judicious use of irrigation water. Farmers are being advised to grow less water intensive crops.

(B) Irrigation Department

Irrigation Department is taking remedial measures for the recharge of ground-water. A total of 26 recharge schemes have been completed so far by the department whereas 6 are in progress and 17 others are proposed to be taken up in near future.

(C) Haryana Urban Development Authority /Urban Local Bodies

(1) Haryana Urban Development Authority and Urban Local Bodies Department have made it mandatory for all Govt. buildings and private houses in HUDA Estates as well as Municipal Areas having roof top surface area of 100 square metres or more to have a Rain Water Harvesting Structure.

(2) HUDA has notified the Haryana Urban Development Authority (Erection of Buildings) Amendment-Regulations, 2001 on 31st October, 2001 whereas Urban Local Bodies Department has notified Haryana Municipal Building (Amendment) Bye-laws, 2002 on 13th December, 2002 for the purpose under reference.

(D) Rural Development Department

Rural Development Department is implementing centrally sponsored schemes namely Desert Development Programme (DDP), Integrated Wastelands Development Programme (IWDP) and MGNREGS, under which it has spent an amount of Rs. 111.32, Rs.19.26 and Rs. 109.34 crore respectively, covering an area of 139764 hectares, 25778 hectares and 7035 works (under MGNREGS) respectively during the period 2006-07 to 2010-11 (upto January, 2011).

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में बहुत ज्यादा पैडी लगायी जाती है जिसके कारण हमारे एरिया में वाटर लेवल नीचे जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करने जा रही है कि जो लोग पैडी लगाते हैं, अगर वे 25 परसैंट पैडी कम लगायें तो सरकार उनको कोई सबसिडी देगी ?

Sardar Paramvir Singh : Sir, I would like to tell the Hon'ble Member that the early variety of Paddy which is called Santhy, has been banned by the Government.

Smt. Sumita Singh : Speaker Sir, I am talking about the other variety.

Sardar Paramvir Singh : Right, you are talking about the normal paddy. This House has already passed a resolution we are going to bring a comprehensive Act which will take care of it. I cannot promise at this time but all aspects will be considered to arrest this problem and for that this House has passed a resolution.

Mr. Speaker : Thank you, Mr. Minister.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का सवाल यह था कि अगर कोई पैडी न लगाये तो क्या सरकार कोई इनसैन्टिव देगी ?

Mr. Speaker : The Government will come up with a comprehensive Act. So, let the comprehensive Act come then there will be discussion in the House in this regard.

Water upto Tails

***446. Shri Jagdish Nayar:** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that water does not reach upto the tails of Hodal distributary, Hassanpur distributary, Gochhi drain and Ujina drain for the last five years?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हां श्रीमान जी। गत् वर्षों में केवल कुछ दिनों को छोड़कर होडल रजबाह तथा हसनपुर रजबाह के अन्तिम छोरों तक पानी नहीं पहुंचा है। यह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा आगरा नहर से इन चैनलों में कम तथा अनिश्चित आपूर्ति छोड़ने के कारण हुआ है।

गोछी ड्रेन तथा उजीना ड्रेन बाढ़ का पानी लाती है और जब गुड़गांव नहर में अधिक पानी उपलब्ध होता है तब गुड़गांव नहर के एस्केप से इन ड्रेनों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। इन ड्रेनों के अन्तिम छोरों पर पानी पहुंचना आवश्यक नहीं है।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, पिछले 5 साल से अब तक रजबाहों में पानी टेल तक नहीं पहुंचा पाये हैं जबकि पिछली बार जब हमारी सरकार थी, उस समय इनकी टेल तक पानी पहुंचता था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि ये 5 साल में इनकी टेल तक पानी नहीं पहुंचा पाये? इन्होंने अपने जवाब में गोछी ड्रेन और उजीना ड्रेन का जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले गोछी ड्रेन और उजीना ड्रेन दोनों में पानी आता था। क्या सरकार ने बंचारी, सौंध, गोड़ोदा, गढ़ी, डाडका और बोराका गांवों के लिए कोई दूसरी नहर खोदने का प्रावधान रखा है ताकि उनकी सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पहले ही बताया था कि आगरा कैनाल का कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। उनको हमने बार-बार पत्र लिखे हैं। हमारे वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग की तरफ से उनको 17 मई, 2010 को एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार से ई०आई०सी० ने भी एक पत्र दिनांक 25 मई, 2010 को लिखा है। हमारे एस०ई० सर्कल ने भी पत्र लिखा है। इसके बाद जब हमने यह मामला अपर यमुना बोर्ड के सामने रखा तो उनके मैम्बर सैक्रेटरी श्री एस०के० साहू ने 1 फरवरी, 2011 को भी उनको एक पत्र लिख कर निर्देश दिये हैं कि हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी पहुंचाये। उन्होंने डिसिल्टिंग के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपये की मांग की है जिसकी हमने प्रशासकीय अनुमति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा कि पहले इनके यहां की नहरों की टेल फीड होती थी और अब पानी नहीं जा रहा है। इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि 1995 में कुल 135 टेलों में से कोई भी टेल फीड नहीं होती थी। 1996 में हमारी केवल 7 टेल फीड होती थी। इसके बाद 1998 में भी 7 टेल फीड होती रही हैं जबकि 2000 में कोई टेल फीड नहीं हुई। इसी प्रकार से 2004 में कोई टेल फीड नहीं हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष साहब, आप मेरी बात सुन तो लें।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister has not completed his reply so please sit down. (Interruption).

श्री जगदीश नायर : स्पीकर साहब, * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वर्ष 2006 में एक टेल फीड होती थी और 2007 में भी एक टेल फीड हुई, 2008 में एक टेल फीड हुई और वर्ष 2010 में 3 टेल फीड हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी यह बात बिल्कुल सही है। (शोर एवं व्यवधान) टोटल जो डिस्चार्ज है वह 80 से लेकर 100 के बीच में आता है जबकि अथोराइज्ड डिसचार्ज 224 है। इस बारे में एक चिट्ठी लिखकर हम उनको कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस प्रकार की बात की तो अगले एक महीने के बाद जितना पानी वे हमारा वहां से कम करेंगे उतना ही उनका पानी हम ताजेवाला हैड से कम करना शुरू कर देंगे क्योंकि वे इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। हमें कंस्ट्रक्टिव स्टैप्स लेने की जरूरत है। स्पीकर सर, हमारे प्रिंसीपल सैक्रेटरी, इरीगेशन यू०पी० गवर्नमैंट के अधिकारियों से बात करेंगे लेकिन अगर उसके बावजूद भी वे नहीं मानेंगे तो हमें यह कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। सर, दिक्कत यह आएगी कि इतना करने के बाद भी पानी वहां पर फिर भी

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

पूरा नहीं पहुंचेगा। सर, इसका तरीका यही है कि उनसे बातचीत करके हम उन्हें समझाने की कोशिश करें। सर, हम देखते हैं कि पानी काटने का उन पर क्या असर पड़ता है।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के बारे में पहले भी विधान सभा में सवाल उठते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में लेगी ? अध्यक्ष महोदय, मुझे पता लगा है कि इस बारे में पहले वायदा भी किया गया था। मंत्री जी केवल कागजी कार्यवाही के बारे में ही बता रहे हैं।

Mr. Speaker : No speech, please ask the question.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन यह है कि किठवाड़ी से आगे दो तीन रजबाहे हैं एक रजबाहा पलवल से होडल वाला और दूसरा रजबाहा पलवल से हथीन वाला है। (विघ्न) इनमें किठवाड़ी से आगे पानी ही नहीं जाता है। मुख्यमंत्री जी अगर इंक्वायरी करवाना चाहें तो इस बारे में कितने ही एफिडेविट उस क्षेत्र के गांवों वालों से लाकर मैं दे सकता हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : No need to reply. He is not asking a question? Next question please.

Steps to improve the Sanitation System in Faridabad City

***515. Shri Anand Kaushik:** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether it is a fact that the sanitation system in the Faridabad City has deteriorated badly; if so, the details of steps being taken by the Government to improve the sanitation system?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : श्रीमान जी। एक कथन सदन के पटल पर रखा जाता है।

कथन

यह कहना उचित नहीं है कि फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। फरीदाबाद शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं जो कि निम्नलिखित हैं:—

1. फरीदाबाद एवं गुड़गांव शहरों के एकीकृत ठोस कूड़ा कर्कट उपचार सनियंत्रण हेतु गांव बन्धवाड़ी में 600 मीट्रिक टन क्षमता के वेस्ट निष्पाद संयंत्र (processing plant) का निर्माण किया गया है जो 1 दिसम्बर, 2010 से शुरू कर दिया गया है। इस समय एन०आई०टी० फरीदाबाद का लगभग 200 मीट्रिक टन ठोस कचरा प्रतिदिन इकट्ठा कर बन्धवाड़ी संयंत्र पर भेजा जा रहा है।

2. एन०आई०टी० जोन के सभी घरों में कूड़ा इकट्ठा करने तथा बन्धवाड़ी संयंत्र तक पहुंचाने के लिए मै० रेमकी इन्वायरो लि० (M/s RAMKY ENVIRO LTD.) नामक कम्पनी को कार्य आबंटित किया जा चुका है।

3. दिल्ली मथुरा रोड के पूर्वी भाग पर बदरपुर बार्डर से झाड़सेतली गांव तथा नगर निगम की पूर्वी सीमा एवं दिल्ली मथुरा रोड के अन्दर के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था मै० सुलभ इन्टरनैशनल को आउटसोर्स की हुई है।

[श्री गोपाल काण्डा]

4. फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में घरों से ठोस कचरा इकट्ठा करने तथा छंटाई कर अलग-अलग करने (segregation) का कार्य कई गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) को आबंटित किया हुआ है।

5. गोछी ड्रेन की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने बारे 'व्यवहार्यता अध्ययन' (Feasibility study) हेतु कंसलटैन्टस से एक्सप्रैशन आफ इन्टरेस्ट (Expression of Interest) आमंत्रित किए जा चुके हैं।

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल में पूरे फरीदाबाद शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में विवरण पूछा गया था लेकिन मंत्री जी ने एन०आई०टी० फरीदाबाद के बारे में कह दिया, एन०आई०टी० जोन के बारे में कह दिया। गोछी ड्रेन तो एन०आई०टी० में लगती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरे फरीदाबाद शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में अपने जवाब में वर्णन नहीं किया। फरीदाबाद में म्यूनिसिपल अधिकारियों ने मंत्री जी को इस तरह का जवाब देकर घुमाने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : कौशिक साहब, आपने क्या कहा है, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया है?

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, जो क्वैश्चन मैंने पूछा था उसका विवरण मंत्री जी ने अपने जवाब में नहीं दिया है।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी शहरों की प्राब्लम तो वही है जो कौशिक साहब फरीदाबाद की बता रहे हैं। करनाल के बारे में कहा गया था कि वहां की इस तरह की समस्या को सौल्व करने के लिए सौलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट का काम शुरू करेंगे और उसका काम शुरू भी हुआ था लेकिन अभी तक भी उसका काम अधर में ही है। पिछले तीन साल से वह ऐसे ही पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उसका काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा और क्या कारण है कि उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, ये सैपरेट क्वैश्चन है इसलिए ये इस बारे में अपना क्वैश्चन लिखकर हमें भिजवा दें, हम इसका डिटेल रिप्लाई दे देंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रान्त के अंदर जितने भी नगर हैं वहां की सफाई व्यवस्था और वेस्ट को इकट्ठा करने की बहुत बड़ी समस्या है। जो ठेका सिस्टम, कंट्रैक्ट सिस्टम है वह भी कोई अच्छा नहीं चल पा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई इस बारे में कम्प्रेहेन्सिव प्लान सरकार के माईंड में है ताकि शहरों के वेस्ट की कलैक्शन हो और वहां की अच्छी तरह से सफाई हो ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, जो बड़े शहर हैं जैसे फरीदाबाद और गुड़गांव, उनके आसपास और उनकी सफाई की देखरेख के लिए हमने सोलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट लगाए हैं। एक तो बंधवाड़ी में 600 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट लगाया है। फरीदाबाद की 200 मीट्रिक टन वेस्ट उसमें आती है। इसी तरह से रोहतक व करनाल के आसपास भी प्लांट लगाये जाएंगे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के पटल पर रखा गया रिप्लाई है और जो ठोस कूड़ा कर्कट उपचार संयंत्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि

सैंट्रल गवनमैंट ने सैन्ट्रल इन्वायर्नमैंट मिनिस्ट्री से 43 शहरों का जो कि अति दूषित थे, सर्वे करवाया था। उस सर्वे में फरीदाबाद को 18वें नंबर पर व पानीपत को 37 नंबर पर रखा गया था। जिस तरह फरीदाबाद में प्लांट लगाने की बात मंत्री जी कह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पानीपत में भी डाइंग और ब्लीचिंग यूनिट्स हैं और अति दूषित शहरों के मानदंड में पानीपत का नंबर 37वां है तो क्या वहां भी मंत्री जी ऐसा प्लांट लगाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, पानीपत में भी इस तरह का प्लांट लगाने का मामला प्रौसेसिंग में चल रहा है।

श्री आनंद कौशिक : अध्यक्ष महोदय, जवाब में फरीदाबाद शहर का जिक्र ही नहीं किया गया है। वहां खुले में गंदगी पड़ी रहती है। सफाई की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सैक्टर 4 से सैक्टर 19 तक फरीदाबाद शहर की गिनती होती है।

श्री अध्यक्ष : फरीदाबाद का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसकी रिप्लाई की स्टेटमैंट सदन की टेबल पर रख दी गई है। (विघ्न) जो पॉलिथिन की बात यहां हो रही है, उसके बारे में मैं सोचता हूं कि चालान की पॉवर्ज सभी मैंबर्ज को भी दी जाएं? यदि ऐसा किया जाए तो क्या आप अपने-अपने हल्कों में चालान करेंगे?

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhry): Speaker Sir, this is for the information of the whole House that there is one village in District Bhiwani I forget the name of that village जहां पर सबने पंचायत में यह डिसाइड कर लिया है कि गांव में किसी को भी पॉलिथिन लेकर नहीं आने देंगे और यदि बाहर से कोई ले जाएगा तो उस पॉलिथिन को जमीन में गाड़ देंगे। (विघ्न)

To Lay Down Sewerage Line

***377. Smt. Kavita Jain:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down sewerage line in Mohalla Kot, Chaudhary Mohalla, Dhobi Wara, Thekedaron Wali Gali and Tambaku Wali Gali of Sonepat City; and

(b) if so, the time by which the work relating to sewerage is likely to be started thereon?

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhry) :

(a) Yes Sir.

(b) The work of laying of sewer in these colonies is likely to be started within two months.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरे सवाल में मोहल्लों के नाम मेंशन किए गए हैं यह विभाजन से पहले के हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जो विभाजन से भी पहले के मोहल्ले थे, उनमें भी आज तक सीवरेज की लाइन नहीं बिछ पाई है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, what is your question?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगी कि मंत्री महोदया ने सीवर बिछाने के बारे में जो टाइम लिमिट बताई है क्या वे उसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर हैं? साथ ही यह भी जानना चाहूंगी कि इस काम के लिए कितना अमाउंट सैंग्शन किया गया है ?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि यह बात ठीक है कि जो पुराने मोहल्ले हैं वहां 55-60 प्रतिशत एरिया ऐसे हैं they have already been provided sewerage facilities. In the House, I am saying कि 2011 तक यह कार्य कम्पलीट करवा देंगे। स्पीकर सर, इसका मतलब यह है कि हमने कोई सिस्टम बनाया होगा जिसके माध्यम से इसको बनाया जायेगा। दूसरी बात मैं माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि यही नहीं 69 ऐसी न्यू कालोनिज हैं जो टाऊन की आउटसक्रेट पर आ गई हैं उनको भी गवर्नमैंट ने एप्रूव किया है। एप्रूव करने के बाद वहां सीवरेज सिस्टम प्रोजैक्ट बनाया है यह 829.25 लाख रुपये का प्रोजेक्ट है जिसमें से 592 लाख रुपये पहले ही रिलीज किये जा चुके हैं। इसका सारा काम मार्च, 2012 तक पूरा हो जायेगा। इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहती हूं कि वहां पर दो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट पहले ही एग्जिस्ट करते हैं और इन दोनों की ऑगमैंटेशन के लिए हमने 95 करोड़ 63 लाख रुपये की detailed Project Report that has been submitted to the Government of India under Yamuna Action Plan-III. उसके अन्दर यह प्लान हम भेज चुके हैं। माननीय सदस्या के कहे बिना ही सरकार ने वहां काम शुरू किया है। इसके अलावा अलग से एक नया 25 एम०एल०डी० का सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट वहां पर लगने वाला है उसके लिए हमारी सरकार ने 9 करोड़ 16 लाख रुपये एप्रूव किये हैं और उसके लिए जमीन पूरी एक्वायर हो चुकी है, उस जमीन का एवार्ड भी दिया जाने वाला है। We are absolutely addressed and we know how important it is that we have to take care of these facilities and water. I would like to assure the Hon'ble Member that even what she has not asked me has already been done for his Constituency. (Interruption)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले भी अनुरोध किया गया था कि हाउस में ज्यादातर हिन्दी ही बोली जाए। * * * * * *

Mr. Speaker : Not to be recorded

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, रूल्ज़ ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस में ऐसा प्रावधान है कि सदन में दोनों भाषाओं का इस्तेमाल हो सकता है। जहां माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दी में बोला जाए तो माननीय मंत्री जी ने हिन्दी में ही जवाब दिया है वे कहेंगे तो पंजाबी में और उर्दू में भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम उर्दू में भी जवाब दे देंगे।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह जून : अध्यक्ष महोदय, मैं बहादुरगढ़ इल्के की बात कहना चाहता हूं। बहादुरगढ़ में लाइन पार क्षेत्र में आधा बहादुरगढ़ रहता है वहां पर सीवरेज सिस्टम और पीने के पानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2006 में 44 करोड़ रुपये सैंगशन किये थे। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। उस पैसे में आधे के करीब सीवर सिस्टम और पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं। तकरीबन एक साल से सैकेण्ड इन्सटाल का पैसा 29 करोड़ रुपये रुके हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस पैसे को कब तक रिलीज कर दिया जायेगा ताकि वहां पर लाइन पार एरिया में सिवरेज सिस्टम और पीने के पानी की व्यवस्था समय पर हो सके।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न इस प्रश्न से रिलेट नहीं करता है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को ऐश्योर करूंगी कि as soon as estimates are approved तो बाकी का काम है वह भी पूरा हो जायेगा। जब कोई काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां शुरू किया है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वह पूरा नहीं होगा।

Community Centre in Grain Market, Trawari

***483. Shri Mamu Ram:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Community Centre in the Grain Market of Trawari; if so, the time by which above stated Community Centre is likely to be set up?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): No Sir.

15.00 बजे **श्री मामू राम** : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि तरावड़ी कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है लेकिन वहां कोई भी कम्युनिटी सैंटर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मामूराम जी, यह प्रश्न इनकी मिनिस्ट्री का नहीं है। जहां तक इनका सवाल है तो इन्होंने कह दिया कि ये नहीं बनाएंगे। आपके पास इस प्रश्न से रिलेटिड कोई और बात हो तो करें।

Haryana Roadways Buses on Pinjore-Nalagarh Route

***559. Shri Pardeep Chaudhary:** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that only few buses of Haryana Roadways are plying on Pinjore-Nalagarh route; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of buses on the aforesaid route together with the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : नहीं, श्रीमान जी। वर्तमान में इस मार्ग पर हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के 5 वापसी चक्कर हैं। इसके अलावा अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों की बसों के भी 30 वापसी चक्कर हैं।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि वर्तमान में पिंजौर-नालागढ़ मार्ग पर हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के 5 वापसी चक्कर हैं। इसके अलावा अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों की बसों के 30 वापसी चक्कर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां आपको कागजों में अधिकारियों ने गुमराह किया हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही पिंजौर ब्लाक के 12-14 पंचायतों के लोग इस बारे में पंचकूला के डी०सी० और एस०डी०एम० से मिले थे। अखबारों और मीडिया में भी काफी आया है कि वहां बसों की भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों ने आपको गुमराह किया हुआ है। आप अधिकारियों से इस बारे में पूछें क्योंकि यह बिल्कुल झूठ है कि वहां 5 वापसी चक्कर हैं। वहां एक दो बसों का रूट है लेकिन वे बसें भी वहां पर नहीं रुकती। लोगों में बड़ा भारी रोष है। हम अधिकारियों से भी बार-बार मिले हैं और अखबारों में भी हमने बार-बार दिया है, लेकिन इस बारे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह बिल्कुल * * * * * है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह * * * * * शब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह * * * * * * शब्द रिकार्ड न किए जाए।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, ये जहां तक गुमराह की बात करते हैं तो हम कोई ऐसे बेवकूफ तो नहीं हैं कि हमारे अधिकारी हमें गुमराह करेंगे। जहां तक 5 वापसी के चक्कर की बात है अगर 5 वापसी के चक्कर न हों तो हम इनके गुनहगार होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य परिवहन पिंजौर-नालागढ़ रूट पर 5 वापसी के चक्कर चला रही है।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister. Take a call on it and check up with your Ministry also.

Shri Om Prakash Jain : O. K. Sir.

Erosion of Agriculture Land

*524. **Shri Rajbir Singh** : Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that huge erosion of agricultural land occurred due to floods in Markanda River in the villages situated on the banks of this river in Mulana Constitutency; and

(b) if so, whether any compensation has been given or is likely to be given to the affected farmers?

Revenue Minister (Shri Satpal Sangwan)

(a) Sir, some erosion is reported in Duliana, Gaganheri and Sabga village of Mulana Constituency alongwith river Markanda.

(b) The matter regarding providing relief is under active consideration of the Government.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो जुलाई में बाढ़ आई थी उस समय अम्बाला में भी बाढ़ आई थी। इनके तीन गांव गगनहेड़ी, दुलियाना और सबगा उस समय एफेक्टिड हुए थे। मारकंडा के बहाव से तीन गांवों में भूमि का कटाव तो हुआ था लेकिन इन तीन गांवों में कोई ज्यादा कटाव नहीं हुआ था। इन तीनों गांवों में मिलाकर एक एकड़ से भी कम भूमि का कटाव हुआ था। हमने तीनों गांवों में 13 लाख 76 हजार रुपये के हिसाब से सारे के सारे कटाव को ठीक करवा दिया था। एक गांव में तो हमने दीवार भी खड़ी करवा दी है जिस पर 5 लाख 37 हजार रुपये खर्च किए थे। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के समय जिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आई थी और पानी की वजह से फसल बरबाद हो गई थी, वहां सभी जगह हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अलावा भूमि कटाव की और किसी जिले की इन्फर्मेशन हमें नहीं मिली। सोनीपत जिले में टोटल 1662 एकड़ जमीन तथा यमुनानगर जिले में 1537 एकड़ जमीन का कटाव हुआ है। इसके मुआवजे के लिए 6000 रुपये प्रति एकड़ सैंट्रल रिलीफ फंड से और 6000 रुपये हमारी सरकार देने के बारे में कंसीडर कर रही है यानि टोटल 12000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह मुआवजा विचाराधीन बताया है। क्या यह किसानों को मिलेगा भी या विचाराधीन ही रहेगा ?

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुआवजा मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। That has been cleared from our Chief Minister. Within two months, not more than two months we will pay it. यह विचाराधीन नहीं रहेगा।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 12000 रुपये प्रति एकड़ कटाव वाली भूमि का किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। जो जमीन कटाव में चली गई वह तो हमेशा के लिए ही चली गई इसलिए इस 12000 रुपये से किसानों को क्या मदद मिलेगी ? बहुत से किसानों ने तो उस जमीन पर लोन भी लिया हुआ है।

Mr. Speaker : Bishan Lal ji, there is law regarding that.

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, 12000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा।

ROB No. 61A on NH-65 Hisar

*425. **Smt. Savitri Jindal :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether ROB No. 61A at Km. 191.176 on NH-65 Hisar is the life line of the city and movement of heavy traffic on the bridge has been closed;

(b) If so, whether North Western Railway has written to D.C. Hisar and S.E., PWD (B&R) Jind for providing a free of cost closure on this ROB for a period of six months and removal of electrical cables and other infringements free of cost to enable them to rebuild the ROB;

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

(c) If so, the present status in this regard; and

(d) The time by which this ROB is likely to be rebuilt?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a&b) Yes Sir, North Western Railway Bikaner Divison *vide* letter dated 28th November, 2007 addressed to Deputy Commissioner, Hisar has requested that movement of heavy vehicles be restricted on this ROB due to weak portion of the ROB.

(c) Senior Divisional Engineer Railway, Bikaner has telephonically intimated that an estimate for replacement of weak bridge with composite steel girder bridge has been sent to Chief Bridge Engineer Railway, Jaipur *vide* memo No. 634/W/96/Raised/ROB/HSR, dated 1st February, 2011 amounting to Rs. 46.50 Lacs.

(d) Railway Authorities will take about six months time for replacement of unsafe bridge portion of ROB after sanction of the estimate.

श्रीमती सावित्री जिंदल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

Removal of Iron Poles

*536@. **Rao Bahadur Singh** / **Shri Rameshwar Dayal** : Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that iron poles are still in use in Nangal Chaudhary to supply electricity although aforesaid iron poles have already been replaced in whole of the State; if so, the time by which these poles are likely to be replaced; and

(b) whether it is a fact that there is no provision for the supply of domestic electricity to the Dhannis; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply domestic electricity as in the manner, the domestic electricity is supplied to the villages?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

(क) श्रीमान, राज्य के विभिन्न भागों में लोहे के कुछ खम्भे मौजूद हैं तथा इन्हें सीमेंटिड खम्भों के साथ चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है; वर्तमान समय में नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में 304 लोहे के खम्भे हैं जिनको वर्ष 2011-12 के दौरान बदल दिया जायेगा।

@ Put by Rao Bahadur Singh.

(ख) गांवों में दी जाने वाली बिजली आपूर्ति की तरह ढ़ाणियों को घरेलू बिजली आपूर्ति देने का प्रावधान है जो कि दिनांक 3 अगस्त, 2010 को अधिसूचित की गई सरकार की नीति में निहित है।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में बताया है कि पूरे प्रदेश में लोहे के पोल हटाए जायेंगे लेकिन मेरे हल्के में तो आज भी 50 प्रतिशत खम्भे लोहे के ही लगे हुए हैं। इस बारे में मैं कई बार विभाग के एक्शियन और एस०ई० से भी मिला हूं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि आने वाले दो महीने में वे पोल हटा दिए जाएंगे क्या वाकई में दो महीने में हटा दिए जाएंगे या और समय लगेगा? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के नांगल चौधरी में ढ़ाणियों की अपनी पंचायतें हैं लेकिन उनको ढ़ाणियां कहकर डोमैस्टिक पॉवर फीडर के साथ नहीं जोड़ा गया जबकि एक-एक ढ़ाणी में 400-400 और 500-500 वोटें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन ढ़ाणियों को भी डोमैस्टिक पॉवर फीडर से जोड़ने का कष्ट करेंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सप्लीमैंट्री पूछी हैं। पहली सप्लीमैंट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के सारे आयरन पोल नहीं हटे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों के मिलाकर 37 हजार लोहे के पोल मौजूद हैं, 8500 लोहे के खम्भों को सीमेंटिड खम्भों में बदल दिया गया है और हमारे विभागीय सर्वे के मुताबिक आज के दिन जो पोल खराब हैं उनकी संख्या 2700 है। स्पीकर सर, जब वर्ष 2004 में विपक्ष के साथियों की सरकार थी उस समय की पॉलिसी के मुताबिक यह निर्णय लिया गया था कि जो लोहे के पोल हैं उनकी रिपेयर की जाये लेकिन उसके बाद जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जो लोहे के खम्भे क्षतिग्रस्त हैं, खराब हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है उनको तुरन्त बदला जाये। इस निर्णय के मुताबिक यह लोहे के खम्भे बदलने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। जहां तक माननीय सदस्य के क्षेत्र का ताल्लुक है, हमारी जानकारी के मुताबिक लोहे के 344 खम्भे मौजूद हैं जिनमें से 40 खम्भों को बदला गया है अर्थात् रिपेयर किये गये हैं और जो बाकी के खम्भे रह गये हैं उनको हम वर्ष 2011-12 के दौरान बदल देंगे। जहां तक माननीय सदस्य की दूसरी सप्लीमैंट्री ढ़ाणियों में डोमैस्टिक फीडर से बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में है, मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इससे पहले वाली सरकार के समय के दौरान सैग्रीगेशन के माध्यम से डोमैस्टिक और एग्रीकल्चर फीडर्ज दोनों को अलग-अलग किया गया था जिसके मुताबिक एग्रीकल्चर फीडर्ज़ में जो हमारी ढ़ाणियां हैं उनके लिए एक निर्णय लिया गया था कि 11 से लेकर 100 तक की आबादी की जो ढ़ाणियों हैं उनको तो नई नीति में शामिल कर लिया गया है जिसमें 50%-50% के अनुपात में खर्च होगा यानि 50 प्रतिशत खर्च कंज्यूमर देगा और 50 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह घोषणा की है कि 50 प्रतिशत खर्च को हम स्वयं वहन करेंगे जिसके मुताबिक 6800 ढ़ाणियों को उसमें शामिल किया गया है। 1 से लेकर 10 तक की संख्या की आबादी को हम ढाणी की संज्ञा नहीं दे सकते। अगर एक परिवार कहीं अलग बस रहा है तो वहां के लिए एक अलग लाइन देने के लिए अलग पॉलिसी है उसके मुताबिक खर्च देने पर लाइन लगाई जा सकती है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Transport System in Jind City

***574.** **Shri Hari Chand Middha :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the transport system in Jind City is in poor condition; if so, the steps being taken by the Government to solve the transport problem of Jind City?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : नहीं, श्रीमान जी।

Municipal Park in Julana

***351.** **Shri Paraminder Singh Dhull:** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a Municipal Park in Julana City; and

(b) If so, the time by which the above said Park is likely to be developed?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Construction of Road

***469.** **Shri Naseem Ahmed :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Sultanpur to village Umra has been damaged completely; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be reconstructed?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हां, श्रीमान जी। इसका पुनर्निर्माण 31.12.2011 तक पूर्ण किए जाने की उम्मीद है।

Posts of Doctors in General Hospital, Narwana

***613.** **Shri Pirithi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) the number of posts of doctors of all specialities sanctioned for General Hospital, Narwana as on 1st April, 2010;

(b) the number of doctors posted speciality-wise in General Hospital, Narwana as on date; and

(c) the number of vacancies of doctors specialty-wise in the General Hospital, Narwana and whether there is any proposal under consideration of the Government to fill the aforesaid vacancies of doctors togetherwith the time likely to be taken for filling the said vacancies?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह) : श्रीमान जी,

(क) सामान्य अस्पताल नरवाना के लिए अलग से विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं हैं लेकिन एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा 11 चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं।

(ख) वर्तमान में तीन विशेषज्ञ (एक हड्डी रोग शल्य चिकित्सक, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा एक नेत्र शल्य चिकित्सक) लगे हुए हैं।

(ग) चिकित्सकों के 12 पदों में से 8 भरे हुए हैं। तीन चिकित्सक विशेषज्ञ हैं। उम्मीदवारों के चयन उपरान्त कार्यग्रहण करने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

Scheme for Increasing the Forest Area

***345. Shri Ram Pal Majra:** Will the Forest Minister be pleased to state—

(a) whether any efforts are being made to increase the forest area and to maintain greenery in the State; if so, the names of the schemes under which the funds are provided by the Central and State Government; and

(b) The details of amount received under the various schemes during the period from March, 2005 to till date and whether any complaint regarding irregularities in the incurring of the said amount has been received?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) हां, श्रीमान्,

राज्य में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए सरकारी वन भूमियों, संस्थानिक भूमियों, सामुदायिक भूमियों, कृषि भूमियों तथा निजी भूमियों पर निम्न स्कीमों के अन्तर्गत पौधारोपण करवाया जा रहा है :

(i) राजकीय प्लान स्कीमें;

(ii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें ; तथा

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

(iii) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(ख) मार्च 2005 से दिसम्बर 2010 तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त/खर्च कुल राशि 60908.83 लाख रुपये का विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	स्टेट स्कीम (रुपये लाखों में)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (रुपये लाखों में)	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (रुपये लाखों में)	कुल योग (रुपये लाखों में)
मार्च, 2005	487.96	13.61	840.76	1342.33
2005-06	2217.20	158.59	6671.62	9047.41
2006-07	1811.12	115.59	7264.37	9191.08
2007-08	1949.54	100.00	7878.24	9927.78
2008-09	5731.35	40.29	4907.69	11679.33
2009-10	6662.00	161.02	2676.60	9499.62
2010-11 (दिसम्बर 2010 तक)	9374.66	117.17	729.45	10221.28
जोड़	**28233.83**	**706.27**	**31968.73**	**60908.83**

झज्जर, हिसार तथा अम्बाला वन मण्डलों में राशि में खर्च करने में अनियमितता बारे शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

झज्जर वन मण्डल की प्राथमिक जांच रिपोर्टों में पौधारोपण क्षेत्रों में क्षेत्रफल का कम पाया जाना तथा पौधारोपण की सफलता का कम पाया जाना अंकित किया गया था। इसके लिए कुल 40 कर्मचारी (4 वन राजिक अधिकारी, 2 उप वन राजिक, 8 वन दरोगा व 26 वन रक्षक) चार्जशीट किये गये हैं। नियमित जांच करवा ली गई है तथा जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट चैक की जा रही है तथा प्रचलित विभागीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तीन महीने के अन्दर आवश्यक कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी।

हिसार वन मण्डल में जुई तथा मिताथल फीडर पर किये गये पौधारोपण में जांच अधिकारी द्वारा कम सफलता का पाया जाना अंकित किया गया था। इसके लिए 5 कर्मचारी (2 वन राजिक, 2 वन दारोगा व 1 वन रक्षक) आरोपित किये गये हैं। दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पौधारोपण क्षेत्र में पौधारोपण का रखरखाव करवाने के उपरान्त आज पौधारोपण की सफलता प्रतिशत लगभग 75 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला द्वारा क्रियान्वयन में अनियमितता पाये जाने बारे रिपोर्ट मिली थी। ग्रामीण

विकास विभाग द्वारा जिला प्रशासन, अम्बाला के माध्यम से वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला को बजट उपलब्ध करवाया गया था। वन विभाग द्वारा विवादित 22 पौधारोपण क्षेत्रों की चैकिंग करवाई गई जिसमें विभागीय नार्मस से अधिक 15.48 लाख रुपये खर्च किये हुए पाये गये परन्तु यह राशि इस स्कीम के प्रावधानों के तहत उपायुक्त/जिला परिषद्, अम्बाला द्वारा स्वीकृत की गई थी। मामले की चौकसी विभाग के माध्यम से छानबीन करवाई जा रही है।

Bricklining of Drain

*323. **Shri Anil Vij :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to brickline the drain passing through Babyal village, Ambala Cantt. to Mahesh Nagar; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

Unauthorised use of Red-Beacon and Black Films

*389. **Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of challans issued by the Police Department with respect to vehicles using unauthorized red-beacon/red-light during last one year; and

(b) the number of challans issued by the Police Department with respect to vehicles using unauthorized black film during last one year?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) गत एक वर्ष में, 131 अनधिकृत रैड-बेकन/रैड लाईट प्रयोग करने वाले वाहनों के चालन किये गये। इसमें 8 चालान ऐसे हैं जिनमें रैड-बेकन/रैड लाईट प्रयोग के अलावा मोटर वाहन अधिनियम की अन्य उल्लंघनाओं के चालान भी शामिल हैं।

(ख) गत एक वर्ष में, 16318 अनाधिकृत ब्लैक फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों के चालान किये गये।

To Fill up the Posts of Teachers

***506. Shri Ashok Kashyap:** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the number of teachers posted in Primary, Middle, High and Senior Secondary Schools togetherwith the number of posts lying vacant in Indri Constituency alongwith the time by which these posts are likely to be filled up; and

(b) the number of teachers working on deputation in the above said schools together with the time since they have been on deputation alongwith number of schools likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

इन्द्री विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 109 अध्यापकों के पद निम्नानुसार रिक्त है :-

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्तियां
प्राध्यापक	117	116	1
मास्टर	324	264	60
सी०एण्ड०वी० अध्यापक	279	231	48
जे०बी०टी०	489	489	0
कुल	1209	1100	109

यह रिक्तियां शैक्षणिक सत्र 2011-12 में भरे जाने की संभावना है।

इन विद्यालयों में कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। वर्तमान में इन्द्री विधानसभा क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों को स्तरौन्नत करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Reducing the Fee for R.T.I.

90. Shri Ajay Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the prescribed fee from Rs. 50/- to Rs. 10/- for obtaining the information from the Government Department under RTI Act, 2005; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान जी। तथापि, 1 जनवरी, 2010 से सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस की दर ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 10/- रुपये से घटाकर 2/- रुपये कर दी गई है।

Amount Spent on Roads and Buildings

92. **Shri Sher Singh Barshami:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the Districtwise amount spent on Roads and Buildings separately by the PWD (B&R) during the year from 1.4.2005 to 31.1.2011.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी! सड़कों तथा इमारतों पर वर्ष 1.4.2005 से 31.1.2011 के दौरान जिलावार खर्च की गई राशि का विवरण नीचे वर्णित है :-

क्र० सं०	जिलों का नाम	सड़कें (रुपये लाखों में)	भवन (रुपये लाखों में)
1	पंचकूला	16308.86	17342.75
2	यमुनानगर	30702.46	3043.15
3	अम्बाला	38007.89	9094.78
4	कुरुक्षेत्र	34318.82	11002.91
5	करनाल	26024.70	9156.79
6	पानीपत	16475.36	5887.72
7	गुड़गांव	39485.99	11133.48
8	पलवल	25550.66	1872.58
9	फरीदाबाद	13864.53	5896.71
10	भिवानी	40604.4	22491.9
11	महेन्द्रगढ़	16536.31	4687.55
12	जीन्द	21458.26	4372.80
13	कैथल	25489.37	11665.22
14	हिसार	33897.66	6180.58
15	फतेहाबाद	20435.38	3617.60
16	सिरसा	22359.96	6032.32
17	झज्जर	74064.45	10552.25
18	सोनीपत	41039.79	11431.28
19	रिवाड़ी	32520.98	7775.94
20	मेवात	38504.10	4888.64
21	रोहतक	93411.77	29954.34

Wrong Benefit under BPL Scheme

91. **Shri Ajay Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the blockwise details of the number of BPL cases that have been detected to have been wrongly given benefits under the scheme during the period from April, 2005 to till date in District Rohtak; and

(b) full details of the number of criminal cases that have been registered against the aforesaid persons/families so detected; whether there is any proposal under consideration of the Government to take suitable action against such families/persons, if no such action taken so far?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान्,

(क) जिला रोहतक में अप्रैल, 2005 से अब तक जाँच में अपात्र पाए गए ग्रामीण बी०पी०एल० मामलों का खण्डवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

खण्ड	मामलों की संख्या
रोहतक	2
महम	30
लाखन माजरा	7
कलानौर	16
सांपला	शून्य

(ख) सिविल लाईन, रोहतक में श्री दलबीर पुत्र श्री प्रीतु (बी०पी०एल० संख्या 118), निवासी भैनी भैरों, खण्ड महम और श्री चन्द्र पुत्र श्री अत्तर सिंह (बी०पी०एल० संख्या 102), निवासी भैनी भैरों, खण्ड महम के विरुद्ध बी०पी०एल० सूची में अपात्र होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 247, दिनांक 29.4.2010 को दर्ज की गई थी। उपरोक्त वर्णित अपात्र व्यक्तियों के नाम बी०पी०एल० सूची में से अब काटे जा चुके हैं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में सूचना

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि श्री सुनील जाखड़, एम०एल०ए०, पंजाब विधान सभा, श्री कुलवीर सिंह मलिक, भूतपूर्व डिप्टी स्पीकर, हरियाणा विधान सभा, श्री राम कुमार गौतम, भूतपूर्व एम०एल०ए० और श्री बंता राम, भूतपूर्व एम०एल०ए० स्पीकर गैलरी में मौजूद हैं। मैं इन सभी का विधान सभा की कार्यवाही देखने आने के लिए स्वागत करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

डॉ० अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैंने, श्री राम पाल माजरा जी और श्री कृष्ण लाल पंवार जी ने regarding agreement between HSIIDC and Reliance signed in the year 2006 to develop a SEZ in Gurgaon-Jhajjar region एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It has been disallowed. (Interruption)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैंनें, regarding increase of fee for sanction of construction of commercial buildings in the Municipal Corporations, Municipal Council and Municipal Committies in the State एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसका क्या फेट है?

Mr. Speaker : It has been disallowed. (Interruption)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, * * * * * *

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, * * * * * *

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. आप सभी बैठिए! आज मैं आपको भी बुलवाऊंगा। आपको भी आज बजट पर बोलना है। आपकी आज बजट स्पीच है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि बजट के ऊपर चर्चा चलने लग रही है। सर, आपने एक-एक घंटा इंडियन नैशनल लोकदल के नेता को बोलने के लिए दिया था लेकिन दो घंटे तक वे खुद बोले हैं। ये स्वयं भी बजट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आज फाईनैंस मिनिस्टर का बजट के ऊपर रिप्लाई है जिसे ये नहीं सुनना चाहते इस वजह से ये जाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2011-12 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the general discussion on the Budget Estimates for the year 2011-12 will resume. Now, Prof. Sampat Singh Ji will speak.

प्रो० सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे और हाउस से क्षमा चाहता हूं क्योंकि 4 दिन हाउस की इजाजत से मुझे अनुपस्थित रहना पड़ा। अब आपने जो मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

Mr. Speaker : Prof. Sahib. I allow you to speak only 10 minutes. Every Hon'ble Member will be allow to speak 10 minutes.

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, I will try to sum up in ten minutes otherwise, I will take your further permission.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Every Member will not get more than 10 minutes. Wind up in 10 minutes.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बारे में सरकार की और वित्त मंत्री जी की जो सोच रही है, उसके बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। स्पीकर सर, बजट सरकार की नीतियों का, कामों का बहुत बड़ा आईना होता है कि कितना पैसा आप प्लान पर खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा प्रोडक्टिव चीजों पर और कितना पैसा नॉन प्लान पर खर्च कर रहे हैं। कितना आपका एक्सपैंडीचर होगा, कितनी आपकी जी०एस०डी०पी० है, कितना रिवैन्यू रिसीप्ट है और कितना रिवैन्यू एक्सपैंडीचर है क्या वे कंट्रोल में हैं? कितने लोन हैं और कितनी आपकी डैट लायबिलिटी है? इसी प्रकार से कितना आपका कैपिटल एक्सपैंडीचर है तथा कितना आपका फिस्कल एक्सपैंडीचर है? कितना आपका घाटा है तथा कितना आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं? बजट में इन सभी चीजों का निचोड़ आता है, एक कंकल्यूजन आता है। वित्त मंत्री पर बजट बनाते समय बहुत बोझ होता है। स्पीकर सर, मैंने तो खुद 5 बजट बनाये हैं। वे मुझे लिमिटिड रिसोर्सिस में बनाने पड़े थे। आज कैप्टन अजय सिंह को मैं बहुत-बहुत मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने रिसोर्सिज देखते हुए जिस तरह का बजट बनाया है वह हर चीज के हिसाब से अगर हम देखें तो वह अग्रगामी है, आगे बढ़ने वाला है। यह बजट हरियाणा प्रदेश को चहुंमुखी विकास की ओर ले जाने वाला है। जितनी प्रकार की लायबिलिटीज व डेफिसिट वगैरह हैं वे सारी चीजें लिमिट में हैं। उन सबको मैनेज किया गया है तथा सीमा में रखा गया है। इनको सरकार की नीतियों का भी और जो दूसरी घोषणाएं हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है इसीलिए बहुत सूझबूझ से एक सैनिक होने के नाते उन्होंने एक डिसिप्लिंड वे में वैल मैनेज्ड, वैल ऑर्गेनाईज्ड और वैल प्लैंड बजट तैयार किया है। इस बात के लिए मैं इनको बहुत-बहुत मुबारिकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूं। स्पीकर सर, सबसे बड़ी बात प्लान की होती है यानि कि योजनागत खर्च की। योजनागत खर्च सरकार हर साल जितना बढ़ायेगी उतना ही ज्यादा योजनाओं पर खर्च होगा। हालांकि 5 साल मैंने भी योजनाएं पेश की हैं लेकिन मेरी लिमिटेशन्स थी, आमदनी की लिमिटेशन्स थीं। आमदनी एक्साईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट से आती है, आमदनी रेवेन्यू डिपार्टमैंट से आती है। आमदनी टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट से आती है। इसी प्रकार से सरकार की कुछ आमदनी फीस, डिवैल्पमैंट चार्जिज या सरकार की रिसीप्ट वगैरह से आती है तथा कुछ स्टैम्प ड्यूटी से भी आमदनी होती है। आमदनी माइन्ज से भी आती है और इसी तरह के जो अदर अदारे हैं उनसे भी आमदनी आती है लेकिन मेरे पास लिमिटिड रिसोर्स थे। आमदनी को इकट्ठा करना, रिसोर्सिज को जैनरेट करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी। जितने रिसोर्सिज जैनरेट होते थे उनके अन्दर ही मुझे प्लान को बनाना पड़ता था। इसलिए स्पीकर सर, मेरे वक्त में जो प्लानिंग बनती थी उसके लिए बहुत क्रंचिज फाईनैंशियल रहते थे। स्पीकर सर, यही कारण है कि मैं जो प्लानिंग बना पाया था उसमें और आज के समय की प्लानिंग में बहुत बड़ा अन्तर है। मैं तो 1700, 1800, 1900 और 2108 करोड़ की प्लान के बीच में अपने आपको सीमित कर लेता था। मैंने आखिरी में 2108 करोड़ की प्लान बनाई थी। आज सैन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीमों का, पब्लिक सैक्टर अंडर टेकिंग्ज का और लोकल बॉडीज का कुल आमदनी का जो प्लान 22499 करोड़ रुपये का आ रहा है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने आमदनी को बढ़ाने का भी काम किया है और साथ-साथ उसी आमदनी को अपने प्लान में लेकर आये हैं। इसी तरह से नोन प्लान एक्सपैंडीचर है। मैं मानता हूं कि नॉन प्लान एक्सपैंडीचर दो सालों से बढ़ रहा है। यह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि छठे वेतन आयोग का बोझ आया है। प्रेजैंट सरकार पूरे हिन्दुस्तान में अकेली ऐसी गवर्नमैंट है जिसने छठे वेतन आयोग के वेजिज

की कैश पैमेंट की है चाहे वह दो तीन किश्तों में देनी पड़ी है। जो भी डी०ए० गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एनाउंस करती है उसके साथ-साथ ही हरियाणा गवर्नमैंट भी उसको एनाउंस कर देती है इसलिए यह बोझ आया है। मुझे लगता है कि अगले दो सालों में नॉन प्लान एक्सपैंडीचर घटेगा। इसी तरह से राज्य सकल घरेलू उत्पाद की बात है। इससे भी यह देखा जाता है कि आपकी आमदनी कितनी हो रही है। जहां पहले यह आमदनी 9.9 परसैंट थी वहीं इस बार भी प्रोजैक्टेड यह 9 परसैंट है लेकिन मुझे लगता है कि यह आंकड़ा दस परसैंट को क्रॉस कर जाएगा। स्पीकर सर, हैल्दी बात यह है कि पहले सारा प्रैशर प्राईमरी सैक्टर पर होता था, ऐग्रीकल्चर सैक्टर पर होता था लेकिन अब यह प्रैशर इंडस्ट्रियल एक्टीविटीज पर, कामर्शियल एक्टीविटीज पर और सर्विस सैक्टर पर भी आ गया है। पहले अदर एक्टीविटीज खत्म हो गयी थी। जब हरियाणा प्रदेश बना था उस वक्त ऐग्रीकल्चर सैक्टर पर ही सारे का सारा बोझ था। पहले लगभग 56.5 परसैंट एग्रीकल्चर सैक्टर से आमदनी होती थी लेकिन आज यह 14.9 परसैंट पर ले आए हैं। हैल्दी बात यह है कि अब सर्विस सैक्टर भी हमें आमदनी देगा। अब सर्विस सेक्टर से 53.5 परसैंट आमदनी हमें होगी। इससे यह पता लगता है कि स्टेट कहां जा रहा है, अब स्टेट आगे जा रहा है अब लोगों को ज्यादा जौब्स मिल रही हैं, ज्यादा इम्प्लायमैंट मिल रहा है और इन्वैस्टमैंट आने लग रहा है। अब स्टेट का विकास हो रहा है, स्टेट की डिवैल्पमैंट हो रही है। स्पीकर सर, इसी तरह से राजस्व प्राप्तियां हैं अगर राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं तो स्वाभाविक है कि बजट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 2010-11 के मुकाबले 2011-12 में 16 परसैंट की ज्यादा आमदनी राजस्व से बतायी गयी है लेकिन स्पीकर साहब, मुझे थोड़ी सी इस बात की चिंता है कि पिछले साल 2010-11 का जो बजट था वह 2009-10 के मुकाबले में 31.46 परसैंट था और इस बार इसको ये 16.2 परसैंट पर ला रहे हैं। यह जो आदमनी का साधन घटा है इससे मैं चाहूंगा कि आज आमदनी में जो कमी आ रही है वह मंत्री जी पूरी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल रैवेन्यू का ग्रोथ था उसको भी मंत्री जी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये फौजी अफसर रहे हैं। इसी तरह से शेयर और सैंट्रल टैक्सिज में इस बार इनको अच्छा शेयर मिला है। पिछले साल यह 29.7 परसैंट था लेकिन इस बार 20.15 परसैंट ले रहे हैं। लेकिन पिछली बार के मुकाबले में यह कम आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने गुड ओफिस के द्वारा, सारी कैबिनेट अपने गुड ओफिस का प्रयोग करके इसको बढ़ाने का इस्तेमाल करेगी। टैक्स रैवेन्यू का बहुत बड़ा कम्पोनैंट पिछली बार से थोड़ा कम अचीव किया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसको भी मंत्री जी कंट्रोल करेंगे। इसी तरह से नोन टैक्सिज में विशेषकर अर्बन डिवेलपमैंट में जो नोन टैक्सिज आये थे, वह पिछली बार 685 परसैंट बढ़ गये थे परन्तु इस बार 23.6 परसैंट आये हैं। पिछली बार आपने कोई अचीवमैंट ले ली होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। स्टेट के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन जो स्पीड कम रही है इसके बारे में आप जब जवाब देंगे तो इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे क्योंकि there are valid reasons. कोई न कोई वैलेड रीजंज हैं जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं। इसी तरह से डैट लायबिलिटीज के बारे में यहां पर जिक्र किया गया होगा क्योंकि मैंने तो अखबारों में पढ़ा था।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी बता रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है? हमारे विपक्ष के नेता ने भी इस बात के लिए सवाल उठाया था और यह कहा था कि इतना कर्जा लिया है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि खर्चा ज्यादा हुआ है और इसके कोई न कोई कारण हैं। मैं बताना चाहता हूं कि तीन साल से मैल्ट डाउन पूरे वर्ल्ड में रहा, जिसकी वजह से उस गंभीर स्थिति में दुनिया के बड़े-बड़े बैंक बैठ गए लेकिन हरियाणा की आर्थिक स्थिति फिर भी मजबूत रही।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
2005-10 के दौरान हरियाणा की जी०एस०डी०पी० का कम्पाउंड ऐनुअल ग्रोथ रेट कंसटैंट प्राइस के हिसाब से 9.6 प्रतिशत रहा है और इसकी तुलना में यह कम्पाउंड ग्रोथ रेट वर्ष 2004-05 में सिर्फ 8.15 प्रतिशत था। पिछले 6 साल में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कंसटैंट प्राइस 2004-05 के हिसाब से कम्पाउंड ऐनुअल ग्रोथ रेट 7.74 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जबकि 2000 से 2005 की तुलना में यह दर केवल 5.74 प्रतिशत थी। फिसकल डेफीसिट का जहां तक सवाल है। फिसकल डैफीसिट जी०एस०डी०पी० का 3.39 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। अब हमारे प्रयास से यह घटकर 2.61 प्रतिशत तक आ गया है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार डैट लायबिलिटी का 22.4 प्रतिशत तक हो सकता है। हरियाणा के केस में यह 17.38 प्रतिशत है जो कि 13वें वित्त आयोग की अधिकतम सीमा से कम है। विपक्ष के नेता ने कर्ज के मामले में बात कही है। कर्ज का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, 2000-2005 की अवधि में जब इनकी सरकार थी तब 26073 करोड़ का कर्ज लिया गया और 2005 से 2010 तक 18548 करोड़ रुपये कर्ज लिया गया जो कि इनके समय से 7525 करोड़ रुपये कम है। वर्ष 2000 से 2005 तक इनकी सरकार के समय में कर्ज 26 हजार करोड़ और कैपिटल ऐक्सपैंडीचर 8308 करोड़ रुपये था और वर्ष 2005 से 2010 तक कर्ज 18545 करोड़ और कैपिटल ऐक्सपैंडीचर 17725 करोड़ का हुआ है। जैसा संपत सिंह जी ने बताया, जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली तब प्लान साइज 2250 करोड़ का था जो आज बढ़कर 20358 करोड़ का है। संपत सिंह जी ने जो चिंता जाहिर की उसके बारे में एक बात सभी सदस्यों को सोचनी चाहिए। जरूरी बात ये है कि हरियाणा थोड़े से प्रान्तों में एक है जिस पर छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर 11 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ा है। हमने अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसको भी खुशी खुशी सहा है। ये उपलब्धियां हमने सारी दुनिया में 3 साल से चल रहे आर्थिक संकट के बावजूद अचीव की हैं। ये बातें सरकार के आर्थिक प्रबंध की मजबूरी को सीधे-सीधे दर्शाती हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट है। कैग किसी भी स्टेट गवर्नमैंट को आसानी से कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। कैग रिपोर्ट की बैकग्राउंड जो कहती है उसकी समरी में आपको बताना चाहता हूं। इस बारे में कैग ने पहले पैरा में कहा है —

"The Government has done well in the establishing and institutional mechanism of fiscal transparency and accountability."

Sir, this is a commendable comment of the CAG which I think anywhere any Government can get it. (Interruptions)

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Chautala Ji, are you raising a point of order?

श्री औम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो डाटा दिया है वह ठीक नहीं है। वैसे तो यह जवाब वित्त मंत्री को रिप्लाई के वक्त देना चाहिए था। लीडर ऑफ दि हाउस का इसमें दखल ही नहीं था।

Mr. Speaker : Chautala Ji, as the Leader of the House he can. (Interruption) He is Leader of the House and under the rules of the House, he can speak.

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी सरकार के वक्त का आपको बताना चाहूंगा। 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था। वर्ष 2004-05 में 23319 करोड़ का हरियाणा प्रदेश पर कर्ज हुआ था और आज 2004-05 से लेकर 2011-12 तक वह कर्ज 52702 करोड़ रुपये होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कर्ज लेकर ये ब्याज अदा करते हैं। इन्होंने अपने सारे अदायरों को लिखित में भेजा

है। (विघ्न) ये बताएं कि इनके समय में कर्ज कितना बढ़ा है? यहां क्रेडिट लेने के लिए ये बात करते हैं। यह बुद्धि की दरकार है। सदन को गुमराह किया जा रहा है, उसके बारे में मैंने ऐक्सप्लेन किया है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो कोई सदस्य बोल ही नहीं पाएगा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि सदन के नेता को बीच में दखल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है आपकी अनुमति से कहा है। ऐसे मैं भी कह सकता हूं कि नेता विपक्ष को हर बात में बीच में खड़ा होने की क्या जरूरत पड़ी थी।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बोलने से पहले मुझसे परमीशन तो लें।

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, I can give best reply. जहां तक डैट लायब्लिटी की बात है। अभी आदरणीय चौटाला जी ने कहा कि 23319.59 करोड़ रुपये that was 68.4 प्रतिशत है within 5 years debt liability 68.4% बढ़ी थी और within these last five years 2005-06 से लेकर 2009-10 तक I am not talking about for the two years expect for next future years and the current year, I am only comparing five years मैं जब छोड़कर गया था उस समय 23319 करोड़ रुपये छोड़कर गया था और पांच साल के अन्दर मैंने जब कर्जा लेना शुरू किया था, उसका 68.4 प्रतिशत अधिक लिया था। आज हमारे मंत्री जी वर्ष 2009-10 तक जो कर्जा ले चुके हैं वह 39230 करोड़ है जोकि 49 प्रतिशत है जबकि मेरे समय में यह 68.4 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्ष में यह 49 प्रतिशत है जोकि मेरे समय से बहुत ही कम है। These are facts. मैं वर्ष 2004-05 के बीच का बता रहा हूं। I am own my best responsibility. मैं वर्ष 2005-06 से लेकर 2009-10 तक पांच साल का बताना चाह रहा हूं कि 49 प्रतिशत है जबकि उस टाईम 68 प्रतिशत था। जरूरत के हिसाब से कर्जा लेना पड़ता है। अब जो कर्जा लिया गया है that is for productive purpose. मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो लोन रेज किया है वह टोटल लोन किया है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2001 और 2005 में जो मुझे कर्जा लेना पड़ा था वह 26073 करोड़ था और इस सरकार ने इन पांच वर्षों में जो कर्जा लिया है वह 18547 करोड़ रुपये है। उस समय के मुकाबले कहीं कम कर्जा लिया गया है। अभी जो हमारा डैट केपिटल एक्सपैंडीचर है उसके बारे में आप देखें। कैपिटल एक्सपैंडीचर या पूंजीगत खर्चा सही मायने में यह होता है कि जो पूंजी लगा रहे हैं जिसकी हमें आगे असैट्स बनानी हैं वे असैट्स हमारे स्टेट के लिए काम आयें। उन एसैट्स पर खर्चा मैं 8307 करोड़ रुपये खर्च कर पाया था जो इस सरकार ने इन पांच साल में 18995 करोड़ रुपये खर्च किया है इसका मतलब 129 प्रतिशत अधिक किया है जो लोन रेज किया है उसको आप किससे कम्पेयर करोगे। लोन को आप कैपिटल एक्सपैंडीचर के साथ कम्पेयर करोगे। कैपिटल एक्सपैंडीचर 18995 करोड़ रुपये कर रहे हैं और पूंजीगत खर्चा जो असैट्स आप रेज कर रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं वह 18547 करोड़ रुपये है जो लोन ले रहे हैं उससे फालतू आप पूंजी पर खर्च कर रहे हैं इससे बढ़िया और खर्चे का तरीका क्या होगा। बहुत ही अच्छी मैनेजमैंट है पूंजीगत खर्च है उससे लोन कम है इसका मतलब है कि जो लोन ले रहे हैं वह कोई वेस्टेज में नहीं जा रहा है बल्कि पूंजी पर लग रहा है और पूंजी को ही बढ़ाया जा रहा है। स्टेट के असैट्स बढ़ाये जा रहे हैं उस पर खर्च हो रहा है। (विघ्न) स्पीकर सर, कैपिटल एक्सपैंडीचर के बाद जहां तक फिसकल डैफीसिट का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है जो फाईनैंस कमीशन होता है वह स्टेट के लिए लिमिट रखता है। अब 13वें फाईनैंस कमीशन ने जो

[प्रो० सम्पत सिंह]

लिमिट रखी है उससे हमारी लिमिट कहीं कम है। जो हमारा फिसकल डैफीसीट है वह जो स्टेट का सकल घेरलू उत्पाद है उसका 2.61 प्रतिशत है और जो लिमिट है वह 3 प्रतिशत है जो काफी ज्यादा है लेकिन उससे कम ये लाये हैं जो कि मैनेजेब्ल है। Expenditure on infrastructure जो है जैसे रोड्स हैं, ट्रान्सपोर्ट है, पॉवर है, इरीगेशन है उससे ही इन्वैस्टमैंट आती है, उसी से इम्पलायमैंट आती है और उसी से प्रदेश का विकास होता है। स्पीकर सर, वर्ष 2004-05 में मैं जो खर्च कर पाया था वह 816 करोड़ रुपये था। I admit it क्योंकि मेरे पास रिसोर्सिज का क्रंच था। 2011-12 में सरकार जो खर्च कर रही है वह 4367 करोड़ रुपया है यानि 6 गुणा फालतू खर्च किया गया है। इससे बढ़िया बधाई के पात्र कैप्टन साहब और क्या होंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। मैं बजट से हटकर बात नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की अच्छी सोच बता रहा हूं कि सरकार की सोच डिवैल्पमैंट की है। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का जैसा कि मैंने जिक्र किया तो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में इरीगेशन की बात करें तो पानी के बारे में रैजोल्यूशन पास करके हरियाणा में एक हिस्ट्री बन गई है। हालांकि यह हिस्ट्री मेरी अबसैंस में बनी। मैंने अखबारों में इस बारे में पढ़ा था। वह हिस्ट्री अपने आप में यह बन गई कि यहां इस बारे में एकमत नहीं था। यहां एस०वाई०एल० कैनाल और हांसी-बुटाना लिंक नहर पर अलग-अलग आवाज उठती थी। एक प्रोजैक्ट यमुना का था और दूसरा प्रोजैक्ट भाखड़ा साइड का था। दोनों प्रोजैक्ट्स को लेकर यहां खूब अलग-अलग आवाज उठती थी। मैं इस बात के लिए सारे सदन को बधाई देता हूं। मैं हाउस के लीडर को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि वे इस बारे एक रैजोल्यूशन लेकर आए हैं। ऐसा करके उन्होंने एक अच्छी सोच प्रदर्शित की है। उन्होंने ऐसा करके सारे हाउस को इकट्ठा करने का काम किया है। दो रैजोल्यूशन पास करने का इन्होंने काम किया। हांसी-बुटाना लिंक नहर के बारे में या फिर एस०वाई०एल० नहर के बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां थीं जिनको दूर करने का इन्होंने काम किया है। That is a healthy discussion of parliamentary democracy. इससे बढ़िया कोई साइन नहीं हो सकता that was in the State interest. मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक वह सदस्य जिन्होंने यह रैजोल्यूशन पास किया है आइंदा भी वे इसी स्टैंड के ऊपर रहेंगे। कहीं ऐसा न हो कि पोलीटिकल स्टेजिज पर ये अलग आ जाएं, प्रैस में अलग आ जाएं और विधान सभा के प्लेटफार्म पर अलग बात करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा रैजोल्यूशन सभी ने पास किया है ये उसी पर स्टैंड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपने आपको किरण जी की बात से जोड़ता हूं कि इसके बाद अब कोई लड़ाई नहीं रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो वह इलाका देखा है जहां पीने का पानी न मिलने की वजह से लोगों को खाज हो जाती थी। हमारे एरिया में नाहरवा निकलता था। पैर में कीड़े निकल आते थे। हम ऐसे इलाके में पैदा हुए हैं। अभी जब मैं विधायक बना तो मुझे कुछ गांवों में जाने का मौका मिला था। हालांकि फौजी साहब ने वहां खूब सेवा की लेकिन कई बार सभी सेवाएं पूरी नहीं हो पाती और कमियां रह जाती हैं लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। मैं नलवा में गया था वहां लोगों को पानी की कमी की वजह से खाज हो रही थी। हमने स्वच्छ पानी के लिए मुख्यमंत्री महोदय से और सिंचाई मंत्री जी से रिक्वैस्ट की तो उन्होंने उसी वक्त 31 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट नलवा माइनर मंजूर किया जिसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां लोगों को खुजली होती थी, लोगों को नाहरवे निकलते थे आज भी ऐसे एरिया पड़े हुए हैं। उस एरिया में इन्होंने विशेष ध्यान दिया मैं इसके लिए इनका बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह जहां तक इरीगेशन में इन दो बड़े प्रोजैक्ट्स के अलावा जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं, जितनी ब्रांचिज हैं आज उनकी रिमॉडलिंग और स्ट्रैंथनिंग

हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह माइनर्स की बात है तो खालों वगैरह का काम काडा और सिंचाई महकमा कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंचाई की वजह से हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार अच्छी बरसात हुई है। राम राजी हो तो सरकार भी राजी हो जाती है। सरकार राजी होती है तो राम भी राजी हो जाता है। दोनों बातें इस बार हो गई यानि सरकार भी राजी और राम भी राजी हो गया। दोनों काम बढ़िया हो गए। आज जमींदारों की फसल बढ़िया लहलहा रही है। हम सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करें कि इसी तरह मौसम ठीक चलता रहे ताकि फसल भरपूर हो और किसान के खेत-खलियान भरे रहें और उसके घर में अनाज पूरा आए। अध्यक्ष महोदय, रोड्ज की बात करें तो पहली बार हरियाणा सरकार ने रोड मैप बनाया है जोकि एक लम्बी सोच का परिचय देता है। यह आज के लिए नहीं, एक साल के नहीं, दो साल के नहीं, 20 साल के नहीं बल्कि 100 सालों तक के लिए लम्बा प्रोजैक्ट बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हाइवेज को सिक्स लेन्ज, फोर लेन्ज और ऐट लेन्ज बनाने जा रहे हैं जो अपने आप में रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, आर०ओ०बीज० की संख्या आज आदमी गिन नहीं सकता यानि आर०ओ०बीज० की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले पत्थर तो रख दिए जाते थे लेकिन उन पर काम नहीं होते थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि कई जगह हमने पत्थर रखे थे लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने उन कामों को पूरा किया है और उनको ओनर किया है। ऐसे ऐसे जो काम किए गए हैं उनके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। इसी तरह जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है इस क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय कार्य किए गए हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश जैन जी मेरी तरफ देखें। ये बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बना रहे हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please wind up Professor Sahib. You have been allotted 10 minutes. Will you wind up in one minute, please? (Interruption)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीच में थोड़ी सी इंट्रप्शन हो गई थी। No doubt that was a healthy interruption. मैंने भी उस इंट्रप्शन का काफी फायदा उठाया है। उसमें कुछ बातें मुख्यमंत्री जी ने कही और एक-दो बातें चौटाला साहब ने भी कहने का प्रयास किया था। उससे मुझे खुशी हुई है ताकि मैं भी उस पर कुछ बोल सकूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट और रूरल डिवैल्पमैंट सभी पर खर्च किया गया है। जहां तक सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है यह सबसे बड़ा कम्पोनैंट बजट का होता है जिसके अंदर एजुकेशन, पब्लिक हैल्थ, हैल्थ, सोशल वैल्फेयर, स्पोर्ट्स, महिला और बाल विकास, एस०सीज०-बी०सीज० वैल्फेयर तथा ओल्ड ऐज, विडोज, हैंडीकैप्ड आदि सभी प्रकार की पैंशज आती हैं। इनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्ज सरकार ने चलाई हैं और बहुत ज्यादा परसैंटेज बजट में बढ़ाई है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पैंशन बांटने का सवाल है इस बारे में हमारी मंत्री महोदया ने बहुत वंडरफुल प्लान तैयार किया है कि बैंक्स के थ्रू बायो मीट्रिक कार्ड बनाकर पैंशन दी जायेगी। इसके लिए मैं गीता भुक्कल जी का धन्यवाद करता हूं। यह जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग आदमी को आज ही खर्चे की जरूरत है, हो सकता है दो महीने बाद खर्चे की जरूरत हो इसलिए वह अपना पैसा रखना चाहता है। इस तरह से बैंक्स के थ्रू पैंशन मिलेगी तो वे अपने पैसे को सेव भी कर सकते हैं और जरूरत के मुताबिक निकलवा भी सकते हैं। इससे दूसरे झंझट भी मिट जाएंगे कि पंचायत पैसा खा गई, बांटे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एजुकेशन की बात है सिरसा के अंदर हमने नाम मात्र की यूनिवर्सिटी बनाई जरूर थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम एक ग्रेट लीडर के नाम से रख दिया गया था यह ठीक बात थी लेकिन उस पर खर्चा नहीं किया गया था। सोच यहां तक थी कि कितनी बड़ी प्राईवेट संस्था यहां परिवार की बन गई थी तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की यहां क्या जरूरत थी। मैंने कहा जरूरत तो थी

[प्रो० सम्पत सिंह]

वह तो व्यावसायिक टाईप की हो गई और यह जो बनेगी यह आम आदमी के लिए होगी तथा सरकारी खर्च पर बच्चे यहां पढ़कर पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर डिग्रियां लेंगे। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी बढ़िया निकली कि इन्होंने उस यूनिवर्सिटी में इतना पैसा खर्चा है कि उसका आज यूनिवर्सिटी का रूप आया है। इसी तरीके से गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी भी नाम की यूनिवर्सिटी थी। आज अदर यूनिवर्सिटीज को भी जोड़ने का काम सरकार कर रही है। वहां लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी अलग से जोड़ी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से सैंट्रल, डिफेंस, महिला, साईंस एंड टैक्नोलोजी यूनिवर्सिटीज का बहुत बार जिक्र आया लेकिन उनको पूरा करने का काम किसी ने नहीं किया अगर किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा करने का काम किया है। जहां तक मैडीकल कालेजिज की बात है, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन मैडीकल कालेज प्रदेश को दिए हैं। करनाल, मेवात और खानपुर में मैडीकल कालेज दिए गए हैं, इससे बढ़िया स्कीम हैल्थ के लिए और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से शहरी और ग्रामीण विकास की तरफ भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के अंदर क्वालीटेटिव ह्यूमन रिसोर्सिज आयेंगे ताकि प्रदेश के अंदर अच्छी सोच पैदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं लैंड एक्वीजेशन पॉलिसी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि इसको बहुत मिस अंडरस्टूड किया जाता है। लोगों को मालूम नहीं होता और सैक्शन 4 होते ही शोर मचवा देते हैं। उनको कहा जाता है कि सैक्शन 4 हो गया, आपको 21.50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है उसमें दो कम्पोनैंट्स हैं कि 'either minimum rates fixed by the Goverment' वो जैसे मिनिमम रखे हैं ब्याज वगैरा मिलाकर वे 21.60 लाख रुपये बैठते हैं। उसके बाद और एवरेज जो मार्केट रेट निकाला जाता है वह होता है उसमें और शब्द भी है। अपोजीशन के लीडर मेरे नेता रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं इस बारे में मैंने कई बार उनका ब्यान अखबारों में पढ़ा है। ये कहते हैं कि किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए बाजार भाव मिलना चाहिए that is very dangerous or risky, Sir. That is against the farmers, Sir. मैं सदन को इसका कारण बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जब इनकी मिनिस्ट्री में थे उस समय आपने किसानों को उनकी जमीन एक्वायर करने पर बाजार भाव दिए थे।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सब कुछ सदन को बताऊंगा। I will tell you everything. अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि 21.60 लाख रुपये रख दिए that is the minimum rate और जो मार्केट रेट है उसमें से whichever will be on higher side that will be given to the farmers. ये एक तरफ बाजार भाव का जिक्र करते हैं इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे इलाके में कांवड़ गांव है, उसके साथ लगता बांसड़ा और गौरछी गांव हैं। वहां पर सड़क को छोड़कर जो एग्रीकल्चर जमीन है उसका आज बाजार भाव 3 लाख रुपये एकड़ है। इस तरह से according to the Leader of Opposition उनको तीन लाख रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए that is against the farmers. मैं यही कह रहा था कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 21 लाख 60 हजार रुपये मिलेंगे। एक तरफ 3 लाख रुपये और दूसरी तरफ 21 लाख 60 हजार रुपये। This the the best policy.

Mr. Speaker : Prof. Sampat Ji, now please wind up. Your time is over. (Interruption) Your time is over.

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, I am talking the facts. I am on my legs on this issue. (Interruption) Speaker Sir, please allow me to complete my comments on this policy.

Mr. Speaker : I think you have said enough.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरी कांस्टीच्यूएंशी में कांवड़ गांव के अन्दर 3 लाख रुपये मार्केट रेट है। इस प्रकार से विपक्ष के साथियों की सोच के मुताबिक वहां के किसानों को 3 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे जो कि बाज़ार भाव है लेकिन सरकार उनको 21 लाख 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ दे रही है। इसके बाद मय्यड़ और सातरोड़ गांव हैं। सातरोड़ गांव के अन्दर भी जमीन एक्वायर हुई है जिसमें 98-98 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिये हैं क्योंकि उनका मार्केट रेट ज्यादा था। सरकार द्वारा मिनीमम रेट और मार्केट रेट की एवरेज़ निकालकर मुआवजा दिया जाता है। इन दोनों उदाहरणों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि इससे बैस्ट पॉलिसी कोई और नहीं हो सकती क्योंकि किसानों के पास जमीन न रहने के बावजूद भी उन्हें 21 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से एन्युटी भी दी जायेगी जिसमें 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ोत्तरी भी होगी। इसके साथ ही अगर किसी किसान की ढ़ाई एकड़ या 75 प्रतिशत से ज्यादा जमीन एक्वायर होती है तो उस किसान के परिवार में से एक मैम्बर को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि सभी दृष्टिकोणों से अगर देखा जाये तो इससे बैस्ट पॉलिसी और कोई नहीं होगी। विपक्ष के साथी जो सैक्शन चार की नोटिफिकेशन होने पर ही शोर मचा देते हैं जबकि किसान को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता और धरनों पर राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी बैठ जाते हैं। अभी मैं आपको अपने हल्के के गांव खेड़ी साध की बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले वहां पर जो धरना चल रहा था उस बारे में अखबारों में फोटो आई थी। (विघ्न) स्पीकर सर, इस प्रकार के अननैसेसरी कमैंट्स की वजह से बहुत सी जरूरी बातें रह जाती हैं। सर, मैं धरने से संबंधित अखबारों में छपी फोटो की बात कह रहा था। जो उस फोटो में व्यक्ति था उसके सिर के सारे बाल सफेद हैं और वह उसी इलाके का आदमी है, वह बहराट गांव का निवासी है और वह इनेलो की कार्यकारिणी का भी सदस्य है उसको सतीश बहरोटिया बोलते हैं। इसी प्रकार से धर्मपाल मकड़ौली, जो कि कभी मेरा साथी था और वह जिले का प्रधान भी है उसकी भी अखबार में फोटो थी। एक सतीश नांदल था जो कि बोहर गांव का था, जिसने मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ गत विधान सभा चुनाव भी लड़ा था, उसकी भी फोटो थी। अब आप ही बताइये कि वह एजीटेशन किसका था? क्या वह किसान का एजीटेशन था या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजीटेशन था? That was organized by political party. स्पीकर सर, जिनका मैंने नाम अभी बताया है कि इन तीनों की अखबारों में फोटो आई थी। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर हमें कोई लड़ाई लड़नी है तो उसे हमें स्वयं लड़ना चाहिए। यह मैं सरकार की लैंड ऐक्वीजीशन पॉलिसी के बारे में कहना चाहता था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राजनीतिक सोच जो कि वास्तव में विकास की सोच है, के बारे में बताना चाहता हूं। सर, डैमोक्रेसी की यह विशेष खूबसूरती है कि डैमोक्रेसी सैट-अप में कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचकर विकास की नई ऊंचाईयों को छू सकता है। चाहे उसके पास एक एकड़ ज़मीन हो या ज़मीन न भी हो और चाहे वह 300 बीघा ज़मीन का मालिक क्यों न हो लेकिन कुछ लोग जो सामंतवादी सोच रखते हैं उनको यह डैमोक्रेसी पसंद नहीं आती और उनकी सोच कुछ और ही होती है। वे हर काम ज़मीन के कारपेट के

[प्रो० सम्पत सिंह]

नीचे से करना चाहते हैं। कोई आदमी कहता है कि उसके पास 200 बीघा ज़मीन है और कोई कहता है कि उसके पास 300 बीघा ज़मीन है। स्पीकर सर, मेरा हल्का चाहे फतेहाबाद हो या सिरसा, वहां पर पहले यह कॉमन सी बात थी कि ज़मीन की कोई विशेष कीमत नहीं थी। एक बार ऐसे हुआ कि एक आदमी को पता चला कि किसी के पास 300 बीघा ज़मीन है तो वह अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए उसके घर गया। रात को वह सोया और सुबह उठा अपनी पगड़ी बांधी, डोगा हाथ में लिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। इस पर घर के मालिक ने पूछा कि क्या बात चौधरी घर पसंद नहीं आया, लड़का पसंद नहीं आया या जो 300 बीघा ज़मीन है यह कम है तो उसने कहा कि ज़मीन तो है ही नहीं क्योंकि आपकी 100 बीघा ज़मीन तो रात आंधी में उड़ गई जो 200 बीघा जमीन रह गई है उसमें से 100 बीघा कल उड़ जायेगी और बाकी की 100 बीघा परसों उड़ जायेगी इसलिए मेरी लड़की यहां भूखी मरेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय हमारी जमीन की कोई वैल्यु नहीं थी क्योंकि उन ज़मीनों में कोई आमदनी नहीं होती थी। अगर कोई तीन बीघा जमीन का मालिक अपनी पढ़ाई-लिखाई, मेहनत और सोच के दम पर राजनीति में आगे आ जाता है तो तथाकथित सामंतवादियों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार से श्री ओ०पी० जिंदल अपने शुरुआती जीवन में हल चलाया करते थे लेकिन आज हमें गर्व है कि उस आदमी ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन इस पर भी सामंतवादियों की सोच यही होती है कि वह आदमी इतना पैसा कहां से कमा लाया, इसके पास इतना पैसा क्यों आ गया और इस आदमी ने इतनी ज्यादा तरक्की क्यों कर ली? ये सामंतवादी लोग अपने गांव में पांचवीं क्लास से ज्यादा का स्कूल तक नहीं बनने देते थे क्योंकि ये लोग जनता में गुलामी की भावना भरना चाहते थे। इनको ये डर था कि कहीं इन लोगों का विकास न हो जाये, कहीं उनकी सोच का विकास न हो जाये, कहीं उनकी शिक्षा न बढ़ जाये और ये लोग राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में आगे न आ जायें। इस किस्म की उनकी सोच रहती थी। आज मुख्यमंत्री जी ने यह सब खत्म किया है। आज द्वेषता की भावना को खत्म करने में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी ने राजनीति से बदले की भावना को भी समाप्त किया है। पहले तो विधायकों की जमानत ली जाती थी, मेरी और धीरपाल जी की 1999 में जमानत लेकर सरकार बनाई गई थी। उस समय के एम०एल०एज० को विश्वास नहीं था कि अब हम किसके साथ जा रहे हैं। हमारी जमानत ली गई और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ यह श्री कर्ण सिंह दलाल और दूसरे साथी जिन्होंने हमें समर्थन दिया था, वे जान सकते हैं। 200-200 रुपये के केसिज बनाये गये थे। आज कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Prof. Sahib, please wind up fast. (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी हैल्दी डिस्कशन चल रही है। चौधरी सम्पत सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, हमारे विपक्ष के साथियों को क्या पीड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Prof. Sahib, please conclude in 30 second. (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदस्य आपकी तरफ देखेंगे। मैं तो न दायें देखता और न बायें देखता आपकी तरफ देख रहा हूं। मुझे तो आपकी परमिशन की जरूरत है। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

Mr. Speaker : Prof. Sahib, please speak on budget.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जनता की सोच की बात आती है। प्रजातंत्र में कई बार कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं लेकिन उन फैसलों में हमें यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जनता का हित किस बात में है। कई बार कोई मूवमैंट छिड़ जाती है जिस प्रकार अब आरक्षण की मूवमैंट छिड़ी हुई है। कुछ लोगों ने चला रखी है लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से संयम बरता है वह ठीक है। सरकार ने पहले भी संयम बरता है और वह बरतना चाहिए क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी प्रोवोक हो जाते तो स्टेट का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि हमें आरक्षण की वजह से लॉस हो रहा है लेकिन कई बार पब्लिक इंट्रेस्ट में संयम बरतना पड़ता है। इन्होंने संयम भी बरता और अपनी पॉलिसी को क्लीयर भी कर दिया कि ठीक है कि केन्द्रीय सरकार में जाटों को आरक्षण होना चाहिए और लिखकर भी भेज दिया। इसी प्रकार से हमारे सासंद श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी संसद में इस बात को उठाया है लेकिन दूसरी पार्टियां इस बात पर मौन हैं। अन्दर ही अन्दर चाहे वे उकसाने का काम करती होंगी लेकिन कोई भी पार्टी अपना स्टैंड क्लीयर नहीं कर रही कि वे उनका समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं। किस सोच को मानते हो या किस सोच को नहीं मानते हो ? अध्यक्ष महोदय, जब भी सरकार के सामने कोई मांग रखी जाती है, चाहे कोई किसान रखे, चाहे कोई मजदूर रखे और चाहे इम्पलाईज रखे, सरकार की यह सोच रहती है कि यह मामला शांतिमय तरीके से निपट जाये वरना आन्दोलन इसी तरीके से गुजरते रहे हैं खत्म होते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने तो कई बार ऐसे भी हालात रहे हैं कि मुझे औरों की गलती की भी माफी मांगनी पड़ी है। मुझे तो लोगों ने माफी मंत्री डिक्लेयर कर दिया था। मैं आज भी माफी मांगता हूं और मैंने तो पहले भी माफी मांगी थी जिसका मैंने जिक्र किया है लेकिन मुझे दूसरे लोगों की गलतियों की वजह से माफी मांगनी पड़ती थी। कंडेला का टाईम हमारा बहुत भयानक टाईम था, वह हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। इसमें हमारे कई किसान मारे गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या ये बजट पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये सम्पत सिंह जी। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे पॉलिसी पर बोलना है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, it is my humble request to you that two minutes may please be given to Prof. Sahib. चौधरी सम्पत सिंह एक महत्त्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाये, उनको मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब, क्या आपको अभी भी आत्मग्लानि है ?

प्रो० सम्पत सिंह : सर, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत रह रही है। (विघ्न) अभी किसी ने जिक्र कर दिया कि इनको यह विभाग दे दो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सम्पत सिंह इसका भूखा नहीं है। सम्पत सिंह ने ठोकर मारी है क्योंकि मंत्री होते हुए मैंने तीन बार मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री जी ने उस इस्तीफे को फाड़ा है और कहा है कि तू मेरा दायां बाजू है इसलिए मुझे कैबिनेट में रहना पड़ेगा। (विघ्न) Spaker Sir, I am not talking controversial.

Mr. Speaker : Prof. Sampat Singh Ji, I will give you another chance to speak. ऐसा है कि semblance cannot be lost. I will not loose semblance.

प्रो० सम्पत सिंह : सर, मैं आपसे एक मिनट और मांग रहा हूं। Speaker Sir, I want to raise some issues.

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, अब आप बैठिए। आपके ऐसा न करने से हाउस का बैलेंस खराब हो जाएगा। I can't allow you to speak now. The balance of the House is going to be lost. (interruption) Now, Shri Prahlad Singh Gillan Khera will speak.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर, जो बजट हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पेश किया है उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, आज मैं ही नहीं बल्कि सारा हरियाणा इस बात को मानता है कि यह जो बजट पेश किया गया है वह एक आम आदमी का बजट है क्योंकि इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है इसलिए वास्तव में हम इस बजट को डिवैल्पमैंट ओरिन्टेड बजट भी कह सकते हैं। इस बजट के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के मुताबिक जितने भी क्षेत्र हैं चाहे वह शिक्षा हो, बिजली हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, ग्रामीण विकास हो, सिंचाई हो, खेलकूद हो, हर क्षेत्र के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। हम सब जानते हैं कि केवल कहने से कुछ नहीं होता क्योंकि जब तक बजट के अंदर पैसे का प्रावधान न हो तब तक विकास नहीं हो सकता। इस बजट की खासियत यही है कि इसके अंदर हर क्षेत्र के लिए पैसे का पूरा प्रावधान है। सर, उसके नतीजे आपके सामने ही हैं। हरियाणा प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है और कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। सदन के नेता किसान परिवार से हैं और दूसरे सदस्य भी किसान परिवारों से संबंध रखते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी जोकि स्वयं भी एक किसान परिवार से संबंधित हैं, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जिसके ऊपर एक बड़ा दायित्व इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का है, पूरा ध्यान देने का काम किया है। कृषि के क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ा काम इन्होंने इस बजट के अंदर किया है वह यह है कि उन्होंने 1529 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इस बजट को हम आम भाषा में कहें तो इस बजट को हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की संज्ञा दे सकते हैं। सर, जिस तरह से मैं कृषि की बात कर रहा हूं। हमें इस बात की खुशी है कि बासमती चावल का हरियाणा सबसे बड़ा निर्यातक है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष चेयर पर पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश ने 2008-09 के अंदर गेहूं की उत्पादकता में और सरसों की उत्पादकता में पहला स्थान प्राप्त किया है जिसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। धान, चना, जौ, कपास, बाजरा और मक्का की फसलों को राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत छोटे और सीमान्त किसान को दस प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज जरूरत फसलों का विविधीकरण करने की है, हमारी जो मूलतः फसलें हैं उनके स्थान पर दूसरी फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा। अब सरकार द्वारा किसानों को गेहूं व धान के बजाए तिलहनों, दलहनों, फल, सब्जियों तथा नकदी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रमाणित बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने पर किसानों को सहायता दी जा रही है।

16.00 बजे | सूरजमुखी काश्त करने वाले किसानों को 1500/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से व ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 1200/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। किसानों को धान, गेहूं, जो पर 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, बाजरा के प्रमाणित बीजों पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और कपास पर बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत या 600 रुपये प्रति

क्विंटल की दर से व दहलन और तिलहन पर 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाता है ताकि किसान इस तरफ और भी अपने आपको लगाएं। सभी लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि आज पानी की बूंद-बूंद को बचाना किसान और आम आदमी के लिए कितना जरूरी हो गया है। आज हम खेती ग्राउंड वाटर या फ्लडेड वाटर के जरिए से करते हैं, लेकिन हमें इससे हटना पड़ेगा। आज सरकार द्वारा किसानों को स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन के ऊपर 50 प्रतिशत या 7500 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान फव्वारा और ड्रिप इरीगेशन पर आएं। इसी प्रकार से किसान को जिप्सम पर 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है क्योंकि आज हमारी जमीन की सेहत रासायनिक खाद की वजह से खराब हो रही है। दूसरी तरीके से जमीन की सेहत को बचाया जाए। इस ग्रीन मेन्योरिंग के लिए जिप्सम बहुत ही कामयाब है। खरीफ 2008 के दौरान किसानों को 31270 क्विंटल ढेंचे का बीज हमारी सरकार ने मुफ्त उपलब्ध कराया। खरीफ 2009 के दौरान 29162 क्विंटल बीज पर 90 प्रतिशत का अनुदान दिया गया ताकि जमीन की सेहत को बचाया जा सके। कृषक आयोग का गठन किया जो कि आज किसान के हक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज अनाज के भंडारण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के किसानों को धातु की टंकियों की खरीद पर 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है जिससे अब तक 53424 किसान लाभांवित हो चुके हैं। इसके अलावा गैर परम्परागत उर्जा के जो विकल्प स्त्रोत हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक घन मीटर के लिए 4 हजार रुपये व 2 से 4 घन मीटर के लिए बायो गैस प्लांट बनाने पर भी 8 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जिससे अगस्त 2010 तक 54300 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों में किसान क्लबों का गठन किया जा रहा है। किसान को धान, गेहूं व जौ पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारा जो किसान है उसको पुरुस्कार योजना के तहत राज्य जिला व खंड स्तर पर 1 लाख, 25 हजार व 10 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाएं। इम्लीमैंट के बगैर कोई भी किसान आज खेती नहीं कर सकता लेकिन किसान के इंप्लीमैंट्स के रेट काफी ज्यादा हैं। रूटावेटर जो कि एक नयी और किसानों के लिए बहुत ही कामयाब पद्धति है। किसानों को जीरो टन की मशीन की खरीद के लिए 30 हजार और 50 हजार रुपये के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा नये इंप्लीमैंट्स खरीदकर इनसे खेती कर सकें। इसके अलावा प्रदेश में मिट्टी व जल परीक्षण निशुल्क करने के लिए 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। कीटनाशकों पर वैट समाप्त किया गया है। आज किसानों को हस्त चालित पम्प व ट्रैक्टर चालित पम्प स्प्रे पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। पिछली सरकार ने किसानों पर जो मुकदमें बनाए उनको भी खत्म किया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। कंडेला गोली कांड में मारे गए किसानों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का काम किया गया है। यह बहुत ही जरूरी था। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस कांड के बारे में सभी लोग जानते हैं इसलिए मैं इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सभी अनाज मंडियों को ऑन लाइन सूचना प्रणाली से जोड़ने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए पंचकूला, करनाल, गुड़गांव में किसान बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा साठी धान की बिजाई पर पूर्णतया रोक लगा दी है क्योंकि साठी धान से पानी का बहुत ही ज्यादा दोहन होता है, जिसको बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज अगर किसान को न बचाया गया तो हम प्रदेश को नहीं बचा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, किसान की खेती को बचाने के लिए सबसे ज्यादा काम इस सरकार ने किया

[श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा]

है। राज्य के अंदर गिरते जल स्तर को नियमित करने व भूजल के पुनर्भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध हेतु तीन करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इससे आज यह अहसास होता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है और किसान को बचाने के लिए सरकार कितनी प्रयत्नशील है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमें इस बारे में सोचना होगा और यह देखना होगा कि आज जो सरकार है वह किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है। आज किसान बहुत मेहनत करता है और देश का पेट पाल रहा है। मुझे एक बात कहते हुए अफसोस भी हो रहा है। मेरे आदरणीय साथी बैठे हैं। मैं थोड़ी सी इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि तीन दिन पहले हमारे हिन्दुस्तान की राज्यसभा के अन्दर अकाली दल के मैम्बर द्वारा एक सवाल किया गया कि किसानों पर टैक्स लगना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य सदन में मौजूद हैं। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या किसान ऐसी कम्यूनिटी है जिस पर टैक्स लगना चाहिए। अकाली दल के एम०पी० श्री नरेश गुजराल ने राज्यसभा के अन्दर यह सवाल उठाया है। मैं इस बात की निन्दा करता हूं। आज पंजाब विधान सभा में भी जब इस बारे में वाक आऊट किया गया तब अकाली दल के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इसकी जाँच करवायेंगे। मैं हमारे इन साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे साथी हरियाणा में अकाली दल से मिलकर चुनाव लड़ते हैं। क्या ये इस बात में उनके साथ सम्मिलित हैं या उससे गुरेज करते हैं ? ये जवाब देना उनका काम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत सोचने का विषय है। डिप्टी स्पीकर सर, खेती के साथ-साथ मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। आज हरियाणा सरकार की एक सोच है कि पानी को बचाया जाए। इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 को जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पानी की अहमियत के बारे में आज हर आदमी जानता है। पानी के बारे में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। हमारे वित्त मंत्री जी जो सिंचाई मंत्री भी हैं, इन्होंने पानी को बचाने के लिए जिस तरीके की परियोजनाएं आज हरियाणा में दी हैं, जिस तरीके से नये माईनर्ज, नई नहरें बनाई जा रही हैं वह काबिलेतारीफ है।

श्री उपाध्यक्ष : गिल्ला खेड़ा जी, आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं इसलिए आप वाईंड अप कीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो नहीं हुए हैं। टाईम तो बहुत जल्दी चल रहा है फिर भी मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बाकी सारी बातें छोड़ता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज सरकार ने सिंचाई के अलावा भी कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है। रोड्स के बारे में कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि क्या किया है, क्या नहीं किया। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। ये फैक्ट्स हैं कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2005 तक सड़कें बनाने पर टोटल खर्च 1829 करोड़ रुपये हुआ और वर्ष 2005 से आज की तारीख तक हमारी सरकार ने सड़कों के निर्माण पर 7454 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। जिस इलाके से मैं सम्बन्ध रखता हूं उसकी चर्चा करना भी मैं जरूरी समझूंगा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पिछली सरकार ने 95 करोड़ रुपये सड़कों पर खर्च किये थे जबकि इस सरकार ने 221 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, फतेहाबाद में पिछली सरकार ने सड़कों पर 101 करोड़ रुपये खर्च किए थे जबकि इस सरकार ने 211 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जबसे हरियाणा बना तब से लेकर वर्ष 2005 तक हरियाणा में सिर्फ 16 आर०ओ०बी० का निर्माण हुआ लेकिन वर्ष 2005 से लेकर फरवरी 2011 तक 23 आर०ओ०बीज० कम्पलीट हो चुके हैं और 6 आर०ओ०बी० प्रोग्रैस में हैं। इन पर 136 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च किये

जायेंगे। इसके अलावा दस आर०ओ०बीज० अभी भी इस वित्त वर्ष के दौरान पाईपलाईन में हैं। जिन पर लागत 283 करोड़ रुपये आयेगी। डिप्टी स्पीकर सर, आज यह बहुत जरूरी है। जो हमारे पी०डब्ल्यू०डी० विभाग है उसने निर्माण सदन के नाम से एक बिल्डिंग बनाई है। उस बिल्डिंग को श्री जयपाल रेड्डी, केन्द्रीय मंत्री ने नम्बर एक बिल्डिंग घोषित किया है और अभी सात मार्च को Construction Industry Development Council जोकि Planning Commission of India की एक संस्था है, इस बिल्डिंग को विश्वकर्मा अवार्ड, 2011 से नवाजा है और कहा है कि यह बिल्डिंग आज हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बढ़िया बिल्डिंग है। डिप्टी स्पीकर सर, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके का यहां पर काम किया है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज यह हरियाणा सरकार की खेल नीति है और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जी की सोच है जिन्होंने हरियाणा के नौजवानों के अन्दर इतना जोश भर दिया कि कोई भी नौजवान खेल के जरिये भी अपना भविष्य बना सकता है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** जो आज हरियाणा की खेल नीति बनी है उसकी चर्चा आज पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है जिसका नतीजा आपके सामने है।

Mr. Speaker : Wind up please.

श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा : स्पीकर सर, अभी जो हमारे कॉमन वैल्थ और एशियन गेम्ज हुए, उसके अन्दर जो हरियाणा के खिलाड़ियों ने काम किया वह हमारी सरकार की स्पोर्ट्स की सोच का ही नतीजा था। इसमें मैं एक ही प्वायंट जोड़ना चाहूंगा कि खिलाड़ियों की मेहनत का जो इनाम सरकार ने खिलाड़ियों को दिया, वह अलग बात है। सरकार ने दो चीजें और की हैं जोकि हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच को दर्शाती हैं, उनके बारे में भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो कोचिज थे उनको पहली बार सरकार ने एक लाख, दो लाख और तीन लाख रुपये मैडल के हिसाब से दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सारा हरियाणा खेलों के मामले में अपने आपको आगे लेकर आए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाही करें। हरियाणा सरकार ने और मुख्यमंत्री महोदय ने यह एलान कर दिया कि जिस गांव का खिलाड़ी गोल्ड मैडल जीतकर आएगा, उस गांव को 51 लाख रुपये और जिस गांव का खिलाड़ी सिल्वर मैडल जीतकर आएगा उस गांव को 31 लाख रुपये तथा जिस गांव का खिलाड़ी ब्रौंज मैडल जीतकर आएगा उस गांव को 11 लाख रुपये गांव के विकास के लिए दिए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा इनीशिएटिव हमारे खिलाड़ियों के लिए है। वे खिलाड़ी जिन्होंने पार्टीसिपेट तो किया है लेकिन किसी कारण वे हरियाणा के लिए कोई भी मैडल नहीं जीत सके तो उनको भी 2-2 लाख रुपये का नकद इनाम देने का काम सरकार ने किया है। इसका नतीजा बहुत ही अच्छा निकलेगा। इसी इनीशिएटिव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि अभी 2012 में जो हमारे ओलम्पिक आएंगे उसमें हरियाणा के लड़के सरकार द्वारा रखे गए 2 करोड़ रुपये के इनाम को भी हासिल करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे काबिल वित्त मंत्री जी ने बहुत ही शायराना अंदाज में इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने बजट के अंत में भी एक शेयर सुनाया था। मैंने भी 2-4 पंक्तियां लिखी हैं जो नजरे कैप्टन अजय सिंह यादव जी को हैं ।

"बिन पंखों के उड़ने की बात करते हो,
हिम्मत है तो फिर क्यों किसी से डरते हो,

[श्री अनिल विज]

सम्भल के रहना कहीं वे ही न मार दें खंजर,
जिनके दम पर तुम अपना दम भरते हो।
जिनके दम पर तुम अपना दम भरते हो।"

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, सच बात यह है कि जब विज साहब की पार्टी चौटाला साहब के साथ होती थी तब तो ये यह कहा करते थे कि:—

जिसके हाथ का खंजर मेरी तलाश में था,
उसी को दोस्त समझकर लिपट गया हूं मैं।

तो इनको अपनी कोई बात याद आ गई होगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है इसमें महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। महंगाई और भ्रष्टाचार ये दो मुख्य मुद्दे आज लोगों के सामने हैं। इसमें किसान, व्यापारी, कर्मचारी और उद्योगों के लिए कोई भी नई बात नहीं की गई। सही मायनों में माना जाए तो यह जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह वास्तव में धोखा है यह असलियत नहीं है। बजट के बारे में कहा गया कि हमने कर रहित बजट प्रस्तुत किया है। पिछला बजट भी मैंने सुना था तब भी इन्होंने कहा था कि हमने कर रहित बजट प्रस्तुत किया है लेकिन इन दोनों बजटों के बीच में जनता के ऊपर जब चाहे कर लगा दिए गए, वैट बढ़ा दिया गया, रोडवेज के किराए बढ़ा दिए गए। अध्यक्ष महोदय, कमर्शियल चार्जिज लगा दिए गए, बिजली के ऊपर फिक्स चार्जिज लगा दिए गए, हाउस टैक्स लगा दिया गया। हर तरह के चार्जिज जब चाहते हैं ये जनता के ऊपर लगा देते हैं। सरकार कहती है कि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी है और बड़े आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी हमारे पूर्व वित्त मंत्री सम्पत सिंह जी ने भी बताने की कोशिश की है कि सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन वास्तविकता को अगर हम देखें तो पिछले साल सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पाई। अनेको डिपार्टमैंटों के लोग धरने और प्रदर्शन करते रहे हैं। हमारे अपने शहर में एक विभाग के बारे में तो यहां तक समाचार प्रकाशित हुआ कि जब वेतन देना होता है तो लाटरी डाली जाती है कि आधा बजट आया है इसलिए जिसकी पर्ची निकलेगी उसको तनख्वाह दी जाएगी। यह रिकार्ड की बात है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, please you may continue. (Interruption) Please carry on. No interruption.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकार की वित्तीय स्थिति की आज इतनी बुरी हालत है कि हमारे जिन खिलाड़ियों ने कॉमनवैल्थ गेम्ज में इतनी मेहनत करके इतने पदक जीते थे उनके लिए सरकार के पास ईनाम देने के लिए पैसे नहीं थे। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरे साथी विज साहब सीनियर मैंबर हैं और बड़े समझदार भी हैं लेकिन पता नहीं आज इनको क्या हो गया है। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाएं दी हैं वे किसी ने नहीं दी। चाहे पैसे की बात हो, नौकरी की बात हो या दूसरी सुविधाएं देने की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के खिलाड़ियों को दी हैं लेकिन विज साहब सदन के सामने गलत बात कर रहे हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए पैसे नहीं थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन बेचारों को कुछ नहीं पता है। इनको तो बांध कर रखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ये हमें बेचारा कैसे बोल रहे है ? बेचारा तो वह होता है जिसकी शादी नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान) विज साहब, हमारे को बेचारा कैसे कह सकते हैं?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं। खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए सरकार ने हरियाणा अर्बन डिवलैपमैंट अथारिटी से 18 तारीख को 7.02 करोड़ रुपये और 20 दिसम्बर को 7.35 करोड़ रुपये का कर्जा लिया तब जाकर ये खिलाड़ियों का सम्मान कर पाये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सरकार की वित्तीय स्थिति है। चाहे बिजली बोर्ड हो, रोड़वेज का विभाग हो। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। यह इनको मालूम है कि खिलाड़ियों को पैसे दिए गए हैं। जहां तक कर्जे की बात है पहले आप कितनी उम्मीद करते हो। मुख्यमंत्री जी ने नई अनाउंसमैंट की थी और बाकायदा एक लाख लोगों के बीच में खिलाड़ियों का स्वागत किया गया था। पहले एशियाड में गोल्ड मैडल जीतने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपये दिये जाते थे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने नई अनाउंसमैंट करके यह राशि 25 लाख रुपये कर दी। इसी तरह से सिल्वर और ब्रौंज मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों के भी पैसे बढ़ाये गये। यह कोई बुरी बात नहीं है। यह स्टेट की पोलिसी का ही नतीजा है कि इस बार हमारे बहुत से खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और ब्रौंज मैडल जीत कर आये। यदि सरकार कर्जा लेकर उन खिलाड़ियों को सम्मान करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वह कर्जा वापस दे दिया जायेगा। हमारे प्रदेश के सभी विभागों का बजट ऑन लाईन है और सभी विभागों का बजट फिक्स होता है इसलिए जरूरत पड़ने पर पैसे ट्रांसफर करने पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की न्यू अनाउंसमैंट आ गई थी जो कि हैल्थी अनाउंसमैंट थी। That was in favour of sports promotions. इनको यह हजम नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप यह बतायें कि खिलाड़ियों को पैसे दिये कि नहीं दिये ? कर्जा लेकर दिये या कहीं और से दिये, ईनाम के पैसे सरकार की तरफ से दिए गए या नहीं दिए गए ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये तो पूर्व वित्त मंत्री हैं। यह इशू वित्तमंत्री जी का है इसलिए इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देंगे तो वित्त मंत्री जी देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, सम्पत सिंह जी तो प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़े हुए थे। आप यह बतायें कि क्या आपकी नॉलेज में है कि खिलाड़ियों को पैसे दिए गए या नहीं दिए गए ? आप असलियत कहो। Do not mislead the House.

Shri Anil Vij : Sir, I am not misleading the House.

Mr. Speaker : You only tell whether they give the money? From whatever source they gave, they gave or not?

श्री अनिल विज : सर, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं सरकार की गरीब वित्तीय स्थिति की बात कर रहा हूं। आज सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि सरकार ने लोन लेकर खिलाड़ियों को पैसे दिये थे। यह तो वही बात हो गई -

इनके घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप सदन को यह बतायें कि आपने खिलाड़ियों को पैसे दिये हैं या नहीं?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, श्री अनिल विज जी बहुत ही सीनियर लैजिस्लेटर हैं। इस सदन में ये कई बार चुनकर आ चुके हैं इसलिए इनको इस प्रकार की बात करना शोभा नहीं देता। हमने अपने खिलाड़ियों को पैसा दिया है। हमने लोन लेकर खिलाड़ियों को पैसा नहीं दिया है। हमारे पास कंटीजैंसी फण्ड्ज़ होते हैं और इन कंटीजैंसी फण्ड में बकायदा बजट से पैसा दिया जाता है इसलिए इनका यह कहना कि लोन लेकर हमने खिलाड़ियों को पैसा दिया है, ठीक नहीं है। ये इस प्रकार की बेतुकी बातें कहकर हाउस को मिसलीड करते हैं जोकि अच्छी बात नहीं है। अगर ये कोई बात कहना चाहते हैं तो तथ्यों पर आधारित बात ही कहें। हमारे पास जो सप्लीमैंट्री एस्टीमेटस थे उनको हमने पिछली बार पास किया था। हमारा जो कंटीजैंसी फण्ड है उसको हमने 10 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये इसलिए किया है ताकि कोई इस प्रकार की अनफोरचुनेटली बात हो जाए तो इस फण्ड में से पैसा दिया जा सके।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे पास सरकार द्वारा आर०टी०आई० के तहत दी गई सूचना मौजूद है जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह पत्र 27 जनवरी, 2011 का है और इसका नम्बर है HUDA/C.C.F./AC.C.T.T./1/2011/359 इसमें इन्होंने लिखा है कि डायरैक्टर, स्पोर्ट्स एण्ड यूथ अफेयर्स हरियाणा को उन्होंने 7 करोड़ रुपये दिये हैं। सर, इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लोन लिया गया है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अनिल विज जी की बात तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली हो गई। फिर भी मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हुडा भी हरियाणा सरकार का ही एक हिस्सा है। HUDA is a statutory Authoprity created by Haryana Urban Development Authority Act, 1977. It is a Statutory Authority.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * * *

Mr. Speaker : Please delete these words.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यह बात बिल्कुल सही है कि हमने लोन लिया था लेकिन सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स में से ये पैसे रिफण्ड कर दिये गये। फिर माननीय सदस्य ये बात क्यों कह रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) श्री अनिल विज जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने पता नहीं कहां से लोन ले लिया हो। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि हमने हुडा से लोन लिया था और सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स के तहत उसको वापस कर दिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज जी, अब आप ही बता दो कि खिलाड़ियों को पैसे दिये थे या नहीं दिये थे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं यह बात कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि (विघ्न)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : विज जी, कहीं आप अपनी स्पीच को डायरैक्शनलैस तो नहीं बना रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, पहले श्री विज यह कह रहे थे कि हमने पैसा दिया ही नहीं, उसके बाद ये कह रहे थे कि पैसा देने के लिए लोन लिया गया। यह बात सच है कि हमने हुडा से पैसा लिया लेकिन सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स पास करके उस पैसे को हुडा को वापस भी कर दिया। स्पीकर सर, कुल मिलाकर यह इंटरनल एडजस्टमैंट थी।

Mr. Speaker : He is not happy that you gave the money

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, अब आप ही बताइये कि खिलाड़ियों को पैसे दिये गये या नहीं?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने शुरू में ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, अब आप ही बताईये कि पैसे दिये गये या नहीं ?

श्री अनिल विज : इतनी सी बात है सर।

श्री अध्यक्ष : आप इतना ही बताइये कि पैसे दिये गये या नहीं ? (विघ्न) Do not mislead the House.

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने ठीक कहा है और वित्त मंत्री महोदय ने भी सही जवाब दिया है कि हुडा सरकार का ही एक पार्ट है इसलिए हुडा के पास पैसा था जो उन्होंने ले लिया और बाद में सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स के जरिये उसे वापस कर दिया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार की वित्तीय हालत यह है कि सरकारी बोर्डों और निगमों को सरकार की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है कि अगर उनको कर्ज़ लेना है तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होगी। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमने हुडा और एच०एस०आई०आई०डी०सी० को ही इस प्रकार के पत्र लिखे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट में चल रहे हैं और ये अपने दम पर लोन ले सकती हैं। अगर गवर्नमैंट उनके लोन की गारंटी देती है तो उस सूरत में दो परसैंट की लेवी लगती है जिससे सरकार को नुकसान होता है। इसलिए सरकार को नुकसान हो हम ऐसा काम क्यों करें ? ऐसा करके अगर हमने कुछ किया है तो वह सरकार के हित में किया है। ये इस प्रकार की बातें कहकर हाऊस को मिसलीड करते हैं कि आप अपने दम पर लोन लें। जो हमने पत्र लिखा है वह उन पी०एस० यूज० को लिखा है जो प्रॉफिट मेकिंग हैं ताकि दो परसैंट की लेवी न लगे। यही मैं कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Yes Mr. Chautala, you wants to say something.

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्या कृपया यह भी बताएंगे कि ये कारपोरेशंज़ जिस अदायरे से कर्ज लेंगे उनको कितने परसैंट सूद देना पड़ेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो भी मार्किट रेट ऑफ इंट्रस्ट होगा उन्हें भी वहीं देना होगा। स्पीकर सर, मैंने बहुत स्पष्ट सी बात कही है कि जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग पी०एस०यूज० अगर उनके लोन के लिए गवर्नमैंट गारंटी देती है तो दो परसैंट एक्स्ट्रा लेवी देनी पड़ेगी जिससे उनको लोन और भी महंगा पड़ेगा।

Mr. Speaker : Mr. Vij, please conclude.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने शुरू ही किया है। मैं सरकार की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। हरियाणा रोडवेज के सारे डिपो लॉस में चल रहे हैं, इनकी शूगर मिल लॉस में चल रही है, बिजली बोर्ड लॉस में चल रहा है। हमारे यहां अपने संसाधन नहीं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चण्डीगढ़ एयरपोर्ट के लिए 230 करोड़ रुपया लगा दिये जबकि हमारे अपने घर के काम तो पूरे हो नहीं रहे।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, on a point of order. I want to tell my learned friend Shri Vij Sahib that the Chandigarh Airport is owned by the people of Haryana that is why we have given our share of money in that.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट तथा दूसरे दफ्तरों की बात कर रहे हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वैस्ट और करना चाहता हूं कि पंजाब विश्वविद्यालय के लिए भी हमें अपना दखल और बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें हमारा उतना दखल नहीं रहा है जितना पहले था, यह हरियाणा के हित में होगा।

Mr. Speaker : This may be noted, please.

श्री अनिल विज : उस एयरपोर्ट पर पैसा लगाने से क्या फायदा होगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उस एयरपोर्ट से जो प्रोफिट होगा, वह हमें मिलेगा। एयरपोर्ट में जितनी हमारी हिस्सेदारी है उसी अनुपात में हमें आमदनी होगी।

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह ऐयरपोर्ट सिविल एविएशन डिपार्टमैंट का है। यह सारे राष्ट्र की सम्पत्ति है किसी प्रदेश की सम्पत्ति नहीं है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह एयरपोर्ट सिविल एविएशन डिपार्टमैंट पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार का ज्वाइंट वैंचर है। इसमें तीनों की हिस्सेदारी है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This may be noted please.

श्री औम प्रकाश चौटाला : यह मात्र केन्द्र सरकार के सिविल एविएशन विभाग की प्रोपर्टी है किसी और की सम्पत्ति नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अगर इनकी बात सही है तो आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए ताकि जो झूठ बोल रहा हो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सके। (शोर एवं व्यवधान) It is owned by the people of Haryana, it is owned by the people of Punjab and it is owned by the Central Government.

Mr. Speaker : He accepts what the Leader of the House said that it is a joint venture.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं।

Mr. Speaker : You cannot ask but only speak.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हम यह पैसा न लगाते तो हरियाणा के लोगों को क्या नुकसान होता और अगर हमने यह पैसा लगा दिया है तो उससे हरियाणा प्रदेश को क्या फायदा होगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि इसमें हमें हमारे हिस्से का प्रोफिट मिलेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में हमारी हिस्सेदारी है और ये चाहते हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ दें। एयरपोर्ट में हमारी हिस्सेदारी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की वित्तीय स्थिति की चर्चा कर रहा हूं। मेरे से पहले भी चर्चा हो चुकी है कि हमारा कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो प्लान प्रस्तुत किया है वह बहुत प्रोग्रैसिव प्लान है और बहुत बढ़ाकर प्लान प्रस्तुत की है। सर, जो टोटल एस्टीमेटिड बजटरी एक्सपैंडीचर है, वह प्लैंड और नॉन प्लैंड मिलाकर बनाया गया है। उसमें प्लैंड 15336.83 करोड़ रुपये और नॉन प्लैंड 24939.45 करोड़ रुपये है यानि 40276.28 करोड़ का टोटल एक्सपैंडीचर इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगर मैं इसकी पिछले साल के साथ तुलना करूं तो यह पिछले साल 36571.70 करोड़ रुपये था इस तरह से इस बार केवल 3704.58 करोड़ ज्यादा है। जो प्लान इस बार प्रस्तुत की गयी है वह पिछली प्लान से केवल 10.12 परसैंट हायर है लेकिन जो फरवरी ऐंड के मुताबिक रेट ऑफ इंफ्लेशन आया है वह 95 परसैंट है i.e. just equal कि जितना रेट ऑफ इंफलेशन है उसके मुताबिक बढ़ाकर इन्होंने प्लान प्रस्तुत नहीं की।

Mr. Speaker : This is not related issue. Mr. Vij do you understand finance ?

श्री अनिल विज : सर, इसमें 6666 करोड़ रुपये का तो हमारा रिपैमेंट ऑफ लोन ही चले जाना है और 4379.77 यानि 11 हजार 46 करोड़ रुपया तो हमें कर्जों और ब्याज के लिए ही देना पड़ेगा इसलिए सर, आज सरकार की स्थिति बहुत खराब है। सर, सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब होते हुए भी मंत्री जी अपने खर्चे कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप तो विधायकों के लिए पैसा मांग रहे हैं।

श्री अनिल विज : मैंने तो नहीं मांगा है।

श्री अध्यक्ष : अगर वित्तीय स्थिति इतनी ही खराब है तो आपको विधायक निधि कहां से मिलेगी?

श्री अनिल विज : मैंने तो विकास निधि के लिए कहा है।

Mr. Speaker : Mr. Vij, please conclude.

श्री अनिल विज : सर, अभी तो मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया है। सर, खर्चों को कम करने के लिए बजट में कोई भी उपाय नहीं बताये गये हैं कि किस प्रकार हम सरकार के खर्चे कम करेंगे ताकि हमारा प्रदेश प्रगति कर सके। मंत्री जी की कारों के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन किसी प्रकार से भी खर्चों को कम करने का प्रयास नहीं किया गया है। कृषि के लिए 1529 करोड़ रुपये है। सर, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था।, सर, इसरो की जो रिपोर्ट आयी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : ISRO is not concerned with this House. It is not concerned with Lal Bahadur Shastri Ji. लाल बहादुर शास्त्री जी आपके ही नेता नहीं थे वे सारे देश के नेता थे।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऐग्रीकल्चरल लैंड है वह 32 परसैंट कम हो गयी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसमें एक कारण कैमीकल्ज का यूज करना भी हो सकता और समय पर बरसातों का न होना भी एक कारण हो सकता है। कैमीकल्ज ज्यादा डालना भी एक कारण हो सकता है और सबसे बड़ा इसका कारण जो आज हो रहा है वह है उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण होना। आज सारे प्रदेश में चाहे अम्बाला हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे मेवात हो, चाहे खरखौदा हो, चाहे गुड़गांव हो या चाहे मानसेर हो, सब जगहों पर किसान इस चीज के लिए बड़े चिंतित हैं। किसान चाहते हैं कि जो उपजाऊ जमीन है उसका अधिग्रहण न किया जाए। आज हरियाणा सैंट्रल पूल में सबसे ज्यादा गेहूं देता है लेकिन अगर हमारी उपजाऊ जमीन कम होगी तो हमें कटोरा लेकर लाईन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम पहले युनानीमस रैजोल्यूशन लेकर आए थे उसी तरह से वैसा ही युनानीमस रैजोल्यूशन हम इस बात के लिए लेकर आएं कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है उसको किसी भी हालत में अधिगृहीत नहीं किया जाएगा। आज लोगों को डर है कि पता नहीं कौन सी जमीन पर कब सरकार की नजर पड़ जाए और वह उस जमीन को अधिगृहीत कर ले। सर, आज लोग डरे हुए हैं। * * *

श्री अध्यक्ष : इनके यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, सदन इनसे माफी मंगवाएं। इनको क्या पता कि कौन सी माँ क्या कहती है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, I think you have finished your speech. Please conclude. (interruption)

श्री अनिल विज : सर, आप इनको तो बिठाओ।

Mr. Speaker : When you will speak like this then this will happen. Alright, everbody sit-down. Only Parliamentary Affairs Minister will speak.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, ये कौन से लोगों की बात कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, सच बात तो ये है कि इनके दिल का जो दुःख है वह इनको याद आ जाता है। जब इनकी संयुक्त सरकार थी उस समय इनकी और इनके विधायकों की पिटाई हुआ करती थी और इस सदन में तो ऐसे लोग भी रहे हैं जो यह कहा करते थे कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसके डर से रात को सोते-सोते 5-10 आदमी उछलकर बिस्तर से गिर न पड़ें।

डॉ० अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये कौन से बजट का हिस्सा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवाल ये है कि इस तरह के डायलोग प्रवोक करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) We all are agreed that we will not make provocative statements. But we are making provocative statements. (interruptions)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज सदन में माफी मांगे। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : मैं यह कहना चाहता हूं कि --

Mr. Speaker : Vij Sahib, now your time is over. I think you are not speaking on budget. Mr. Vij, we all agreed that we will not indulge in provocative speeches.

श्री अनिल विज : सर, मैं बजट पर ही बोलना चाहता हूं। ये बोलने ही नहीं देते हैं। हर बात पर खड़े हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में कंक्ल्यूड करें। On 4.37 P.M. you have to resume your seat.

श्री अनिल विज : सर, मैं कंक्ल्यूड ही कर रहा हूं। अगर मुझे बीच में इंट्रप्ट नहीं किया जाएगा तो मैं एक मिनट में कंक्ल्यूड कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Don't make a mockery please. This is not good. Sit down please.

श्री अनिल विज : सर, मैं यह कंसर्न शो करना चाह रहा था कि हमें उपजाऊ जमीनों को बचाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि यह जो उपजाऊ जमीनें अधिगृहीत की जा रही हैं, ये इंडस्ट्री बनाने के लिए नहीं की जा रही हैं बल्कि डी०एल०एफ० को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। Sir, I want to quote from one judgement. सर, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सी०डब्ल्यू०पी० 4542 of 2009 है। सर, मैं इसका पेज 30 यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। This is a judgement of Hon'ble Mr. Justice Jasbir Singh and Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kumar Garg. Sir, I want to read the observation of the Court. This is a very serious matter.

Mr. Speaker : No, you probably do not quote anything that said in the body of the Judgement, cannot be read out. Only the operative part can be read out. I am a lawyer. Please read out the operative part only. You cannot quote the judgment here.

श्री अनिल विज : सर, मैं ऑपरेटिव पोर्शन ही पढ़ रहा हूं। * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार से जुड़े हुए कोई मामले यदि अदालत में विचाराधीन हैं और अदालत ने उस पर फैसला दिया है तो क्या उसको यहां बताया नहीं जा सकता?

Mr. Speaker : Let me tell you. चौटाला साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदालत की ऑब्जर्वेशन्स जजमैंट का हिस्सा नहीं हुआ करतीं। उसका ओबीटरडिक्टा अलग है और ऑपरेटिव पोर्शन अलग है। ऑब्जर्वेशन कुछ होती हैं और फैसले कुछ होते हैं।

श्री अनिल विज : सर, मैं ऑपरेटिव पार्ट ही पढ़ रहा हूं।

Mr. Speaker : Let me tell you. You can read out only the operative part of the judgement but not the observation.

Shri Anil Vij : In the aforesaid judgement, this Court also observed that the State and its officers... (Interruption) This is not an isolated case. मेरे पास पूरे केस की लिस्ट है।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए। This is not the part of the judgement. This is not the order. Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * *

Mr. Speaker : Not to be recorded.

श्री अनिल विज : सर, आप चाहें तो इस फैसले की कॉपी ले लीजिए।

Mr. Speaker : Alright, give the copy also. Now, you please resume your seat. Vij ji, I think you have concluded. Nothing more to say.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Vij sahib, is it a Budget speech? Nothing is to be recorded. I invite the next speaker, Shri Dharambir Singh.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I want to clarify one fact. We have clarified it earlier also, when Shri Chautala has raised the issue, not even a single inch of land has been acquired by the State Government for any private party.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनके समय का एक केस है, उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन की है उसमें जो कंक्ल्यूजन दिया है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं -

> "As a matter of fact, the only policy that seems to have been followed. If you show me the face, I will show you the rule."

This is a judgement of Hon'ble Mr. Justice R. M. Lodha in Civil Appeal No. 5440 of 2000. There was a severe indictment of the way you left the land from the process of land acquisition. (interruption)

वॉक आऊट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Mr. Vij, I am not looking towards you.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मवीर सिंह) : स्पीकर सर, कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने जो वर्ष 2011-2012 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, I gave you 28 minutes to speak. You have started making provocative speeches. Let it be noted. You started provoking. Either you resume your seat. Not to be recorded. Mr. Dharambir Singh, you may please start your speech.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप मुझे बजट पर बोलने के लिए और समय नहीं दे रहे इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वॉक आउट करता हूं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अनिल विज सदन से वॉक आऊट कर गये।)

वर्ष 2011-12 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने वर्ष 2011-2012 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, जिस मेहनत से, ईमानदारी से और लगन से कैप्टन साहब ने नेक्सट ईयर के लिए जो बजट बनाया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर सर, बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से और लगन से कैप्टन साहब ने नेक्सट ईयर के लिए बजट बनाया है। उसमें सही नजर आता है कि पिछले छ: सालों में वाकई अब नया युग आया है। हरियाणा प्रदेश एक नवम्बर, 1966 को बना था तब से आज तक इस प्रदेश में बहुत सी सरकारें आईं लेकिन ये छ: साल इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए स्वर्णिम युग कहा जायेगा। इसमें कई खास बातें हैं। स्पीकर सर, इस बजट में सबसे ज्यादा सोशल सैक्टर पर ध्यान दिया गया है। सोशल सैक्टर में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां डायरेक्ट रूप से या इन-डायरेक्ट रूप में कैप्टन साहब ने पैसा देने में मेहनत न की हो। कहीं पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक तरफ प्रदेश का विकास भी बढ़ाया और दूसरी तरफ सोशल सैक्टर पर भी काफी पैसा खर्च किया गया है। 1639 करोड़ रुपये इसमें खर्च करने के लिए प्रयोजन किया गया है। इसमें अगर हम देखें तो 14 लाख से ज्यादा संख्या बुजुर्गों की पैंशन लेने वालों की है, 4 लाख 90 हजार की संख्या विडोज की है और एक लाख 34 हजार से ज्यादा की संख्या हैण्डीकैप्ड लोगों की है यानी ऐसे वर्ग को सीधे तौर पर पैसा उन्हें देने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से अगर हम एजूकेशन के क्षेत्र में देखें तो प्रदेश के अंदर तकरीबन 21 लाख वे गरीब बच्चे हैं जिनको वजीफा दिया जाता है यानि ऐसा बजट दिया है जिसमें कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसी तरह से सोशल सैक्टर में भी बहुत पैसा खर्च किया गया है। आज प्रदेश में तकरीबन 48 लाख परिवार हैं। 48 लाख परिवारों में से 21 लाख परिवारों के बच्चों को एजूकेशन के माध्यम से सीधा पैसा दिया जाता है। 21 लाख के आस पास वे लोग हैं जिन बेचारों को पैसे की जरूरत है चाहे वे हमारे बुजुर्ग हैं, विडोज हैं या हैंडीकैप्ड हैं। वह पैसा भी थोड़ा नहीं है। 500 रुपये से शुरू करके 1000 रुपये तक का पैसा सीधे घर में दिया जाता है। तकरीबन 2800 करोड़ रुपये सालाना केवल सोशल सैक्टर के लिए रखा गया है। हम हैरान हैं जब सम्पत सिंह जी वित्त मंत्री होते थे तब प्लान बजट जैसा कि इन्होंने भी बताया कि मुश्किल से 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होता था। इससे डेढ़ गुणा ज्यादा पैसा सीधे तौर पर सोशल सैक्टर में खर्च करना आज के दिन बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हम डिपार्टमैंटवाइज देखें तो हर सैक्टर के अंदर पैसा रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हम बिजली की बात लें तो 2004-05 तक जितनी बिजली पैदा होती थी उससे कई गुणा ज्यादा बिजली आज की सरकार पैदा करती है। वह सैक्शन जो इस देश का पेट भरता है खासकर किसान यानि आम आदमी उसके लिए भी तकरीबन 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है ताकि उस वर्ग को सीधा फायदा दिया जा सके। मेरे साथी भाई कृष्ण पाल गुर्जर जी कह रहे थे कि आपने जो 1600 करोड़ रुपये माफ किए, वे गलत माफ किए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि गलत माफ किए।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह कह रहे हो कि ठीक किया है?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा है कि आज बकाया 1600 करोड़ की जगह 3200 करोड़ हो गया है। पिछली बार मैंने सवाल भी किया था कि क्या आगे बिजली के बिल माफी के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार लाना चाहती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसान इस प्रदेश का पेट भरता है। सबसे ज्यादा पैदावार करता है। भूखा प्यासा रहकर जनता का पेट भरता है। हमें इस बात की खुशी है कि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री महोदय जी की अच्छी पॉलिसी की वजह से हमारे खाद्यान्न पदार्थ हर साल बढ़े हैं। आज प्रदेश के किसान की हालत यह हो गई है कि आज से 5-6 साल पहले जो किसान कर्जे के लिए भागता था आज वह खुशी से अपनी जिंदगी जीता है। आज किसान और मजदूर की आर्थिक पोजीशन मजबूत हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह कहीं न कहीं सरकार की अच्छी पौलिसी की वजह से ही हुआ है। जहां तक मुझे याद है जब चुनाव होते थे तो ये लोग कहते थे कि न मीटर होगा न रीडर होगा। इनके गलत कारनामों के कारण कंडेला और मंडियाली जैसे कांड हुए। इन 6 सालों के अंदर बिजली के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप खुद देखेंगे कि आज से 6 साल पहले किसान को ट्यूबवैल के बिजली के कनैक्शन के लिए जो फ्लैट रेट देना पड़ता था उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया। किसान आज इस बात से खुश होकर अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। किसान की हर फसल के भाव ठीक बढ़ाए गए। पानी के ठीक यूटीलाइजेशन के लिए कहीं स्प्रिंकलर्स सैट्स और कहीं ड्रिप इरीगेशन के लिए जिस प्रकार से सबसिडी का प्रावधान किया गया है इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इरीगेशन की बात है तो हरियाणा बनने के बाद यह पहली सरकार है जिसने इस बात को सोचा कि हम आखरी छोर तक सबको पानी कैसे दें। अंग्रेजों के समय में यमुना नदी में से डब्ल्यू०जे०सी० बनी थी। उस पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया कि बारिश के दिनों में जब 6 महीने ज्यादा पानी होता है तो उस पानी को बचाकर आगे भी ले जाया जा सकता है। डब्ल्यू०जे०सी० की कैपेसिटी 12000 क्यूसिक मुश्किल से थी। हमारी सरकार ने 155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि 5-6 महीने जो फालतू पानी यमुना का होता है उसको सभी यूज कर सकें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ताजेवाला से करनाल लाईन जो डब्ल्यू०जे०सी० की है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें लिफ्ट कैनाल का एरिया भी पूरी तरह से फीड किया जा सकता है। यह पहली सरकार है जो मेवात में कोटला झील और अरोड़ा जी के कुरुक्षेत्र में बीबीपुर झील पानी के संरक्षण के लिए बना रही है। सर, आपको याद होगा कि हरियाणा विकास पार्टी की सरकार ने बीबीपुर लेक बनाने का प्रावधान किया था और इनके नेताओं ने धरना दिया था कि जमीन ऐक्वायर नहीं होने देंगे। आज की सरकार ने भारतीय किसान यूनियन की डिमांड पर 160 करोड़ रुपये बीबीपुर झील बनाने के लिए दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाढ़ आई उस समय कुरुक्षेत्र में मेरी और हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी की मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई थी। उस समय लोगों ने कहा कि यहां पर झील बनानी बहुत जरूरी है इसलिए वहां पर 5 एकड़ चौड़ी और 10 फिट गहरी झील बनाने के लिए बजट में कैप्टन साहब ने पैसे का प्रावधान किया है। इसके अंदर आप खुद ही देख लें कि यह मांग किसी ने पूरी नहीं की। मेवात के अंदर कोटला में भी झील बनाई जायेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं भी आधा मेवाती हूं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि हमारे पड़ौस में भी हाऊस चल रहा है। वहां अकाली दल, बीजेपी और लगभग लोकदल मिलीजुली सरकार है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग जब बोलते हैं तो ज्यादातर इस तरह की बातों को उजागर कर बैठते हैं। जैसे एयरपोर्ट का जिक्र किया। हमारे

मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच थी कि चण्डीगढ़ में हमारा हिस्सा होना चाहिए उसमें पैसा कितना भी खर्च हो लेकिन ये लोग उसका भी विरोध कर बैठते हैं।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह यादव जी मेरे छोटे भाई हैं। ये बार-बार मेवात में कोटला झील का जिक्र कर रहे हैं। वहां 100 एकड़ में यह झील बनाई जायेगी। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, यह ठीक है कि इन्होंने सपने कई बार लिये होंगे। वहां बैठे-बैठे कई बार सपना लिया था कि कभी यहां कोटला झील बनेगी लेकिन कभी भी एक नया पैसा इन्होंने झील के लिए नहीं रखा।

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No cross questioning, Nothing is to be recorded. (Interruptions)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, कोटला में झील बनाने का जो प्रोजैक्ट है वह 178 एकड़ का ही है। अब तो इलियास जी राजी हो जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Anything said without my permission should not be recorded. (Interruption) Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस हाऊस को मर्यादा में चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बड़शामी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और तजुर्बेकार भी हैं परन्तु आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी सदस्य आपकी अनुमति लिए बिना न बोले।

Mr. Speaker : Anything said without my permission shall not be recorded. It is not the part of the proceedings of the House.

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, हम इस हाऊस में आने से पहले पंचायती राज से जुड़े हुए थे। गांव की पंचायत से हमने अपनी राजनीति शुरू की थी। कभी-कभार जब गांव में कोई मसला हो जाता है तो गांव की पंचायत होती है उसमें एक प्रधान का चुनाव होता है जो कि पंचायत का मुखिया होता है जैसे कि आप इस सदन के स्पीकर हैं। सर, जिस प्रकार की अव्यवस्था यहां पर सदस्यों द्वारा क्रिएट की जाती है ऐसी तो पंचायत में भी देखने को नहीं मिलती। जब हम यहां पर सदस्य को बिना आपकी अनुमति के बार-बार खड़े होते हुए और बोलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दु:ख होता है। पंचायत में कोई भी बोलने से पहले प्रधान की इजाजत लेता है लेकिन आपके द्वारा बार-बार कहने पर भी यहां माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगर पंचायत में कोई बिना परमीशन के बोलता है तो उसका बाकायदा बॉयकाट कर दिया जाता है और उसी समय यह फैसला भी ले लिया जाता है कि आने वाले समय में उसे पंचायत में नहीं बुलाया जायेगा। आज इस सदन में जो सदस्य बिना आपकी अनुमति लिए बार-बार खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं इस के ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए इस समस्या का कोई न कोई कारगर हल अवश्य निकालना पड़ेगा तभी इस सदन की महान गरिमा को बरकरार रखा जा सकेगा क्योंकि मैं समझता हूं कि सदस्य बार-बार आपकी अवहेलना करके सदन की गरिमा को ही गिराते हैं। इसके साथ ही स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिहाज से भी यह बिल्कुल ठीक नहीं है। (विघ्न)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पानी के मामले में प्रबंध किया है वह सराहनीय है। पहले वाली सरकारें इस बारे में सिर्फ घोषणाएं करने तक ही सीमित रही हैं। वर्ष 1995 में जब इस प्रदेश में बाढ़ आई उसके बाद केवल घोषणाएं ही हुई हैं। जितना ड्रेनेज का सिस्टम वर्तमान सरकार के समय में बना है उतना किसी अन्य सरकार के समय में नहीं बना। चाहे घग्गर के नाम से हो अथवा किसी और नाम से हो, केवल मात्र इस सरकार ने ही सत्ता में आने के बाद ड्रेनेज के लिए ज़मीन एक्वायर करके एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब भी हरियाणा में विशेषकर उत्तरी हरियाणा में बाढ़ आयेगी तो पानी ड्रेनेज के माध्यम से घग्गर से होता हुआ बाहर निकल जायेगा। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में भी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त बनाया गया है ताकि बाढ़ की समस्या पर काबू पाया जा सके। सर, पहले लोग अपनी जमीन के अन्दर से पानी का खाला नहीं बनाने देते थे लेकिन इस सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के अस्तित्व में आने के बाद हर किसान यह चाहता है कि उसकी जमीन ड्रेनेज के लिए ऐक्वायर की जाये क्योंकि सरकार की तरफ से उसको बेहतर मुआवजा मिलेगा और नई पॉलिसी के हिसाब से उसे जो ठेके के रूप में मिलेगा उतनी उसे जमीन से आमदनी नहीं होती। इसके साथ-साथ वह अपनी बाकी बची जमीन की सिंचाई करके अतिरिक्त फायदा भी उठायेगा। इसी प्रकार से यहां पर सड़कों का जिक्र किया गया। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने इस बारे में सही ही कहा है कि जिस व्यक्ति ने आज से 6-7 साल पहले हरियाणा की सड़कों की हालत देखी होगी उसे आज की सड़कों की अच्छी हालत देखकर विश्वास नहीं होता होगा क्योंकि सड़कों के मामले में आज बहुत सुधार हो गया है। हर रोज नये-नये प्रोजैक्ट्स के तहत सड़कें बनने लग रही हैं। चाहे आप चण्डीगढ़ से चलकर दिल्ली चले जायें, दिल्ली से जयपुर चले जाये, आगरा, हांसी, हिसार और मेवात के अन्दर चले जायें आप यह पायेंगे कि इस सरकार ने सड़कों को बहुत ही अच्छा बना दिया है।

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. सैनी जी, आप क्यों खड़े हो गये हैं?

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं इसके बाद यह कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सोहना है वहां से चाहे आप गुड़गांव, अलवर (राजस्थान) के लिए निकल जाओ वह बहुत ही अच्छी सड़क है। इसके अतिरिक्त चाहे आप भिवानी से बल्लभगढ़ वाया सोहना निकल जायें, सोहना से पलवल निकल जायें और चाहे नूंह से होडल निकल जायें, ये सभी सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। इन सड़कों पर आंख बंद करके गाड़ी चलाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जब हम गुड़गांव से दिल्ली वाया सोहना निकलते हैं तो रास्ते में बादशाहपुर गांव पड़ता है अगर वहां पर फ्लाईओवर बना दिया जाये तो इस सड़क पर सफर करना और भी अधिक सुगम हो जायेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि सड़कों के बारे में प्रदेश में जो प्लानिंग बनाई गई है वह लाजवाब है। जयपुर, कोटपुतली, नारनौल, भिवानी को जाने वाली सड़कें अच्छी बन गई हैं। इसके साथ-साथ हरियाणा से विशेषकर राजस्थान और पंजाब जाने वाली सभी सड़कें भी बहुत ही अच्छी बन गई हैं। ये 1300-1300 करोड़ रुपये की लागत वाली स्कीम्ज़ हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हर क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

है उसको देखते हुये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात कहना चाहूंगा कि भिवानी में एक बाई-पास जरूर बना दिया जाये ताकि दिल्ली से हांसी-हिसार का रास्ता सीधा हो जाये।

17.00 बजे अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि बगैर कोई नया टैक्स लगाये माननीय कैप्टन साहब ने जो यह बजट हमें दिया है अगर यही रफ्तार हमारी रही तो आने वाले समय में न केवल हम हिन्दुस्तान में नम्बर एक होंगे बल्कि दुनिया में हमारा नाम होगा। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker : I want Finance Minister to reply today, so that we can go on other business tomorrow. Is it possible for you Mr. Finance Minister?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes, Sir. I am ready with reply.

Mr. Speaker : O.K. now, Shri Balbir Pal Shah will speak.

Shri Balbir Pal Shah (Panipat City) : Hon'ble Spaker Sir, after the Governor's address I was asked to speak on Governor's address and today I again beg to pardon that I am not going to speak on Budget (interruptions) After the presentation of budget in the House, now, we are discussing it. My feeling is that Prof. Sampat Singh Ji and other Members of Treasury Benches have explained everything in a very nice manner. Speaker Sir, first of all, I congratulate all my colleagues with thanks. Secondly, I again thank to the Council of Ministers and the Bureaucrats who have made this budget and what was required by the poor people everything has been done and maximum stress has been given on the budget. One thing, I will speak to all the members of the House that action speaks louder than the words. Whatever had been done by Ch. Bupinder Singh Hooda and their colleagues it was never expected and he has really shown a sportsman sprit because he is also a lawyer and sportsman who plays tennis sometimes and he has given stress. He has taken initiative that Haryana's players should get more medals wherever they go. Secondly, one thing I also should say that Ch. Bhupinder Singh Hooda is Hon'ble man, determined and promising one who has brought Haryana to upward instead of downward. Four Yugs are set in our mythology i.e. Sat Yug, Treta Yug, Duaper Yug and Kali Yug. I should say that we are ascending step by step, day by day, movement to movement and this process is continuing. As far as Hooda Sahib is concerned, in Iron Age, he is the iron man of Haryana, what he speaks he is strict to that and I have seen his working and working of all the Chief Ministers. Before Ch. Bhupinder Singh Hooda came as a Chief Minister there are certain demands which are not only related to Panipat but also related to Haryana. Last time, I am really thankful to you that you promise to give me some time to complete the demands of Panipat. Panipat was declared in 1991-96 as a ecological town "Pardushan Rahit Shahar" but no work had been done by any Government previously but now we are sure and works says action speaks. He will be able to take up Haryana and we will step up. We are ascending not descending. There was a stone age also. There were so many ages. Golden age has gone, Treta has gone, Duapar age has gone and Iron Age has come. I defer to those people who say that the previous ages are better than this age. I think this era is the golden era and we are going ahead platinum era and diamond era. Project for solid waste and cleanliness should be started in my town because the Hon'ble Speaker has already mentioned the name of Panipat town that it is the dirtiest town.

[श्री बलबीर पाल शाह]
Though people of Panipat earn lot of money in the form of foreign currency but reward is not given properly, share is not given properly and last time I requested the Hon'ble Chief Minister to allot extra funds to Panipat so that at least we may call our city the clean city.

Chandigarh is called as a city beautiful. Panipat is doorway to Delhi and from Delhi all the three-wheelers have discarded by the Government. These are operating now in Panipat and creating certain problems there. I will request the Council of Ministers, Chief Minister to interfere and introduce CNG buses and traveling vehicles. Water level has gone down due to over drawing of water, some of the water by MITC Tube wells. Now the Delhi Parallel Canal has been lined by cement so that there should be no leaching of water and Water level is going down. When we talk of dye houses, dye houses have mushroom growth in Panipat. Only 50 dye houses could have been registered and still 200 dye houses required attention so that they do not pollute the drinking water. There is the requirement of Government Engineering College and Textile College. Government should be requested that a Government school be opened in Khatik Basti in urban area because people of that area are very poor and they cannot bear the strain. In Panipat there is no Government Senior Secondary School for boys. A Senior Secondary School for boys should be opened in the city. There is no Government College in Panipat and I would request to the Government a Co-Education College up to Post Graduation should be opened. Next thing is very important which is concerned to the health. Our Hospital is not up to the mark, as far as Panipat city is concerned, as far as importance of Panipat is concerned. There are no new instruments in Hospital and sometimes there is shortage of Doctors. But still I am thankful to the Chief Minister that four dispensaries were given to the Panipat and in different areas they are working for the poor.

Mr. Speaker: Hon'ble Member, rest of the demands you may give in writing please.

Shri Balbir Pal Shah: Speaker Sir, I will take only 5-7 minutes, I am not going to explain everything now. These dispensaries opened in Tehsil Camp, Krishanpura, Gurunanakpura & Chandani Bagh in Panipat City. Recently revised commercial charges for Municipal Corporation from 1400 per square yard to 6000 & 7500 per square yard has been imposed. The old policy should be adopted and to rationalize it should be rolled back. To curb unauthorized construction in urban areas all the power should be with the corporation and interference of town and country planning Department should be stopped in Municipal limit. Pity of the situation is that Panipat is an industrial area where most of the labour are living there. I can say that labour is more than the residents of Panipat so mushroom growth of colonies should be checked. There should not be any fresh growth as it is happening in the area between Western Yamuna Canal and Delhi Parallel Canal.

Mr. Speaker: Thank you, Shah Ji.

Shri Balbir Pal Shah: Speaker Sir, All the old electric wire should be replaced there. At least one person from Balmiki family should be given a Government job,

permanent job because they deserve it. I know that my worthy Chief Minister is very humble and he will take it on priority.

Mr. Speaker: Thank you.

Shri Balbir Pal Shah: Speaker Sir, only two things I want to say. Special project for houses should be started for urban poor Below Poverty Line, SCs, BCs & homeless. Then one Rehari market, Fari market may be provided. Transport Minister knows that how much reharies stand with the walls of the Bus stand and create pollution and everything. They should be given small size of booth for rehabilitation. Transport Department will earn something and the people will able to earn something for their family. In 2005 Ch. Bhupinder Singh Hooda Ji came to Panipat and one demand was raised by the people of Panipat with regard to open Sabji Mandi under the scheme No. 24 of the improvement trust. Speaker Sir, the people wanted to change residential area to commercial area and that was also accepted by the Chief Minister. Now people are getting benefit but few of them are not getting benefit. Speaker Sir, I want to say that some plots have been resumed by the Government but their plots should be restored and whatever the charges are there, the same may be charged from them.

Mr. Speaker: You give it in writing.

Shri Balbir Pal Shah: O.K. I will give it in writing to the Hon'ble Chief Minister.

Mr. Speaker: Before I invite Shri Ashok Kumar Arora to speak up, I have received a chart of demands from the Hon'ble Member Shri D.K. Bansal which I am forwarding to the Hon'ble Finance Minister for his consideration.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया है। जब देश में महंगाई बढ़ रही है, जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ऐसे समय में प्रदेश के लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं परन्तु इस बजट में न तो महंगाई रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है और न ही भ्रष्टाचार रोकने की कोई बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए और प्रजातंत्र लाने के लिए लड़ाई हो रही है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सामंतशाह युग बहुत माड़ा युग है जैसा कि सम्पत सिंह जी ने भी कहा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा हिन्दुस्तान देश है। यहां पर लोगों को इस प्रदेश के प्रजातंत्र से बहुत उम्मीदें हैं परंतु अफसोस के साथ कहूंगा कि आज लोगों का विश्वास देश के राजनेताओं से उठता जा रहा है। एक समय था जब स्वर्गीय महात्मा गांधी जैसे, स्वर्गीय लाल बहादुर जैसे, स्वर्गीय लोक नायक जय प्रकाश जैसे या फिर स्वर्गीय देवीलाल जैसे लोग देश के नेता हुआ करते थे और लोग उनकी बातों पर विश्वास करते थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 1965 में जब हम छोटे-छोटे थे उस समय देश की लड़ाई हुई थी। उस समय देश के प्रधनमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने देश के लोगों को कहा था कि देश में अन्न और धन की कमी है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि उनकी बातों पर विश्वास करते हुए जहां हमारे बुजुर्गों ने एक दिन का व्रत रखा था वहीं हमारी माताओं और बहनों ने अपने जेवर तक भी दे दिए थे ताकि देश की सीमाओं की रक्षा की जा सके। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कई तरह के घोटाले हुए। कहीं कॉमनवैल्थ गेम्ज घोटाला, कहीं इसरो घोटाला और कहीं आदर्श घोटाला हो गया। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, यहां हरियाणा का बजट पेश किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) ये कहां-कहां के घोटालों का जिक्र करने लगे। अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप इनको स्पीकर होने के नाते ये ऐडवाइस तो कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी सुने। मैं सबके लिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि आज लोगों का विश्वास जीतने की जरूरत है।

Mr. Speaker : Restrict yourself to the speech on budget.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कहीं 2 जी० स्पैक्ट्रम घोटाला हो रहा है और कहीं हरियाणा प्रदेश में भूमि घोटाला हो रहा है। आज पोजीशन यह हो गई है कि पहले नेताओं की बात पर लोग विश्वास किया करते थे लेकिन आज कोई नेता जब लाल बत्ती वाली गाड़ी पर जाता है तो लोग कहते हैं कि ******** जा रहे हैं। यह हालत है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं। भूमि घोटाले के बारे में पहले ये बताएं कि कौन-सा भूमि घोटाला है। मैं पहले ही इस बारे में कह चुका हूं लेकिन फिर ये बार-बार लोगों को गुमराह करने की बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीनियर नेता हैं और पार्टी के प्रधान हैं इनको इस प्रकार की बातें कहना शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) कोई बात कहो तो विद एथैंटिसिटी कहो।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद नहीं कहता। आप मेरी बात सुनते नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं कहते हैं दूसरों को कहने दो क्या फर्क पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं कहते तो बात खत्म हुई। हमें दूसरों से मतलब ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा। He is not leveling any allegation. बात खत्म हुई।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह अशोभनीय बात है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इन्होंने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द यूज किए हैं वे अशोभनीय हैं इसलिए इनको रिकार्ड न करवाया जाए और कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, वे शब्द रिकार्ड न किए जाएं। वैसे इन्होंने खुद कहा है कि मैं नहीं कह रहा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज पोजीशन ऐसी हो गई है कि माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट को एक बार नहीं बल्कि दो-दो, तीन-तीन बार यह कहना पड़ा कि यह सरकार लोगों की नहीं बल्कि बिल्डर के एजैंट के रूप में काम कर रही है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर हाउस को मिसलीड किया जा रहा है। माननीय अरोड़ा जी सुनना चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ बातें जो कही गई थीं वे आदरणीय चौटाला जी की सरकार द्वारा जो जमीन छोड़ी गई है उसके बारे में कही गई थीं। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट है। ये कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) यह जजमैंट अभी ताजा ही आई है। यह जस्टिस आर०एम० लोधा का निर्णय है। 11 फरवरी, 2010 की जजमैंट है। यह बहुत पुराना निर्णय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये अगर सुनना नहीं चाहते तो ठीक है। मैं सबकी बात कह रहा हूं। ये नहीं सुनना चाहते तो ठीक है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Actually, Shri Ashok Kumar Arora is becoming a statesman.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये नहीं सुनना चाहते तो इनकी मर्जी। ये नहीं ठीक होना चाहते हैं ये भी इनकी मर्जी है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर ये स्टेट्समैन बन जायें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि ये हमारे मित्र हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं महंगाई का जिक्र कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार यह दोहराया है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन इसके लिए प्रदेश की सरकारें भी जिम्मेवार हैं। ऐसे समय में प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि प्रदेश के वित्त मंत्री बजट में टैक्सिज को कम करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों पर महंगाई की मार कम पड़े। अध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बजट में वित्तमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति की भी बातें हुई हैं। सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए कि आपके समय में इतना लोन लिया गया और हमारे समय में इतना लोन लिया गया। अध्यक्ष महोदय, आज जो बजट अनुमान में दिखाया है कि हरियाणा प्रदेश का ऋण 52702 करोड़ रुपये हो जायेगा। वित्त मंत्री जी ने और प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने कहा कि हमारे समय में 65 प्रतिशत ऋण लिया गया और इन्होंने उससे कम लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय हमारी सरकार थी उस समय पांच साल के अंदर टोटल 20198 करोड़ रुपये ऋण लिया गया जिसमें से 16000 करोड़ रुपये वापस भी किया गया था। वित्तमंत्री जी अपने जवाब में यह भी बता दें कि इन्होंने टोटल कितना लोन लिया और उसमें से कितना वापस किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं आज के दिन प्रदेश के ऊपर इतना लोन है कि हमारे प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 22 हजार रुपये ऋण के नीचे दबा हुआ है इसको कम करना चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं विकास पर आना चाहूंगा कि प्रदेश के विकास के बारे में सरकार बहुत कुछ कह रही है लेकिन वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें इन्होंने स्वयं माना है कि बजट का 48 प्रतिशत सैलरी और पैंशन पर खर्च हो रहा है, लगभग 23.50 प्रतिशत रीपेमैंट ऑफ लोन का जो ब्याज है उस पर जा रहा है यानि लगभग बजट का 72 प्रतिशत हिस्सा तो सैलरी, पैंशन और रीपेमैंट आफ लोन के ब्याज में ही चला जायेगा तो केवल मात्र 28 प्रतिशत में प्रदेश का विकास कहां से हो पायेगा ? इसके अतिरिक्त 28 प्रतिशत में से भी 25-26 प्रतिशत कमीशन में चला जायेगा तो प्रदेश का विकास कहां से हो पायेगा ? इस तरह से वित्त मंत्री जी किस प्रकार से प्रदेश का विकास करना चाहते हैं यह भी अपने जवाब में बतायें।

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के बारे में मुख्यमंत्री जी ने, विपक्ष के नेता और दूसरे साथियों ने बहुत चर्चा की है। सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए कि हमारे समय में कम रेट दिया जाता था और अब ज्यादा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं कि पूरे देश में और प्रदेश में जमीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। रेट बढ़ने के साथ-साथ यह स्वाभाविक है कि जिस भी किसान की जमीन जाती है उसके बराबर में ज्यादा रेट मिलता है तो उसके अंदर जो डर छिपा हुआ है यह ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में इण्डस्ट्री लगे लेकिन इसके लिए ठोस नीति बनानी बहुत जरूरी है। खाली जमीन देने से इण्डस्ट्रीज नहीं आयेंगी। वित्तमंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि अब तक कितने आई०एम०टी० काटे और कितनी इण्डस्ट्रीज आई ? यदि सरकार वाकई में प्रदेश में इण्डस्ट्री लाना चाहती है तो इण्डस्ट्रीज को वैट में और बिजली में छूट देनी चाहिए। साहा के इण्डस्ट्रीयल टाउन की बात हुई, वहां से 25-30 कि०मी० की दूरी पर काला अम्ब हिमाचल में है। काला अम्ब जो हिमाचल का एरिया है और साहा के साथ लगता है वहां उन्होंने टैक्सिज में रियायत दे दी जिससे इण्डस्ट्रियल पार्क, साहा की सारी इण्डस्ट्री वहां पर चली गई। पानीपत का भी यहां जिक्र किया गया। पानीपत का जो कम्बल उद्योग था वह ज्यादातर उत्तराखण्ड में चला गया है क्योंकि उन्होंने टैक्सिज में रियायत दी है। मेरा यह कहना है कि किसी को जमीन ऐक्वायर करके सस्ते प्लॉट देने से इण्डस्ट्री यहां पर नहीं आयेगी बल्कि इण्डस्ट्री आयेगी इण्डस्ट्री का माहौल पैदा करने से। आज हरियाणा प्रदेश में शहरों के साथ जो एरिया लगते हैं वहां के किसानों में यह प्रवृत्ति है कि जो किसान अपनी जमीन नहीं भी बेचना चाहते थे वे भी अपनी जमीन बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी जमीन को भी सरकार द्वारा ऐक्वायर न कर लिया जाये। यह डर केवल हरियाणा प्रदेश के लोगों में ही नहीं है बल्कि इस प्रकार का डर हरियाणा सरकार के मंत्रियों में भी है तभी तो उन्होंने अपनी जमीन 2.5-2.5 करोड़ रुपये में अन-अप्रूव्ड कालोनियों के लिए बेचने का काम किया है। आज इस प्रकार से अन-अप्रूव्ड कालोनियां काटी जा रही हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा ऐक्वायर करने से पहले उनकी जमीन बिक जाये।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, on a point of order. सर, आदरणीय अरोड़ा जी सीनियर मैम्बर हैं और ये स्पीकर भी रहे हैं। उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वह रिकार्ड पर आ गया है कि हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये में अन-अप्रूवड कालोनी को अपनी जमीन बेच दी है। यह बात असत्य और सरासर गलत है। अगर उनके पास इस बारे में कोई तथ्य हैं तो वे उन्हें सदन के पटल पर रखें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम इस बात की इंक्वायरी करवा लेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सदन की एक कमेटी का गठन कर दें जो यह पता कर ले कि जमीन बिकी है या नहीं और उसके बाद आगे वह कितने रुपये प्रति गज के हिसाब से बिकी है। यह मैं चैलेंज करता हूं कि अगर जमीन नहीं बिकी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर बिकी होगी तो फिर ये इस्तीफा दे दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अरोड़ा जी एक बार फिर असत्य बोल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहे वह मंत्री हो, अपनी जमीन बेचने का अधिकार है परन्तु अनअथोराईज्ड कालोनी के लिए हरियाणा सरकार के मंत्री ने अपनी जमीन बेची है यह इल्जाम गलत है।

(शोर एवं व्यवधान) मेरी जमीन है मैं किसी को भी बेचूं।

Mr. Speaker : This is unsubstantiated allegation.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, it is completely unsubstantiated, it is misleading, it is defamatory. Mr. Arora is trying to unnecessary level allegation on a Member of this House.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं तो यह कहता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिए हाऊस की एक कमेटी बनाई जाये।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this has to be expunged. Sir, the allegation of the Hon'ble Member has to be expunged. It is completely untrue. सर, मेरी जमीन है उसे मैं किसी को भी बेचूं।

Mr. Speaker : Unsubstantiated allegation can not be entertained.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, यह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जमीन बेची गई है।

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी कि समूचा सदन यह चाहता है कि एक कमेटी मुकर्रर की जाये और सारी बेकायदगियों की इंक्वायरी हो जाये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 01 नवम्बर, 1966 जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक जिस किसी ने भी जितनी भी बेकायदगियां की हैं उसके लिए एक कमेटी मुकर्रर हो जाये ताकि सबको सच्चाई का पता चल पाये। यह आज ही तय हो जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, बेकायदगियों के ऊपर तो सी०बी०आई० की जांच चल रही है इसलिए हाऊस की कमेटी बनाने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, जो आप सजैस्ट कर रहे हैं अगर इस प्रकार की कमेटी बने तो उसके मैम्बर कौन-कौन होंगे ?

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पार्लियामैंट में जे०पी०सी० का गठन हुआ उसी प्रकार से इस हाऊस में जिस पार्टी के जितने मैम्बर हैं उस रेश्यो से इस कमेटी में भी मैम्बर बना दिये जायें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बेकायदगियों की तो सी०बी०आई० द्वारा जांच चलने लग रही है।

श्री अध्यक्ष : किसके खिलाफ जांच चल रही है ?

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब ये if और but लगायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, अगर इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने अपनी जमीन बेच दी है तो यह कहना कि वह अनअथोराईज्ड कालोनी बनाने के लिए बेची गई है यह गलत है और इस पर हमें ऐतराज है। स्पीकर सर, इन्होंने बेकायदगियां की होंगी इसलिए ये अब भागना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, सीधी बात यह है कि अगर इस माननीय सदन के किसी सदस्य ने अपनी जमीन बेची है तो यह कहना कि उसको अनअथोराईज्ड कालोनी के लिए बेचा है, बिल्कुल गलत है।

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात तो हो गई है कि जितनी बेकायदगियां हुई हैं उनकी जांच हो जाये अब if और but की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक कमेटी का गठन करें जिस प्रकार से पार्लियामैंट में जे०पी०सी० का गठन हुआ है और किसी भी पार्टी के सदस्यों की सदन में संख्या के हिसाब से उसमें मैम्बर बनायें यह हम आपको अधिकार देते हैं। क्या इससे बढ़िया कोई मौका आयेगा ? आप इस बारे में एक कमेटी का गठन करें। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) : स्पीकर सर, अगर इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई भी जाती है तो भिवानी के बारे में भी आप जरूर जांच करवा लेना।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, आदरणीय चौटाला जी की एक आदत है कि जब भी ये कहीं फंस जाते हैं तो फिर उस मामले को एक कमेटी के माध्यम से डी-रेल कर देंगे क्योंकि ये जानते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो चार्ज-शीट फाईल करने वाला है। यह चार्ज-शीट फाईल न हो जाये इसलिए पहले ये एक कमेटी बनवा देना चाहते हैं ताकि वे इस मामले को डी-रेल करवा लें।

श्री औम प्रकाश चौटाला : यह मामला तो अदालत के विचाराधीन है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, from where the allegation was started ? The allegation was that a Minister has cut un-authorised colony. That was the allegation. I have said no Minister has cut any un-authorised colony. If a Minister owned agriculture land, if a Minister owned urban land, he can sell it at a fair price. (Interruption) Does a Minister have no right to sell his land ? Every member of this House has a right to sell his land. (Interruption)

Mr. Speaker : I have seen people growing from rags to riches. But I do not want to name them. I have seen everybody. So, any un-substantiated allegation not to be recorded.

श्री औम प्रकाश चौटाला : सवाल तो इस कमेटी के गठन का है।

श्री अध्यक्ष : मुझे सबका पता है। (शोर एवं व्यवधान) जो चौटाला साहब सुना रहे हैं वह मेरा अनुभव है मैं क्या कहूंगा।

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फैसला तो आपको करना है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूं कि मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में प्रदेश की कालोनियों को लाना चाहता हूं। हमारे शहर में इस समय अनअप्रूव्ड कालोनियां लोगों द्वारा काटी जा रही हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने एक मेला एरिया चिह्नित किया है। कुछ तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने जमीन ऐक्वायर की हुई है लेकिन कुछ जमीन को रिजर्व छोड़ा हुआ था कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, उस मेला एरिया में भी एक कालोनी कट रही है तथा नगर परिषद, कुरुक्षेत्र उनके नक्शे पास कर रही है। उसकी इन्क्वायरी हुई, इन्क्वायरी में प्रूव भी हो गया लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर रोक लगे तथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से खेती

की बात सभी कर रहे हैं। हम भी यह चाहते हैं कि खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। यहां एक साथी ने 5500 रुपये पॉपूलर के रेट की बात भी की। अध्यक्ष महोदय, किसान को ज्यादा रेट मिलना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राईस से भी कम रेट पर किसान की फसल खरीदी जायेगी तो किसान को कैसे अच्छा रेट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा प्रदेश में जीरी की खरीद हो रही थी उस समय किसानों का पर्चा काटकर किसानों से दस्ती पैसा लिया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राईस से 100-100 रुपये कम पर किसानों की फसल खरीदी गई। इसी प्रकार से खाद की बात की जाये तो जो यूरिया और डी०ए०पी० खाद लेने जाते हैं तो उसकी कमी हो जाती है और जब कभी लेने जाते हैं तो उसके साथ दवाओं तथा बीज के पैकेट भी देने शुरु कर देते हैं जिसे किसानों को मजबूरी में खरीदना पड़ता है। मैंने कृषि मंत्री से पिछली बार भी इस बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि जितना खाद चाहिए उतना आ रहा है। मैं भी यह मानता हूं कि उतना खाद आ रहा है लेकिन कमी तब होती है जब कोइ चीज न मिले। जो चीज मिल रही है इसका मतलब कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमी उस समय कर दी जाती है जिस समय खाद की जरूरत होती है क्योंकि उस समय खाद की ऐलोकेशन कम कर दी जाती है। जब खाद की मांग खत्म हो जाती है तो फिर ऐलोकेशन पूरी करके दी जाती है। हमारा कहना यह है कि खाद की ऐलोकेशन समय पर होनी चाहिए ताकि बिजाई के समय और जिस समय किसानों को अपनी फसलों में यूरिया डालना हो, उस समय उसकी कमी न हो।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आपको बोलते हुए 21 मिनट हो गए हैं इसलिए अब आप कंक्लूड करें। You started speaking at 5.19 p.m.. I have noted your time.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपने मुझे कल या परसों कहा था कि मैं आपको बीस पच्चीस मिनट बोलने के लिए दूंगा। सर, मैं दो चार मिनट और लूंगा। मैं किसान के हित की बात करना चाहता हूं। जब किसान की फसल बाजार में जाती है तो उसका भाव मंदा हो जाता है लेकिन जब बड़े-बड़े पूंजीपतियों के गोदाम में वह जाती है तो उसका भाव ज्यादा हो जाता है। सर, हमारे एरिया में आजकल आलू की फसल आ रही है लेकिन इस बार वहां आलू एक रुपये किलो तक बिका है। आज भी वह पौने दो रुपये, दो रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। मेरी सदन के नेता से मांग है कि बाकी चीजों के साथ-साथ आलू और प्याज तथा जो फसल किसान पैदा करता है, उसका मिनीमम सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए ताकि उनको पता हो कि उनकी फसल इस रेट पर बिकेगी। इसके साथ-साथ अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। ऐजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अच्छी बात है कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो लेकिन जो बाहर से यूनिवर्सिटीज आएं या किसी भी कालेज को यदि आप कोई कोर्स चलाने की अनुमति देते हो तो उसको इस बात के लिए पाबन्द करें कि वह महंगी शिक्षा लोगों को नहीं देगा क्योंकि महंगी शिक्षा गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे नहीं ले सकते। उन पर पाबन्दी होनी चाहिए कि आपकी जो मैक्सिमम फीस होगी वह ठीक होगी। मैं एक बात और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र से पता नहीं क्यों उनको और वित्त मंत्री जी को नाराजगी है क्योंकि बजट में और गवर्नर ऐड्रेस में भी आप पढ़कर देख लें कहीं पर भी कुरुक्षेत्र का नाम आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ बीबीपुर लेक का जिक्र किया गया है। अभी धर्मबीर सिंह कह रहे थे कि बीबीपुर लेक के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन हमने तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, न हमारी पार्टी ने ऐसा किया है। वह तो मेरे हल्के में है भी नहीं बल्कि वह हल्का चड्ढा साहब का है। वहां के किसानों की मांग है कि इसकी गहराई ज्यादा कर दी जाए ताकि उसका एरिया कम हो। अभी तो उसका हजारों एकड़ में पानी फैल जाता है इसलिए उसकी खुदाई करके उसको गहरा किया जाए। सर, यही मांग हमारी तरफ से आयी

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कहीं पर जो लोग हैल्थ में बी०पी०एल० की सुविधा मांगते हैं और कहीं पर किसी और तरह की सुविधा मांगते हैं लेकिन पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर ऐसा है जहां पर ढाई या तीन हजार लोग ऐसे हैं जिनका न बी०पी०एल० है और न उनके पास रहने के लिए जगह है। वे लोग ब्रह्म सरोवर या सन्निहित सरोवर पर सोए रहते हैं। उनके रहने के लिए भी जगह दी जानी चाहिए और उनके लिए कुरुक्षेत्र में एक मल्टी स्पेशिएलिटी हॉस्पीटल भी जरूर बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या आप बाबाओं के लिए चाहते हैं कि वहां पर मल्टी स्पेशिएलिटी हॉस्पीटल बनें?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : जी हां सर, क्योंकि बीमार तो बाबे भी होते हैं। (विघ्न) सर, हॉस्पीटल तो वहां पर हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको और बड़ा करें। वहां पर ढाई हजार तो बाबा ही पड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हो कि वहां से बाबा हटें या रहें ?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, मैं तो चाहता हूं कि वे वहां पर रहें। वह धर्म नगरी है। मैं उनको हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात और मैं कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूंगा। आपके समेत जितने भी एम०एल०ए० हरियाणा प्रदेश के हैं उन सभी से गैस्ट टीचर्ज मिले थे।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, कुरुक्षेत्र में पुरोहित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं उनका क्या करें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, मैं तो उनकी पूजा करता हूं। मैं आपकी भी पूजा करता हूं क्योंकि आप भी पुरोहित हो। मैं कहना चाह रहा हूं कि गैस्ट टीचर्ज सभी विधायकों से मिले थे और उनको पक्का करने का आश्वासन भी कांग्रेस के कई विधायकों ने दिया था। मेरी मांग है कि जो कर्मचारी बहुत समय से काम कर रहे हैं, कई-कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको भी पक्का किया जाए। पिछले कई साल से सरकार इस बारे में नीति नहीं लाई है। महंगाई बढ़ रही है डी०सी० रेट पर जो कर्मचारी हम रखते हैं उनका उतनी तनख्वाह में गुजारा आज के दिन बिल्कुल नहीं चलता है इसलिए ऐसे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव अच्छे हैं। आपको बोलते हुए 26 मिनट हो गए हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सरकार को कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। जो ये हर बात में कह देते हैं कि 'पी०पी०पी०', यह नहीं होना चाहिए। जैन साहब भी सवाल के जवाब में कह रहे थे। सरकार को जनहित में काम करना होता है। कुछ महकमें ऐसे होते हैं जो जनहित में काम करते हैं। बस अड्डा भी पी०पी०पी० में देंगे तो वे मर्जी से रेट लगायेंगे, फीस तय करेंगे। मेरा अनुरोध है कि ऐसे महकमे प्राईवेट पार्टीज को न दें। पिछले साल के बजट में कहा गया था कि 4500 बसें बेड़े में होंगी और इस बार फिर वही कहा गया। आज हरियाणा प्रदेश में बसों की बहुत दिक्कत है। पूरे हाउस के लोग जानते हैं कि इतने नये कालेज बन रहे हैं उनके बच्चे बसों की इंतजार में खड़े रहते हैं बहुत देर बाद बस आती है तो उसके पीछे भागते हैं, कई बार ऐक्सीडेंट भी होते हैं। वर्ष 2005 में 3255 बसें थीं और स्टाफ 18675 था और आज बसें घटकर 3260 रह गई हैं, स्टाफ भी लगातार घटकर 16693 रह गया है। कैसे 4500 बसें करेंगे, इस बारे में जवाब में बताएं ? जब 3203 बसें थीं तब कहा था कि 4500 करेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 4500 बसें हो जाएंगी। हमारे विभाग में ड्राईवर्स और कंडक्टर्स की कमी थी इनको भर्ती करने जा रहे हैं। कुल 1837 चालकों की भर्ती करने जा रहे हैं और 3837 परिचालकों की भर्ती करने जा रहे हैं। यह भर्ती हो जाएगी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : पहले 3203 बसें थीं और अब 3260 हुईं, एक साल में मात्र 57 बसें बढ़ी हैं। 4500 पर बेड़ा कैसे ले जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप कंक्लूड करें क्योंकि बजट पर एफ०एम० साहब ने रिप्लाई भी देना है। इस प्रकार अन्य मैम्बर्स का समय चला जाएगा।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अभी एक बात का जिक्र आया था। खानों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी और कहा था कि 5 एकड़ से ज्यादा खान नहीं दे सकते। लेकिन 3 एकड़ की एक खान देकर एक सांसद को फायदा पहुंचाया गया। मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा सुरजेवाला जी ने कहा कि हमारे समय में 92 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया था और इन्होंने कहा कि इनके समय में 250 करोड़ रुपये का आया है। ये भी ध्यान दें कि पहले रेत का ट्रक 2500 रुपये का था और आज 11 हजार रुपये का है। बजरी 5 रुपये फुट थी आज 11 रुपये फुट के हिसाब से है। पब्लिक के हित की बात करते हैं तो उसमें ये जरूर डालें कि जो ठेकेदार इसमें लगे, उनके लिए यह तय कर दें कि मैक्सिमम इतने रुपये तक की रायल्टी ले सकता है। इससे ज्यादा नहीं ले सकता ताकि जो रेता और बजरी की कीमत बढ़ रही है, वह न बढ़े। एक तो महंगाई बढ़ रही है और उसी के साथ रेत की कीमत भी बढ़ रही है, उस पर आपको पाबन्दी लगानी चाहिए। धन्यवाद।

कुमारी शारदा राठौर (वल्लभगढ़) : धन्यवाद स्पीकर सर, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी का धन्यवाद करती हूं और साथ में बधाई भी देती हूं कि उन्होंने एक विकासशील, कल्याणकारी और एक सन्तुलित बजट यहां पर प्रस्तुत किया है। बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिससे सरकार की मन्शा का पता लगता है कि सरकार गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में क्या सोचती है उसकी क्या योजनाएं हैं। मुझे फख्र है कि जो हमारा बजट है यह सभी बिन्दुओं पर खरा उतरता है। इसमें 4458 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा भी दिखाया गया है। इस पर भी हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं। हरियाणा दो-तीन राज्यों में एक है जिन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले लागू की हैं और उसका फायदा हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को मिला है। सोशल सैक्टर पर जो खर्चा हुआ है उसकी वजह से भी राजस्व घाटा हुआ है। जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2012-13 में हमारा राजस्व सरप्लस में होगा। इसको देखकर मैं समझ सकती हूं कि घाटा मैनेजेबल है और हमारे वित्त मंत्री जी और हमारी सरकार के पास ऐसी योजना है जो इस घाटे को पूरा करके भी आने वाले समय में जो भी हमारी योजनाएं हैं, उनको भी पूरा करेंगे। प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ भी हम नई से नई योजना लागू करेंगे। जहां हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य आधारभूत ढांचा मजबूत करना है वहीं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना और हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक

[कुमारी शारदा राठौर]

नये विकास युग का भी सूत्रपात हुआ है और एक नये राजनीतिक युग का भी सूत्रपात हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है उसमें हरियाणा प्रदेश में हर क्षेत्र में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आये हैं और ये परिवर्तन आने वाले समय में हमारे विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं तो अपने विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहूंगी कि एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है इसलिए आप हरियाणा की राजनीति में भी और हरियाणा के विकास में भी अपना सहयोग दें। सिर्फ आलोचना करने की नीयत से मीनमेख न निकालें, आलोचना न करें। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** हम पहले सुना करते थे कि एक वैल्फेयर स्टेट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, किताबों में भी पढ़ा और सुना था। आज हरियाणा एक वैल्फेयर स्टेट के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। मैं यहां जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय बी०बी०सी० लन्दन से समाचार आया करते थे। उस वक्त हरियाणा काले अध्याय के रूप में जाना जाता था। महम काण्ड जैसे अध्याय के रूप में हमारा हरियाणा जाना जाता था। हम डर जाया करते थे। उस वक्त मैं स्टूडैंट हुआ करती थी और स्कूल में पढ़ती थी। उस समय सुबह-सुबह बी०बी०सी० लन्दन से सिर्फ महम काण्ड के समाचार सुनने को मिलते थे। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन आज हमें खुशी है कि आज हरियाणा की देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनी है। आज हरियाणा की पहचान एक खेल शक्ति के रूप में है, एक आर्थिक शक्ति के रूप में है, एक सामाजिक शक्ति के रूप में और एक शैक्षिक शक्ति के रूप में है। आज हमारी अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक शक्ति के रूप में पहचान बनी है। आज हरियाणा ने नये विकास के आयाम स्थापित किए हैं। आज हरियाणा की एक अलग पहचान बनी है। इस बात के लिए इनको भी धन्यवाद करना चाहिए और इनको गर्व भी होना चाहिए। आज हरियाणा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के निवेश में देश का प्रथम राज्य है और यह गर्व की बात है कि हमारी खेल नीति को, हमारी भूमि अधिग्रहण नीति को बाकी प्रदेश एक मॉडल नीति के रूप में सराह रहे हैं और अपना रहे हैं। गेहूं और सरसों के उत्पादन में भी हम लोग देश में प्रथम हैं। हरियाणा मनरेगा के तहत पूरे देश में सर्वाधिक मजदूरी देता है। यहां 179 रुपये प्रति व्यक्ति मजदूरी दी जाती है। पड़ोसी राज्यों को देखें तो पंजाब स्टेट में 124 से 130 रुपये प्रति व्यक्ति मजदूरी मिलती है। इसी तरीके से हिमाचल में 150 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलती है। चण्डीगढ़ जो कि हमारा संघीय क्षेत्र है उसमें भी हरियाणा से कम मजदूरी मिलती है। चंडीगढ़ में 174 रुपये मजदूरी मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह जी ने प्रमुख राज्यों के पी०सी०-एन०एस०डी०पी० पर नैशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च यानी NCAER की नवीनतम रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई दी है क्योंकि देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद हरियाणा का है। इसके लिए हमें भी सरकार को बधाई देनी चाहिए। P.E.-N.S.D.P. के दृष्टिकोण से NCAER के अध्ययन के अनुसार हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। गोआ के अलावा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में भी देश में पहले स्थान पर है। हमें हरियाणा पर गर्व होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय में 7.2 परसैंट की वृद्धि हुई है। कांसटैंट प्राइसिज के आधार पर हम 2004-05 की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय 28805 थी जो कि 2010 के अनुमानों के मुताबिक 55214 हुई है। दूसरे राज्यों की हम बात करें तो 37500 का आंकड़ा भी कोई भी राज्य छू नहीं पाया है। हमारे विकास की कहानी प्रदेश का बच्चा-बच्चा जान रहा है क्योंकि हमारा प्रदेश एक ट्रांसफार्मेशन के दौर से गुजर रहा है। यहां एक साइलैंट रैवोल्यूशन चल रही है। अभी हमारे भाई सम्पत सिंह जी ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने 2005 और 2010-11 का तुलनात्मक बजट प्रस्तुत किया। उसका सारा ब्यौरा आप

लोगों के सामने आ गया है। फिर भी अगर आप कहें कि बजट ठीक नहीं है तो यह सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में पब्लिक डैब्ट की बात करें तो 2004-05 में 38.87 परसैंट था और 2011-12 में 29.60 परसैंट है यानि कम हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बिना विकास सम्भव नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी स्वयं शिक्षा के प्रति गम्भीर और सजग रहते हैं। हमारी शिक्षा मंत्री जी भी मेहनत के साथ शिक्षा के प्रोत्साहन में लगी रहती हैं। पिछले 5 वर्षों में शिक्षा के बजट में तीन गुणा वृद्धि हुई है। 6913.76 करोड़ रुपये टैक्नीकल शिक्षा, खेलकूद और कला और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए खर्च किए जा रहे हैं जो कि सरकार के सराहनीय कदम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम अपने प्रदेश को इंटरनेशनल स्तर का हब बना पाएं और हम बना पाएंगे। 2004-05 की बात करें तो शिक्षा पर केवल 1878.22 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। उस समय सिर्फ इतनी व्यवस्था थी। मैं कहना चाहूंगी कि 1966 से लेकर 2005 तक केवल 5 विश्वविद्यालय थे। आज शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। 22 विश्वविद्यालय आज हमारे सामने हैं। इतनी तेजी से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी शायद ही कहीं हुई होगी। मैं एक-एक नाम पढ़ूंगी तो समय लग जाएगा। अपनी संस्कृति और भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट में अलग से प्रावधान किया है। हमारी जो अकादमियां हैं चाहे संस्कृत अकादमी है, चाहे उर्दू अकादमी है, चाहे पंजाबी अकादमी है या फिर हिन्दी अकादमी है उनमें हमारी सरकार अपने साहित्यकारों और लेखकों को सम्मानित करके एक-एक लाख, 51-51 हजार और 21-21 हजार रुपये के इनामात देने का काम कर रही है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग भाषाओं में उनकी पुस्तकें हैं। हमारी अकादमियां उन पुस्तकों को भी प्रकाशित करवा रही है। इसी तरह टैक्नीकल शिक्षा की बात करें तो 2005 तक सिर्फ 46 टैक्नीकल एजुकेशन इंस्टीच्यूट यानि इंजीनियरिंग कालेज और पॉलीटेक्निक कालेज हरियाणा में थे। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की सोच दूरगामी है। उन्हें पता है कि यह तकनीक की सदी है और यदि हमारे बच्चे तकनीकी शिक्षा के पीछे रह गए तो हमारी तरक्की सम्भव नहीं है।

18.00 बजे

आज हरियाणा में 550 से ज्यादा टैक्नीकल इंस्टीच्यूट्स हैं। इसके अतिरिक्त हम एस०सीज०, एस०टीज० के स्टूडैंट्स और विशेषकर लड़कियों के लिए विभिन्न योजनाएं दे रहे हैं। आने वाले समय में टैक्नीकल एजुकेशन विभाग बैंकों के द्वारा डायरैक्ट बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप के पैसे जमा करवायेगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत होरीजेंटल रिजर्वेशन की है। इस तरह से आई०टी०आईज० की सीटों में बढ़ोत्तरी हुई है और काफी बच्चों ने ऐडमिशन लिए हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि सामाजिक सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तो सभी सोचते हैं, सभी बात करते हैं लेकिन सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता की हमारे प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है तथा सबसे ज्यादा बजट देकर इस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। इसके पीछे मंशा यही थी कि गरीब से गरीब और हर वर्ग के आदमी ऊपर उठें, उनकी तरक्की हो और उत्थान हो। बजट में सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 5323.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जबकि वर्ष 2004 में केवल 1055.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। आज मुझे गर्व है कि वित्तमंत्री जी ने बजट में पिछड़े वर्ग और गरीबों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया है। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्ज और हैल्पर्ज का भी मानदेय बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, विकलांगों, किन्नरों, बौनों, वृद्धावस्था आदि पैंशन आने वाले समय में बैंकों के थ्रू दी जायेगी जैसा कि माननीय श्रीमती गीता भुक्कल जी ने बताया है। इसके अतिरिक्त ड्रग ऐडिक्ट्स का इलाज

[कुमारी शारदा राठौर]

करने के लिए सरकार ने ड्रग डी-एडिक्शन सैंटर खोले हैं ऐसा पहली बार हुआ है। (विघ्न) इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। वृद्धों के लिए राज्य पुरस्कार देना, वरिष्ठ नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करना, चश्में उपलब्ध करवाना, स्वैच्छिक सेवाएं परिसंघ स्थापित करवाना, वरिष्ठ महिलाओं को हरियाणा रोडवेज में 50 प्रतिशत किराए में रियायत देना, शहरों में सीनियर सिटीजन क्लब स्थापित करना आदि ऐसी योजनाएं हैं जिससे वृद्धों को सम्मान मिलेगा। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है।

Mr. Speaker : Please conclude.

कुमारी शारदा राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन ऐसे विषयों पर चर्चा और करना चाहूंगी जिनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया है। प्रदेश में बिजली की बढ़ोतरी के लिए काफी प्लांट लगाये गये हैं मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। इसके लिए भी बजट में 4962.06 करोड़ रुपये का अनुमान है जिससे लगभग 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। इसके अतिरिक्त पेयजल के लिए भी 1900.31 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें हमारी स्लम बस्तियों को भी शामिल किया गया है। झज्जर और कैथल जिले के लगभग 15 गांवों में आर०ओज० लगाये जा रहे हैं। पिछले वर्ष जो इन्दिरा गांधी पेय जल योजना शुरू की थी उसमें अनुसूचित जातियों के तकरीबन सभी घर कवर हो गये हैं और जो थोड़े से घर रह गए हैं हमें उम्मीद है कि उनको भी जल्दी ही कवर कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं फरीदाबाद जिले से आती हूं इसलिए मैं यह उल्लेख जरूर करना चाहूंगी कि हमने भवन एवं सड़कों पर काफी पैसा खर्च किया है। आज प्रदेश में बहुत से आर०ओ०बीज० बन रहे हैं और सड़कों का जाल भी हरियाणा में बिछा है। इसके साथ-साथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी काफी पैसा खर्च किया है। 98 गांवों को मॉडल विलेज बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत यह भी बहुत अच्छी की है कि हमारा हरियाणा प्रदेश लड़ाई झगड़ों के लिए जाना जाता है। गांवों में छोटी राजनीति के तहत कई बार लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर सोशल हार्मोनी अवार्ड शुरू किया है जो उन गांवों को दिया जायेगा जहां कोई लिटीगेशन नहीं होगी। यह कम्यूनल हार्मोनी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी 1695.01 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है इसके लिए भी मैं बधाई देती हूं। सिटी डिवैल्पमैंट प्लान के तहत 73 गांवों में रोड्ज, ड्रेन्ज, वाटर सप्लाई, सीवरेज आदि की व्यवस्था की जायेगी और जहां 50 प्रतिशत एस०सीज० आबादी है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, the Finance Minister has to reply. Sharda Ji, please conclude.

कुमारी शारदा राठौर : ठीक है सर, मैं जल्दी ही समाप्त करने जा रही हूं। सर, मैं अपनी सरकार के राज्यमंत्री श्री गोपाल कांडा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी इन्होंने पहली ही मीटिंग में यह कहा था कि जितने भी हमारे छोटे टाऊन हैं उनके लिए हम एक कंसोलिडेटिड इंडीकेटिड प्लॉन बनवायेंगे ताकि उसके हिसाब से उन्हें बजट की एलोकेशन हो और वहां की आधारभूत संरचना मजबूत हो सके। हमारे यहां उद्योग और वाणिज्य पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा है और नये-नये आई०एम०टीज० भी आ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक नया आई०एम०टी० बल्लभगढ़ में

भी आ रहा है, एक रोहतक में आ रहा है और एक रोज-का-मेव में भी आ रहा है, इस प्रकार से जो मेवात के विपक्षी विधायक मेवात की तरफ सरकार द्वारा ध्यान न दिये जाने की बात करते हैं वह गलत और निराधार है। इसी प्रकार से एक आई०एम०टी० खरखौदा में भी आ रहा है। ऐसे ही दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक फ्रेट कॉरीडोर जो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा जिससे औद्योगिक ढांचा मजबूत किया जायेगा और इसका फायदा सभी को होगा। इससे सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसी प्रकार से सरकार द्वारा गुड़गांव-दिल्ली के बीच में रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की गई है। सर, चाहे एग्जीबीशन-कम-कंवैंशन सैंटर हो, कलस्टर डैवलपमैंट हो या बहुउद्देश्यीय मॉडल लॉजिस्टिक हब्स की बात हो, ये सभी अपने आप में बहुत ही अनूठी परियोजनायें हैं जो हरियाणा में बहुत बड़े आयाम स्थापित करेंगी। विपक्ष के साथियों की सरकार के समय में उद्योगों की हालत क्या थी, यह सभी जानते हैं। फरीदाबाद इण्डस्ट्रियल टाऊन है, वहां के उद्योगपति विपक्ष के साथियों की सरकार के समय में डरा करते थे क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में भूसा भरवाने के लिए भेज दिया जाता था। उनको उत्तर प्रदेश में इंडियन नैशनल लोकदल द्वारा की जाने वाली रैलियों में बसों में भरकर भेजा जाता था। विपक्ष के साथियों की सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश की सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता था और हरियाणा प्रदेश का पैसा बर्बाद किया जाता था लेकिन मैं श्री चौटाला जी से यह पूछना चाहती हूं कि हरियाणा का पैसा उत्तर प्रदेश में पानी की तरह बहाने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश से आखिरकार क्या मिला? अर्थात् इन्हें वहां से कुछ नहीं मिला और अंत में इन्हें लौटकर अपने घर में ही आना पड़ा। सर, एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगी कि गुड़गांव हमारा एक ऐसा जिला है जो लेटैस्ट विदेशी टैक्नोलॉजी से सुसज्जित लगता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। जिस प्रकार से इलैक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी में गुड़गांव की पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान बनी है इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच को जाता है। वैसे तो आई०टी० और आई०टी०एस० इंडस्ट्री के हब के रूप में गुड़गांव की पहचान बनी है लेकिन उसको और प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यहां कई महत्वपूर्ण आई०टी० कम्पनियों द्वारा अपने उपक्रम स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा वहां पर 35 आई०टी० और आई०टी०एस० विशेष आर्थिक जोन को एप्रूवल्ज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 33 लाईसैंसिज आई०टी० और साईबर पार्क स्थापित करने के लिए दिये गये हैं। आई०एम०टी०, मानेसर में 10 टैक्नोलॉजी पार्क्स भी स्थापित किये गये हैं। इसके साथ-साथ 2600 सरकारी स्कूलों और सभी सरकारी कालेजिज में आई०सी०टी० लैब्ज का भी निर्माण किया जा रहा है जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। इसके साथ-साथ विभिन्न गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स के 1400 ऑफिसिज में वर्टीकल और होरीजोंटल कनेक्टिविटी की स्थापना भी की जा रही है जिससे स्टेट-वाईज एरिया नैटवर्किंग और स्टेट डाटा सैंटर को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ मजबूती भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ई-गवर्नैंस की शुरुआत भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक जिले से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बाकी के जिलों में बाद में इसकी शुरुआत होगी क्योंकि आज ई-गवर्नैंस का समय है। इसके तहत हमारी चार सर्विसिज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है।

Mr. Speaker : Sharda Ji, please conclude.

कुमारी शारदा राठौर : सर, मैं कंक्लयूड ही कर रही हूं। एक मैडीकल कालेज भी बन रहा है और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) ई-गवर्नैंस से चार सर्विसिज का बड़ा सुधारीकरण होगा। इससे इन्कम टैक्स सर्टीफिकेट बनेंगे, कास्ट सर्टीफिकेट बनेंगे, डोमीसाईल बनेंगे

[कुमारी शारदा राठौर]

और जो भी हमारी ग्रिवेंसिज होंगी उनको भी हम लोग भेज सकेंगे। स्पीकर सर, कहने को तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं लेकिन समय की कमी है। फिर भी मैं माननीय किरण चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अगर सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेन्ट पॉलिसी कोई अब तक के इतिहास में आई है तो वह हमारी एक्साईज पॉलिसी आई है; इससे ज्यादा से ज्यादा रैवेन्यू कलैक्शन होगा। पहले जो सरकार और अधिकारियों के हाथ में डिस्क्रीशन हुआ करती थी अब वह डिस्क्रीशन नहीं है। इसके साथ ही जो माफिया का पहले इस मामले में कंट्रोल हुआ करता था वह हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। स्पीकर सर, जो विपक्ष के साथी हमें बोलने नहीं देते, इनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। स्पीकर सर, मैं यहां पर एक शेर जरूर अर्ज करना चाहूंगी -

साथ चलने का इरादा जब जवां हो जायेगा,
आदमी मिल आदमी से कारवां हो जायेगा,
तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमीं,
तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जायेगा।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किस ग्रुप के कितने मैम्बर हैं उसी अनुपात में उनको बोलने का टाईम मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से बत्तरा साहब 45 मिनट बोले हैं। सम्पत सिंह जी 50 मिनट बोले हैं। प्रहलाद सिंह गिल्लांखेड़ा 20 मिनट बोले हैं, श्री धर्मबीर जी, 15 मिनट बोले हैं। बलबीर पाल शाह जी 20 मिनट बोले हैं और कुमारी शारदा राठौर 25 मिनट बोली हैं। हमारी तरफ से दो ही सदस्य बोले हैं। मुझे 20 मिनट का समय मिला है जबकि अशोक अरोड़ा जी 25 मिनट का समय मिला है तथा तीसरे आदमी को अब आपने बोलने के लिए समय दिया है। इस प्रकार की ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। जिस ग्रुप के जितने सदस्य हों उसी अनुपात में उनको टाईम दिया जाना चाहिए। आपने घोषणा कर दी कि इसके बाद वित्त मंत्री जी बोलेंगे, इसका मतलब बाकी बचे हुए लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप तो 65 मिनट बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला : क्या आप शोर-शराबे को भी मेरे टाईम में जोड़ रहे हैं। आपने यह कैसे कह दिया कि इसके बाद वित्त मंत्री जवाब देंगे।

Mr. Speaker : I have to look to the time.

श्री औम प्रकाश चौटाला : आपको यह तो पहले देखना चाहिए था। आपने उनको इतना टाईम कैसे दे दिया? आपके ऊपर हम पक्षपात का आरोप लगायें तो कोई अच्छी बात थोड़े ही होगी। इस तरह से नहीं चल पायेगा। आपको सबको टाईम देना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराणा) (एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2011-12 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब भी बजट पेश किया जाता है तो प्रदेश के लोग समझते हैं कि किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का तथा उद्योगपतियों का सबका ध्यान रखा जायेगा लेकिन बजट पढ़ कर ऐसा लगा कि प्रदेश के हित में यह बजट नहीं है। जैसा मेरी

पार्टी के नेता ने भी सदन में बताया कि 2004-05 में जो सरकार थी उसकी देनदारियां 23319 करोड़ रुपये थीं लेकिन आज 2011 में यह बढ़कर 52702 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वह 2006-07 में 1189 करोड़ रुपये हो गया था जो 2009-10 में 10090 करोड़ रुपये हो गया है। 2010-11 संशोधित अनुमान तथा 2011-12 में बजट का ऐस्टीमेटिड घाटा क्रमश: 8750 व 8009 करोड़ रुपये होना निश्चित दिखाया गया है। 2009-10 का जो रिवाईज्ड अनुमान दर्शाया है उसको देखकर लगता है कि घाटा और बढ़कर 1216 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में बताना चाहूंगा। जब वर्ष 2005 में कांग्रेस की सरकार आई तथा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने शपथ लेने के बाद जनता को बताया था कि बिजली की समस्या हमें विरासत में मिली है लेकिन आगामी 2 वर्षों में बिजली की समस्या न केवल खत्म हो जायेगी बल्कि प्रदेश में बिजली का अतिरिक्त उत्पादन भी होगा जिससे दूसरे प्रदेशों को भी बिजली बेची जा सकेगी। उसके बाद 2 फरवरी, 2006 को दीन बंधु सर छोटू राम जयंती पर मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि हम तीन वर्षों में 5 हजार मेगावाट बिजली की वृद्धि करने जा रहे हैं क्योंकि यमुनानगर में 600 मेगावाट की क्षमता की परियोजना पर भी कार्य चल रहा है और फरीदाबाद का जो 1065 मेगावाट का गैस पर आधारित प्लांट है उस परियोजना की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। यह मुख्यमंत्री जी का ब्यान है कि झज्जर में 1000 मेगावाट और हिसार में खेदड़ में 1200 मेगावाट के प्लांट पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद 5.3.2006 को 'नव निर्माण रैली' के दौरान फिर इनका बयान आया कि पिछले 40 वर्षों में 4033 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ जिसमें से प्रदेश के अपने संसाधनों से 1587 मेगावाट बिजली पैदा हुई और इसमें से 75 प्रतिशत बिजली चौधरी देवीलाल के शासनकाल में पैदा हुई है। इसके बाद फिर एन०डी०टी०वी० पर मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हम तीन साल में 5 हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। 18 जनवरी, 2006 को चैम्बर्ज ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में फिर इन्होंने कहा कि तीन वर्षों में हम 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। एक सितम्बर, 2006 को 'इंडिया टुडे' में फिर इनका बयान आया कि हम 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। 7 अक्तूबर, 2007 को झाडली में बिजली रैली में फिर इनका बयान आया कि हम पांच हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। 26 अक्तूबर, 2007 को अपने निवास स्थान चण्डीगढ़ में फिर इन्होंने बयान दिया कि तीन साढ़े तीन साल में पांच हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। एक नवम्बर, 2007 को दीन बन्धू सर छोटू राम यमुनानगर पावर प्लांट के बारे में इन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में इसको चालू कर देंगे। 25 फरवरी, 2007 को भी इनका सिरसा से बयान आया, 26 जनवरी, 2008 को फिर रिवाड़ी से इनका बयान आया। इस तरह से यह बहुत लम्बी लिस्ट है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मैंने मुख्यमंत्री जी की एक किताब पढ़ी है उसमें मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि विकास की उड़ान अभी बाकी है। यह किताब सारी पढ़कर मैंने इसमें डेटवाइज कलैक्शन की है। आज अगर प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की नैगलीजेन्सी है। रिलायंस कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए खेदड़ के पावर प्लांट को इन एडवांस सिंक्रोनाइज कर दिया जबकि कोयले का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इन्होंने फर्निश ऑयल पर इसको ट्रायल बेस पर चला दिया। ट्रायल बेस पर चलाने की वजह से सरकार का, एच०पी०जी०सी०एल० का उसमें 168.23 करोड़ रुपये का तेल लगा और बिजली पैदा कितनी हुई, बिजली पैदा सिर्फ 69.16 करोड़ रुपये की हुई और घाटा 102.07 करोड़ रुपये का हुआ। इसके अलावा पानीपत से इमरजेन्सी में जो कोयला हिसार के थर्मल पावर प्लांट के लिए आ रहा है

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

वह घटिया किस्म का आ रहा है। एच०पी०जी०सी०एल० पानीपत को रेलवे को 12 लाख का अलग से किराया देना पड़ा है। इसके अलावा जो मेन कमी है वह एक और है। एक यूनिट बिजली तैयार करने के लिए चार हजार क्लोरीफिल वैल्यू होनी चाहिए लेकिन आज हालत यह है कि पानीपत के थर्मल पावर प्लांट में चार हजार क्लोरीफिल वैल्यू के बजाए 3500 क्लोरीफिल वैल्यू आ रही है, यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट में 3600 क्लोरीफिल वैल्यू आ रही है और हिसार के थर्मल पावर प्लांट में 2800 क्लोरीफिल वैल्यू आ रही है। कहने का मतलब यह है कि एक किलो कोयला खर्च करके एक यूनिट बिजली हिसार थर्मल पावर प्लांट में बन रही है, 750 ग्राम कोयला खर्च करके यमुनानगर पावर प्लांट में एक यूनिट बिजली बन रही है और 800 ग्राम कोयला खर्च करे पानीपत थर्मल पावर प्लांट में एक यूनिट बिजली बन रही है। मैं पंडित तो नहीं हूं लेकिन भविष्यवाणी कर रहा हूं कि खेदड़ प्लांट में सबसे बड़ा नुक्सान होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पावर प्लांट में जो एक ड्राई ऐसकुलेक्शन सिस्टम होता है जिसको हम सैलो बोलते हैं, जितनी हमारी ऐश होती है उसका ब्लो डाउन सब पम्प में मिक्स करके ऐश डैक से बाहर निकाल देते हैं लेकिन वह सिस्टम अभी तक चालू नहीं हुआ है। जब इस खेदड़ प्लांट को ट्रायल बेस पर चलाया गया तो वह सी०सी०एल० कम्पनी के कोयले से चलाया गया जबकि उसको एम०सी०एल० कम्पनी के कोयले से चलाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, वहां के जो प्रवक्ता के०सी० गर्ग हैं उनका बयान आया है कि दो-तीन महीने में इंडोनेशिया से कोयला आ जाएगा। स्पीकर साहब, इनके पास कोयला नहीं है। आज के अखबार में चीफ इंजीनियर का बयान है कि यमुनानगर के दो यूनिट और पानीपत की एक यूनिट बंद है। वे कहते हैं कि केवल 2-3 दिन का कोयला बचा है। ये आज अखबारों में है। इसके अलावा फर्नेस ऑयल का बहुत बड़ा घोटाला है। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट जब चालू किया गया तो दिल्ली से फर्नेस ऑयल ट्रकों में लाया गया क्योंकि तब तक रेलवे लाइन वहां स्थापित नहीं हुई थी। जिसकी वजह से क्वांटिटी काफी कम आई और करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। अखबारों में भी इस बारे में आया है। सरकार इसकी इंक्वायरी कराए और जवाब में मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी इस बारे में बताएं और रिसपौंसिबिलिटी भी फिक्स करें कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वहां लिफ्ट सिस्टम है लेकिन लिफ्ट चालू नहीं हुई। लिफ्ट का मतलब यह नहीं कि वह आदमी के जाने के लिए है। बॉयलर ऊंचाई वहां 65 मीटर है। कोल बंकर हैं जहां पर कोयला पड़ता है, कन्वेयर बैल्ट है कई बार इमरजैंसी में फायर हो जाता है। इमरजैंसी में 65 मीटर तक कोई पौड़ियों से चढ़ेगा तो तब तक तो भारी नुक्सान हो जाएगा। लिफ्ट की कमीशनिंग वहां नहीं हुई है, उसके लिए भी आदेश दें। यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट है जिसके बारे में औम प्रकाश चौटाला जी ने बताया था। उसका एम०ओ०यू० चौधरी औम प्रकाश चौटला जी के समय में हुआ था। बी०एच०ई०एल० को यह ठेका दिया गया था लेकिन मौजूदा सरकार ने उस ठेके को कैंसिल करके वह ठेका रिलायंस कंपनी को दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि ई०एस०पी० जिसको इलैक्ट्रोस्टेट प्रेसिपिटेटर कहते हैं, में इतनी ऐश भर गई कि वह डक्ट के नीचे गिर गया और परिणामस्वरूप 6 महीने तक वह प्लांट बंद रहा। सी०ए०जी० की रिपोर्ट के मुताबिक उस प्लांट के बंद रहने से सरकार को 480 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ। इसके अलावा गोल्ड शील्ड की बात करते हैं। आल इंडिया इंजीनियर पावर फैडरेशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि 500 करोड़ रुपये का नुक्सान हो गया और इसके बावजूद उनको गोल्ड मैडल दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि जो गोल्ड मैडल दिया गया उसको वापस लिया जाए। ब्लो डाउन पम्प हाउस यमुनानगर पावर प्लांट का चालू नहीं है। इसी प्रकार

से झाड़ली पावर प्लांट की बात ये बार-बार कहते हैं, 1500 मेगावाट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर की बात करते हैं। स्पीकर सर, सरकार असलियत नहीं बताती। असलियत यह है कि उसमें 50 परसैंट शेयर एन०टी०पी०सी० का, 25 परसैंट दिल्ली गवर्नमैंट का और 25 परसैंट हरियाणा गवर्नमैंट का है। (विघ्न) मुख्यमंत्री जी ने खुद यह बात ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कही है। वित्त मंत्री जी जवाब देते समय इसके बारे में भी बताएं। (विघ्न) उस 1500 मेगावाट में से हरियाणा को कितनी बिजली मिल रही है। सी०एल०पी० कंपनी द्वारा 660 मेगावाट के दो यूनिट बनाए, जो चाइनीज कंपनी ने बनाए हैं। सरकार यह भी बताएं कि ये जो 660 मेगावाट के दो यूनिट हैं उनमें से हरियाणा को कितनी बिजली मिल रही है? इसके अलावा फरीदाबाद के जो 3 यूनिट थे वह सरकार ने बंद कर दिये और मुख्यमंत्री ने केवल इतना कह दिया कि पौल्यूशन की वजह से बंद किए हैं। क्या मुख्यमंत्री जी यह बताएंगे कि उनको वहां से शिफ्ट करके कहां लगाने का काम किया गया है? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या पानीपत थर्मल प्लांट की है। यह प्रदेश का सबसे पहला प्लांट है। सरकार ने यह कहा कि उस प्लांट से 1999 से 2005 तक 724.4 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। आज की मौजूदा सरकार ने दावा कर दिया कि 2005 में 1643 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। स्पीकर सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1989 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, उस समय इस प्लांट की 210 मेगावाट की पांचवीं यूनिट का पाथलिंग वर्क सौ परसैंट हो गया था। उसके बाद चौधरी साहब उप प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हमारी सरकार चली गई। 1991 में कांग्रेस की सरकार आई। उसके साथ साढ़े तीन साल तक चौधरी बंसी लाल की सरकार रही। उनके समय में उस प्लांट के लिए 100 करोड़ रुपये का सामान आ गया था और वह रेलवे स्टेशन पानीपत में पड़ा रहा और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। 24 जुलाई, 1999 को चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 210 मेगावाट की पांचवीं यूनिट चालू हुई, उसके बाद 210 की छठी और 7वीं यूनिट शुरू हुई और 7वीं व 8वीं यूनिट 250-250 मेगावाट की चालू हुई। कहने का मतलब यह है कि कुल 920 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट पानीपत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में लगे। इसके अलावा जो 6, 7 और 8 यूनिट हैं उनका एक स्टैंडर्ड है कि वह इन टाईम दो मिल चलने चाहिए। एच०पी०जी०सी०एल० का बहुत घाटा हो रहा है वह तीन मिल चला रहे हैं क्योंकि कोयला घटिया एफ ग्रेड का आ रहा है जबकि हमारा जो स्टैण्डर्ड कोयला है वह डी ग्रेड के बीच का होना चाहिए, लेकिन अब एफ ग्रेड का कोयला आ रहा है, इसलिए दो की बजाए तीन मिल चलानी पड़ रही हैं। पानीपत पावर प्लांट में स्टाफ की 3376 पोस्टें सैंग्शंड हैं लेकिन वहां पर आज 966 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हिसार थर्मल पावर प्लांट में 600 पोस्टें सैंग्शंड हैं लेकिन वहां 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यमुनानगर पावर प्लांट में 461 पोस्टें सैंग्शंड हैं लेकिन वहां 150 कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब कर्मचारी साईट पर नहीं होंगे तो कैसे प्लांट चलेंगे? इसके अलावा अगले पांच साल के लिए कोई ऐश डैक का प्रबन्ध नहीं किया गया। सर, लाखों टन ऐश होती है उसका ऐश डैक होता है उसके लिए सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। पानीपत पावर प्लांट की यह हालत है कि वहां सातवां और आठवां यूनिट जो 250-250 मैगावाट के हैं, उनके लिए ऐश डालने का केवल सात महीने का समय है उसके बाद ऐश डालने का कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा इस प्लांट की एक, दो और तीन यूनिटों का ऐश डिस्पोजल का कोई प्रबन्ध नहीं किया, किसी नार्म्स के तहत काम नहीं किया गया। तीनों यूनिट्स के ऐश डैक कम्पलीट हो चुके हैं। इससे सरकार और एच०पी०जी०सी०एल० को बहुत नुक्सान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा जो फ्यूल कन्जम्पशन प्रतिदिन हो रहा है वह एक यूनिट पर 3.37 मिलीलीटर हो रहा है जबकि एच०ई०आर०सी० के नार्म्स के अनुसार 1.61 मिलीलीटर होना

[श्री कृष्ण लाल पंवार]
चाहिए। इसके अलावा जो एग्जलरी कन्जम्पशन होती है वह 10.21 प्रतिशत हो रही है जबकि एच०ई०आर०सी० के हिसाब से 9.61 प्रतिशत होनी चाहिए। इसके अलावा पी०एल०एफ० पूरे एक साल का सभी प्लांट्स का 77.14 प्रतिशत है जबकि एच०ई०आर०सी० के हिसाब से 80.19 प्रतिशत होना चाहिए। वह कम है इसकी वजह घटिया कोयला है और इसी वजह से हमारा बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। स्पीकर सर, खुखराना और सुताना मेरे हल्के के गांव हैं। वर्ष 1974-75 में पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट स्थापित हुआ था, वहां पर 55 एकड़ जमीन है जिसमें सुचाड़ बनाया हुआ है कि जिनको बड़े-बड़े टॉवर बोलते हैं। न तो सरकार ने जमीन एक्वायर की और न ही किसान उस जमीन को बीज सकते हैं। वहां पर टॉवर बनाये हुए हैं और सारी जमीन में पानी भरा हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार उस जमीन को ऐक्वायर करे और किसानों को मुआवजा दे। स्पीकर सर, 25-30 साल से किसानों को एक भी पैसा नहीं मिला है। दिल्ली के एक एम०पी० के भाई की एक कम्पनी थी लोको अमर कान्टैक थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट। हरियाणा सरकार ने उस कम्पनी के साथ एम०ओ०यू० किया था कि इस कम्पनी से हम हरियाणा के लिए बिजली लेंगे। इसका प्लांट हैदराबाद में है, वह प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। इसके लिए वित्तमंत्री जी बतायें कि वहां से हरियाणा को कितनी बिजली आ रही है?

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल जी, आपको बोलते हुए 26 मिनट हो गये हैं।

श्री कृष्णलाल पंवार : स्पीकर सर, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं। जहां तक सभी एम०एल०एज० के बारे में बात है। बड़ी खुशी की बात है कि आपने कहा कि सभी एम०एल०एज० के लिए एम०एल०एज० हॉस्टल की रेनोवेशन करेंगे लेकिन जो हरियाणा विधान सभा की रेनोवेशन हुई है उस पर 6 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च किया गया है आप इसकी इन्क्वायरी करवायें। कोई भी एम०एल०ए० एम०एल०एज० होस्टल में रहता है तो तीन दिन के बाद उसको स्पीकर की चिट्ठी आती है कि वह तीन दिन से ज्यादा वहां नहीं रह सकता और यदि वह रहता है तो उसको पैनल रैन्ट 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा। परन्तु कई एम०एल०एज० वहां रह रहे हैं। इसके अलावा स्पीकर सर, आप किसी भी स्टेट में देख लें, विधान सभा के अन्दर विपक्ष के नेता का अलग से कमरा होता है। यहां कमरा तो बनाया गया है लेकिन आज तक विपक्ष के नेता को कमरा नहीं दिया गया है। स्पीकर सर, इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत एस०सीज० परिवारों को पानी के कनैक्शन दिये गये हैं उन पर 6.34 करोड़ रुपये बर्बाद हुए हैं क्योंकि एस०सीज० परिवारों को जो 22649 जल आपूर्ति कनैक्शन दिये गये हैं वहां पर कच्चा पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। इसके अलावा आई०सी०डी०सी० का मुख्य उद्देश्य छः वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य सुधार रखना है। इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश में 17644 आंगनवाड़ी सैंटर हैं जिनमें से 12707 आंगनवाड़ी सैंटरों में पेयजल की सुविधा नहीं है और 2922 आंगनवाड़ी सैंटरों में शौचालय नहीं हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended for half an hour?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for half an hour.

वर्ष 2011-12 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सिंचाई विभाग की बात करें तो जो CAG की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि बिना सिंचाई की उपलब्धता के सिंचाई चैनल्स का निर्माण कर दिया गया और इन पर 85.75 लाख रुपये खर्च कर दिए गए। उस पर 41.16 लाख रुपये ब्याज देना पड़ा। ड्रेनेज स्कीम पर 52 लाख रुपये खर्च कर दिए गए और अपूर्ण जलापूर्ति कार्य पर 49 लाख रुपये खर्च कर दिए।

Mr. Speaker : Thanks you Krishan Lal Ji. Hon'ble Finance Minister will give reply.

श्री कृष्ण पाल पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी कंक्लयूड कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Thank you, please take your seat

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मुझे न परसों बोलने दिया गया और न ही आज बोलने का मौका दिया गया।

Mr. Speaker : Please sit down. आपको कल एप्रोप्रिएशन बिल पर बुलवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें 5-5 मिनट का समय दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए, आपकी सारी सीनियर लीडरशिप बोली है इसलिए आप सब बैठिए। आपको कल बुलवाएंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें 5 मिनट का समय दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, you have been very liberal. आप इनको दो-दो घण्टे बुलवाते हैं। You have been more than liberal. Everybody has been given a chance. Finance Minister has to reply now, Sir. They have to hear, I know they want to run away. They did not hear Chief Minister's reply on Governor's Address. They are about to run away again. They only look for an opportunity to run away.

Mr. Speaker : Finance Minister may start his reply.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कंक्ल्यूड करने का मौका तो दे दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्हें कंक्ल्यूड तो करने दें।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब ये कंक्ल्यूड कर नहीं रहे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो ये कंक्ल्यूड करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृष्ण लाल जी, आप एक मिनट में कंक्ल्यूड कर दें।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, असंध के फफड़ाना के अंदर जो शुगर मिल है, मुख्यमंत्री जी ने जब उस शुगर मिल को खोलने के लिए अनाउंसमेंट की थी तो वह कोऑपरेटिव सैक्टर के अंडर की थी। उसे बाद किसानों से शेयर के लिए पैसा लिया गया। किसानों ने उसमें अपना शेयर लिया। उसके बाद उसको हैफेड के अंडर कर दिया लेकिन आज तक उस करोड़ों रुपयों का पता नहीं

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

चला कि वह किस हैड में चला गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर शुगर मिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अनाउंसमैंट हुई कि अगर कोई किसान अर्ली वैरायटी का गन्ना उगाएगा तो हम किसान को 1250 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में देंगे। इसके बाद किसानों ने गन्ना उगाया लेकिन आज तक किसी किसान को एक पैसा भी नहीं मिला है जिसके कारण किसान वहां पर धरने दे रहे हैं।

Mr. Speaker : Thank you very much. Your one minute is over. अब कंक्ल्यूड करें।

श्री कृष्ण लाल पंवार : जब किसान की जमीन एक्वायर की गई तो गांव के किसानों ने कहा था कि जो लैंड लूजर किसान हैं उन परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए। जब पंचायत से रैजोल्यूशन लिया गया तो कहा गया कि नौकरी देंगे लेकिन फफड़ाना गांव का एक सफाई कर्मचारी भी नहीं लगाया गया। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी अपना ब्यान दें।

Mr. Speaker : Thank you very much. (Interruption) I promise that you will speak tomorrow.

वॉक आऊट

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आप हमारी बात भी नहीं सुनेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा और अब फिर दोहरा रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोगों को आपने 3 घण्टे अलाट किए। हमारे 32 एम०एल०एज० हैं और आपने हमें केवल एक घण्टा दिया है। यह कोई ठीक बात नहीं है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Hon'ble Leader of the Opposition says that I have allowed six members from the Treasury Benches to speak whereas four-five from the Opposition. Is it not in proportion to the strength of the House? (Interruption) I want to make it clear that the total time allotted to the Opposition is much more than the time allotted to the Treasury Benches. So, Finance Minister you may reply. (Interruption) चौटाला साहब यह रिकार्ड है। 114 मिनट ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से बजट पर बोले हैं और 119 मिनट विपक्ष की तरफ से बोले हैं।

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमें बीच-बीच में इन्ट्रप्ट भी किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, जब ये लोग बोले हैं इन्ट्रप्शन तो तब भी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से सदस्यों ने बजट पर बोलना था लेकिन उन्हें बजट पर बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है इसलिए ऐज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आऊट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल लोकदल और शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य बजट अनुमानों पर बोलने के लिए समय न दिये जाने पर सदन से वाक आऊट कर गए।)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption) Hon'ble Members my ruling is that the total time taken by the Congress Party i.e. Treasury Benches for that matter is 114 minutes. Total time taken by the INLD is 119 minutes whereas 32 minutes have been taken by BJP. (Interruption) Shri Anil Vij spoke. Now, Finance Minister may reply. (Interruption)

वर्ष 2011-12 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा 9 मार्च को प्रस्तुत किये गये बजट अनुमान 2011-12 पर हमारे पक्ष और विपक्ष के कई साथियों ने खुलकर अपने विचार रखे तथा सभी ने अपने बहुमूल्य व सार्थक सुझाव दिए। आप सभी जानते हैं कि आर्थिक मंदी की वजह से हमने पिछले 2-3 वर्ष कठिन परिस्थितियों में बिताए हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है तथा सभी कठिनाइयों का सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, जो हमने बजट प्रस्तुत किया है वह आम आदमी का बजट है और प्रगतिशील बजट है जिसमें हमने विशेष फोकस सामाजिक क्षेत्र पर रखा है और इस क्षेत्र के लिए 49.1 प्रतिशत पैसा प्लान बजट में रखा है। दूसरा हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है तथा इसके लिए 35.5 प्रतिशत पैसा प्लान बजट में रखा है जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा ध्यान प्रदेश की उन्नति तथा विकास की तरफ है। वर्ष 2005-2010 की अवधि के दौरान हमारा पूंजीगत खर्च 2000-2005 की तुलना में 129 प्रतिशत बढ़ा है। हमने विशेष रूप से सिंचाई, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, सड़कों, कृषि, ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास पर ध्यान दिया है। हमने बजट पूर्ण रूप से टैक्स फ्री इसलिए दिया है ताकि आम आदमी पर कोई नया आर्थिक बोझ न पड़े। हम गैर योजनागत खर्चों में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान हमने प्रशासनिक खर्चों में 10 प्रतिशत की कमी की है। हमारा प्रयास रहेगा कि वर्ष 2012-13 में हरियाणा रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो जाये। हमने सभी कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग लागू किया और उनके सभी एरियर्ज का भुगतान भी कर दिया है जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ा लेकिन हमने यह लागू किया। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब ने अभी छठा वेतन आयोग लागू ही नहीं किया है। दूसरे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अभी केवल 30 प्रतिशत एरियर ही दिया गया है। किसी शायर ने कहा है-

शायद हमारी बात ये उनको बुरी लगे,
लेकिन यकीं करो, मेरी नीयत बुरी नहीं।
(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

अध्यक्ष महोदय, हमने जहां कर्मचारियों को उनके पूरे एरियर्ज दिए हैं उसके साथ-साथ प्रदेश के हित के बारे में भी पूरा सोचा है। सर, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने, श्री अनिल विज जी ने, श्री भारत भूषण बतरा जी ने, श्री सम्पत सिंह जी ने, श्री प्रह्लाद सिंह गिल्लांखेड़ा जी ने, श्री धर्मबीर सिंह जी ने, श्री बलबीर पाल शाह जी ने, श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी ने, कुमारी शारदा राठौर जी ने और श्री कृष्ण पाल पंवार जी ने यहां विभिन्न विषयों पर अपने-अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि सभी ने अपने-अपने तरीके से सार्थक विचार रखे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक बजट का सवाल है विपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने बजट का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया है। हालांकि ये बहुत सुलझे हुए और तजुर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं। हमारी यह अपेक्षा थी कि वे प्रदेश के हित में बहुत से सार्थक सुझाव देंगे और मुझे मार्गदर्शन देने का काम भी करेंगे लेकिन उन्होंने केवल मात्र आलोचना की है और कोई भी नया सुझाव नहीं दिया है। सर, मैं पिछले 22 वर्षों से इस विधान सभा में लगातार चुनकर आ

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस समय जो हमारा level of debate है वह निरंतर गिर रहा है। इसके लिए सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और विपक्ष को भी अपनी भूमिका को रचनात्मक तरीके से निभाना चाहिए। विशेष तौर पर जब विपक्ष के माननीय सदस्य हमें अच्छे सजैशंज़ देते हैं तो वे हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें एक-दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिएं और न ही एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ही करनी चाहिए। यही हमारा हाउस के प्रति फर्ज बनता है। हमें सही तरीके से आंकड़े पेश करने चाहिएं और सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं "जो सफर तय कर चुके हैं उनको तो नाज़-ए-सफ़र है, जो दो कदम भी चले नहीं वे रफ्तार की बातें करते हैं।"

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आप शेर के ऊपर प्वायंट ऑफ आर्डर मांग रहे हैं क्या आप शेर सुनाना चाहते हैं। आप शेर सुनाना लेकिन पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। यह मैं हरियाणा प्रदेश के हित में कह रहा हूं "लम्बा सफ़र है दोस्त बनाकर चलो, दिल मिलें न मिलें लेकिन हाथ मिलाकर चलो" अगर आप भी शेर सुनाना चाहते हैं तो सुनाईए।

वॉक आऊट

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मैं एक बात प्वायंट ऑफ आर्डर पर कहना चाहता हूं कि— (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आपका प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं बनता इसलिए आप कृपया बैठ जायें।

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय जी को कोटला लेक के बारे में सुझाव दिया था, क्या उन्होंने उसको मान लिया है?

श्री अध्यक्ष : हां, मान लिया है। अब आप बैठ जायें।

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, * * * *

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, has Mr. Illyas taken your permission to speak?

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Iliyas Ji, please be seated.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, लगता है कि आप मोहम्मद इलियास जी के ऊपर आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। ये हर मैम्बर को डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप इन्हें कुछ नहीं कहते। Speaker Sir, he cannot disturb the House like this. Although he is a Hon'ble Member of this House but he has no right to disturb the Hon'ble Minister like this. How can he disturb the Minister? He cannot disturb the House like this. ये माननीय वित्तमंत्री जी को भी कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Illyas Ji, please take your seat. Hon'ble Finance Minister please continue.

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं as a protest इस सदन से वॉक-आउट करता हूं।

(At this stage, Shri Mohammad Illyas, a member of the Indian National Lok Dal, staged a walk out as a protest against not being allowed to raise a point of order.)

वर्ष 2011-12 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जिस प्रकार से विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथियों ने बी०एम०एल० कैनाल और एस०वाई०एल० कैनाल के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया है उसके लिए मैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी साथियों की सराहना करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। इससे एक बहुत ही अच्छी परिपाटी हाउस के अन्दर स्थापित हुई और चारों तरफ हरियाणा प्रदेश के हित के मुद्दों पर पूरे हाउस की एकता का संदेश गया है। सर, जो हांसी-बुटाना लिंक नहर है यह एक मल्टी परपज नहर है। इससे गुहला, चीका और कैथल के एरिया को बाढ़ के पानी से राहत मिलेगी और इनलैट चैनल के द्वारा जीरी के लिए पानी दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि आप अगर हिसार के ही एरिया को देखें तो वहां पर एक ऐसा इलाका है जहां पर 16 दिन पानी चलता है और 16 दिन पानी बंद रहता है और दूसरी तरफ नारनौंद का एरिया है, हांसी का एरिया है जहां 32 दिन में केवल 8 दिन पानी चलता है। अध्यक्ष महोदय, बी०एम०एल० हांसी-बुटाना लिंक कैनाल बनाने का हमारा केवल एक ही मकसद था कि पानी का समान बंटवारा हो ताकि इससे 18 जिलों को लाभ हो। हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि यह नहर वायबल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि यह वायबल है फिर बार-बार इस बात को क्यों उठाया जा रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल वाटर कमिशन ने इस नहर को वायबल बताया है और आई०आई०टी० रूड़की के हैड ऑफ डिपार्टमैंट ने इसको वायबल होने का सर्टिफिकेट दिया है। इसके साथ-साथ वन तथ पर्यावरण विभाग से भी इसको क्लीयरेंस मिल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक में ही फैसला होगा। जिस तरह से हमारे बीच एकता बनी है उससे हमें बल मिलेगा। हमने सर्वसम्मति से जो रैजोल्यूशन पास किया है उससे हमें बल मिला है तथा इसके लिए मैं विपक्ष व सत्ता पक्ष के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं श्री अनिल विज जो बिना बात के ही वाक-आउट कर जाते हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि जब ये इंडियन नैशनल लोकदल के साथ थे तो—

पहले उनमें इक अदा थी, नाज था, अन्दाज था,
रूठना अब तो इनकी आदत में शामिल हो गया।

ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है उसके बावजूद भी बात-बात में वॉक-आउट कर जाना गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और न ही अर्थशास्त्र का कोई छात्र हूं लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने विश्व की सबसे बेहतरीन सेना में अधिकारी के रूप में काम किया है और अब राज्य की वित्तीय स्थिति में भली भांति परिचित हूं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा व यू०पी०ए० की

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी जी तथा मुख्य मंत्री जी ने मुझे जो वित्त विभाग का जिम्मा दिया है उसको मैं अपनी कड़ी मेहनत और लगन से निभाने की कोशिश करूंगा तथा हरियाणा को विकास के पथ पर ले जाऊंगा। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि —

कभी वक्त बदला तो बदलेगा मौसम,
यही आस लेकर मैं चलता रहा हूँ।

हमारी कोशिश रहेगी कि वक्त भी बदलेगा और सफलता के नये आयाम भी स्थापित होंगे। इस प्रकार से हम अपनी सरकार को चलायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सवाल है वह वर्ष 2009-10 के दौरान करंट प्राइसिज पर 19.2 परसैंट है जिसमें कि 9 परसैंट की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से जो हमारी ग्रोथ है वह करंट प्राइसिज पर लगभग 18.2 परसैंट है जिसमें कि 9.9 परसैंट की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है। वह वर्ष 2010-11 के दौरान करंट प्राइसिज पर 17.2 परसैंट है तथा कंस्टैंट प्राइसिज पर 7.2 परसैंट बढ़ी है। इसकी ग्रोथ 16.3 परसैंट थी और करंट रेट 8.2 परसैंट है। इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे कि मैल्ट डाउन के कारण 2008-09 में जो हमारी परसैंटेज ऑफ इन्क्रीज 7.2 परसैंट थी वह 2009-10 में बढ़कर 8.2 परसैंट हो गई है। इसी प्रकार से जो हमारी पर-कैपिटा इन्कम है वह 92327 लाख रुपये है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेवैन्यू डैफिसिट की बात है वह हमने 4458.38 करोड़ के तौर पर रखा था क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बाकायदा हमने 8 परसैंट और 10 परसैंट के हिसाब से डी०ए० की इन्सटालमैन्ट्स दी हैं। इसके अलावा हमने रेवैन्यू डैफीसिट कम रखा है। वर्ष 2011-12 में रेवैन्यू डैफीसिट घटकर 2660.68 करोड़ रुपये रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी इकोनोमी ग्रो कर रही है। हमारा रेवैन्यू डैफीसिट कम होता जाएगा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जो हमारे सैल्ज टैक्स की परसैंटेज ऑफ ग्रोथ है वह वर्ष 2004-05 के मुकाबले में 114.07 परसैंट, एक्साइज ड्यूटी में 58.4 परसैंट, गुड्ज एवं पैसेंजर टैक्स में 32.37 परसैंट, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन में 161 परसैंट रही है। जो नोन टैक्स का टोटल रेवैन्यू है वह 87.24 परसैंट रहा। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि वर्ष 2011 में हर क्षेत्र में ग्रोथ रही चाहे वह सेल्ज टैक्स का क्षेत्र हो जिसमें 15.37 परसैंट ग्रोथ है और चाहे एक्साइज ड्यूटी का क्षेत्र हो जिसमें 14.63 परसैंट ग्रोथ है। जो टोटल रेवैन्यू कलैक्शन है वह सैल्ज टैक्स में 14100 करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने मुझसे पूछते हुए कहा था कि रेवैन्यू कहां से आएगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सैल्ज टैक्स में 14100 करोड़ रुपये की रेवैन्यू कलैक्शन है, एक्साइज ड्यूटी में 2400 करोड़ रुपये, गुड्ज एवं पैसेंजर टैक्स में 425 करोड़ रुपये, स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 435 करोड़ रुपये, स्टैम्प ड्यूटी में 2350 करोड़ रुपये और व्हीकल्ज टैक्स में 515 करोड़ रुपये की कलैक्शन रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जो परसैंटेज ऑफ ग्रोथ है वह ज्यादा रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फाईनेंस मिनिस्टर केवल यही स्पष्ट कर दें कि क्या आप इस बजट सैशन के बाद कोई और नया टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? इनकी पुरानी परम्परा तो यही रही है कि बजट के बाद इन्होंने बहुत टैक्स लगाए हैं। दो बातों के बारे में स्पष्ट कर दें। एक तो ये यह कह दें कि बजट के बाद ये कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और दूसरी बात ये यह बता दें कि जो कर्जा बढ़ता जा रहा है उसको सरकार कैसे अदा करेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव : ठीक है, मैं बता रहा हूं। स्पीकर साहब, यह हाईपोथीटिकल क्वैश्चन है। सरकार समय-समय पर अपना कार्य करती है आज के दिन हमने यह बजट पास करना है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बजट की बात है इसे ये ऐसे ही टाल नहीं सकते हैं। इनको इस बात के लिए स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले भी बजट के बाद बहुत टैक्स लगाए थे। हरियाणा की जनता यह चाहती है कि क्या आप इस बार भी बजट पास करने के बाद फिर से लोगों पर टैक्स लादने जा रहे हो या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, ये ऑन दि फ्लोर ऑफ दी हाउस कह दें कि हम कोई नया टैक्स बजट के बाद नहीं लगाएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : जो आज हमने बजट पास करना है वह टैक्स फ्री बजट है। आगे की बात हम आगे देखेंगे, समय आने पर देखेंगे। (विघ्न)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, क्या अगले पांच साल की कोई गारंटी ले सकता है, क्या चौटाला साहब गारंटी ले सकते हैं? (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please maintain the decorum of the House.

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : स्पीकर सर, एक पल की खबर नहीं तो कल का किस को क्या मालूम कि क्या होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या तुम्हें पता था कि तुम मंत्री बनने जा रही हो लेकिन आप दोबारा मंत्री बनकर आयी हो या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हमारी सरकार में हमारा जो विशेष फोकस रहा है वह कैपीटल एक्सपैंडीचर के ऊपर रहा है। आप देखेंगे कि वर्ष 2005 में पावर सैक्टर में 169.8 परसैंट, एजुकेशन सैक्टर में 109 परसैंट, इरीगेशन सैक्टर में 137.6 परसैंट, सोशल सैक्टर में 134.3 परसैंट और हैल्थ सैक्टर में 99.8 परसैंट का इजाफा था।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, 12 कम्पनियों जैसे बूडैल, अमरटैक, लोनको और करमचम आदि के साथ पावर परचेज कम्पनियों का एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि उनसे बिजली कब आएगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल थोड़े ही है, ऐसे काम नहीं चलेगा।

Mr. Speaker : Majra Ji, can you ask a question? You can't.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बी० एंड आर० सैक्टर में इजाफा रहा है वह 205.3 परसैंट रहा है और एग्रीकल्चर सैक्टर में 248.9 परसैंट का इजाफा रहा है। इसी प्रकार से रूरल डिवैल्पमैंट में 339.8 परसैंट वृद्धि हुई है। 2000-05 में इतना हमारा इजाफा हर सैक्टर में रहा

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

है। 2011-12 में हमारी जो परसैंटेज ऑफ ग्रोथ है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हैल्थ का क्षेत्र हो, हर जगह इन्क्रीज है। वेजिज में 2004-05 में 4560.33 की राशि थी, जो अब बढ़कर 13538 हो गयी है। इस प्रकार 196.7 परसैंट सैलरी में इजाफा हुआ है। हमने सारी कठिनाइयों का सामना करते हुये भी काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सैलरी बिल में 161 परसैंट का इजाफा हुआ और पैंशन में 260.3 परसैंट का इजाफा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि टोटल 11 हजार करोड़ रुपये हमने खर्च किए हैं। 2008-09 और 2011 में **on account of implementation of 6th Pay Commission only on salaries and arrears** में जो हमारा प्लान साइज है वह 20358 करोड़ था, इसमें हमारा इजाफा 18.92 परसैंट है। जो प्लान ऐक्सपैंडीचर था उसमें इनके समय में टोटल एवरेज इन्क्रीज 4.3 परसैंट थी जबकि हमारे समय में इसकी ग्रोथ 35.7 परसैंट रही है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनके समय में यानी 2000-2004 में 816.79 करोड़ रुपये खर्च हुआ और हमारे समय में यानी 2011-12 में 4364.33 करोड़ रुपये खर्च हुआ। इसमें भी 434.3 परसैंट की वृद्धि है। उसी प्रकार से प्लान आउट ले में 35.5 परसैंट इजाफा है। डैब्ट लायबिलिटी की जहां तक बात है, वैसे तो संपत सिंह जी ने उसके बारे में बता ही दिया था कि इनके समय में यह 68.4 परसैंट रही थी जबकि हमारे समय में यह 49.3 परसैंट रही। इन्होंने कहा कि हमारा डैब्ट 52701.9 करोड़ है। यह सही है। 13वें वित्त आयोग की रिकमंडेशन के तहत जो हमारा आउट डैबिट है वह जी०एस०डी०पी० के परसैंटेज में 22.4 परसैंट है जिसकी कुल राशि 69500 करोड़ रुपये बनती है। इस प्रकार से यह विद इन दि परमिसिबल लिमिट हमने लिया है। जो हमने खर्च किया है। इनके समय में लोन 26073.07 करोड़ रुपये लिया गया जबकि हमने 18547.57 करोड़ रुपये लोन लिया है। हमने जो लोन लिया **within the permissible limit** लिया है। जो लोन लिया है उसमें से भी 18995.12 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपैंडीचर पर अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है। यह अमाउंट जितना लोन लिया, उससे कम है और उसे भी इन्फ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए खर्च किया है। पे और पैंशन के लिए हमारी सरकार ने लोन नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, जो अनिल विज ने कहा कि कौन सा नया काम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यमुनानगर, लाडवा और करनाल तक के 54 किलोमीटर लम्बे चारमार्गी मार्ग को 435 करोड़ रुपये की लागत से बी०ओ०टी० बेसिस पर बनाने के लिए योजना आयोग को केस भेजा गया है। (शोर एवं व्यवधान) इसके अलावा कौशल्या डैम हमने बनाया है, रोहतक, फरीदाबाद और रोज-का-मेव में तीन आई०एम०टी० बनाने का कार्य विभिन्न चरणों में है। पूरे हरियाणा की जितनी भी हमारी गलियां हैं उनको बनाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। 6764 गांव हैं, हर गांव में 10 लाख रुपये की राशि दे रहे हैं। इसके अलावा जो तीन मैडीकल कालेजिज खोले जा रहे हैं, उनमें से एक मेवात में भी खोला जा रहा है जबकि मोहम्मद इलियास जी कहते हैं कि हमारे मेवात में काम नहीं हुआ। करनाल में कल्पना चावला के नाम से कालेज बना रहे हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : It is the sense of the House that the time of the Sitting of the House be extended for half an hour.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for half an hour.

वर्ष 2011-2012 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

17.00 बजे **कैप्टन अजय सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी नेता ने यह कहा कि जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है तब से हरियाणा में डिवैल्पमेंट नहीं हो रही है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे कस्बे हैं जैसे धारूहेड़ा है, बावल है, पलवल है, कैथल है, घरौण्डा है, तरावड़ी है, नरवाना है, इन्द्री है, महेन्द्रगढ़ है, रतिया है और दादरी है यहां पर हमारे प्राईवेट डिवैल्पर्ज भी आये हैं और हुडा ने भी सैक्टर काटे हैं। जबकि इससे पहले पिछली सरकार के समय में ये फरीदाबाद और गुड़गांव तक सीमित रहते थे। हमारी सरकार आने के बाद छोटे-छोटे कस्बों पर भी ध्यान दिया गया है। वर्ष 2005 की जो नीति थी उसकी बदौलत इण्डस्ट्रीज में 53000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। इन्होंने यह कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट नहीं हुई है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 93000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट का हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। सी०एम०आई०ई० और एशोचैम की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती उसके आंकड़े भी मैं बता रहा हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो राजीव गान्धी एजूसिटी है उसके बारे में भी इन्होंने आलोचना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि इतना बढ़िया कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजीव गांधी एजूकेशन सिटी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एजूकेशन हब बनाया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो राजीव गान्धी एजूकेशन सिटी है हम उसको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्डवर्ड यूनिवर्सिटीज के पैटर्न पर डिवैल्प कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माईनिंग के बारे में भी बात कही। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 में माईनिंग से कुल 536 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि वर्ष 2005-2006 में 1005 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह डिफरैंस है। उसी प्रकार से हमारे समय में इसकी ओपन ऑक्शन हुई है। इन्होंने एजूसैट के बारे में अपनी बात कह दी है। इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्ज के बारे में भी बात की है कि आंगनवाड़ी वर्कर्ज के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी वर्कर्ज के लिए पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था के लिए सरकार वर्ष 2011 में 176.40 लाख रुपये खर्च कर रही है। आंगनवाड़ी सैंटर्ज में टॉयलैट भी बनायेंगे और शौचालय भी बनायेंगे। (विघ्न) इसके अलावा इन्होंने यह भी कह दिया कि बहुत सारी पी०एस०यूज० हैं जिनको हमने मना कर दिया कि हम आपकी गारण्टी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, केवल दो हमारे इंस्टीच्यूशंज हैं जैसे एच०एस०आई०आई०डी०सी० और हुडा जो प्रोफिट मेकिंग पी०एस०यूज० हैं, हमने यह कहा है कि स्टेट गवर्नमैंट इनको गारण्टी इसलिए दे रही है क्योंकि उस पर दो प्रतिशत लैवी लगती है। जिससे पी०एस०यूज० को नुकसान है। यह जो भी हमने किया है, स्टेट के हित में ही किया है। अध्यक्ष महोदय, फ्लड की बात करें तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर इन 6 जिलों में काफी फ्लड आया। करीबन हमारे 10 जिलों यमुनानगर, पलवल, रोहतक, भिवानी, झज्जर, पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद और मेवात में भी बाढ़ से काफी डैमेज हुआ। उसके लिए स्पैशल गिरदावरी हम करवा चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मुआवजे के लिए हमारे नार्म्ज रिवाइज्ड हो गए हैं। ये नार्म्ज हमने हाल ही में जुलाई, 2010 में रिवाइज किए हैं। व्हीट क्रॉप के 26 परसैंट से 50 परसैंट नुकसान पर हमने 3500 रुपये मुआवजा दिया है। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार एक बात इन्होंने रखी कि आपने मुआवजा बहुत कम

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

दिया है। इन्होंने 15 रुपये की या इस प्रकार से मुआवजा की बात रखी है। सब-तहसील गांव जठियाना की बात है। वहां पर टोटल जमीन 4 कनाल 16 मरला थी और उस जमीन के को-शेयरर्स 60 थे। अध्यक्ष महोदय, आप हिसाब लगा सकते हैं कि मुआवजा कितना बनेगा। हमारी सरकार के नार्म्ज एकड़ के हिसाब से हैं। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वे मरले के हिसाब से दिए हैं। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उससे इन्होंने हाउस को मिसलीड करने की बात की है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्होंने एक बात और आंगनवाड़ी वर्कर्स की रखी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का 5 हजार रुपये का ओनरेरियम जो हमारी सरकार ने किया है वह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी आंगनवाड़ियों में अटैंडेंस बेहतर हुई है। हमने बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर खोले भी हैं। हमने आंगनवाड़ियों में बहुत से फर्नीचर वगैरह दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, फूड प्रोडैक्शन के बारे में इन्होंने कहा कि हमारा प्रोडैक्शन कम हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि 1999 में इनके समय में फूड प्रोडैक्शन 130.65 मीट्रिक टन थी, 2004-05 में भी फूड प्रोडैक्शन 130.57 मीट्रिक टन रही यानि स्टैटिक रही जबकि हमारे समय में यह बढ़कर 153.58 मीट्रिक टन हुई यानि इन्क्रीज हुआ है। इनका यह कहना है कि हमारी फूड प्रोडैक्शन इन्क्रीज नहीं कर रही है, यह ठीक नहीं है। इनके समय में फूड प्रोडैक्शन 5 साल तक स्टैटिक रही। हमने तो प्लानिंग कमीशन में यह बात भी उठाई थी कि हीट टोलरैंट वैराइटी ऑफ व्हीट हमें दें ताकि हमारी प्रोडैक्टिविटी और बढ़ सके। इसी प्रकार जो राइस की प्रोडैक्शन है वह भी इन्क्रीज हुई है। 1999-2000 में राइस की प्रोडैक्टिविटी 2385 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी जबकि 2009-10 में यह 3008 किलोगाम प्रति हेक्टेयर हो गई यानि इन्क्रीज हुई है। उसी प्रकार से राइस की प्रोडैक्टिविटी मीट्रिक टन में भी इन्क्रीज हुई है। व्हीट प्रोडैक्शन भी हमारी इन्क्रीज हुई है। 2008-09 में व्हीट प्रोडैक्शन सबसे ज्यादा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात इन्होंने मनरेगा के बारे में की कि इस स्कीम में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। एक मामला अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का था जिसके बारे में अनिल विज जी कई बार कहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि बकायदा इसकी इन्कवायरी हुई है और उसमें कुछ इररैगुलरटीज पाई गई हैं। इसमें कुछ ब्लैंक जॉब कार्ड पाए गए और कुछ दूसरी वायलेशंज पाई गई हैं। मिनीमम 50 परसैंट मैंडेटरी ग्राम पंचायतों के काम के नार्म्स मेंटेन करने की जो बात कही गई है उसमें भी फोरेस्ट डिपार्टमैंट ने इन्कवायरी की है। उसमें कुछ प्रोसीजरल लैपसिज पाए गए। उसमें प्लांट के साइज और कुछ डिस्टैंस के बारे में पाया गया। लेकिन इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं है कि पौधे बिल्कुल लगाए ही नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, वहां पौधे लगाए हैं। फिर भी इसके बारे में विजीलैंस ने इन्कवायरी शुरू कर दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Vij Sahib, I have not permitted you to speak. Nothing is to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें फोरेस्ट डिपार्टमैंट ने कहा था कि अफसर की गलती नहीं है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी विजीलैंस इन्कवायरी करवाओ। इस केस की बकायदा विजीलैंस इन्कवायरी करवा रहे हैं। कोई भी दोषी व्यक्ति जो गलत काम करेगा उसको पूरी सजा दी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

गांव शिमला मुलाना, जिला पानीपत में है जहां मनरेगा में गड़बड़ी पाई गई और कार्यवाही की गई है। वहां ग्राम सचिव को सस्पैंड किया गया है और रविकांत, एडीशनल ब्लॉक आफिसर तथा श्री बलराज कौशिक, ग्राम रोजगार सहायक को टर्मीनेट किया गया है। इसी तरह से अंबाला के अंदर भी इन्क्वायरी की गई है। अंबाला के अन्दर ग्राम गाजीपुर में मनरेगा के तहत सरपंच मूर्ति देवी को दोषी पाया गया है। उसके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हो गई है और उससे पैसे की रिकवरी भी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से जिला भिवानी के गांव बेथन में अनियमितता मनरेगा में पाई गई है। वहां भी एफ०आई०आर० दर्ज करवा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा में या किसी भी दूसरी जगह जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं उनमें हमने कार्यवाही की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप लोग आपस में बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपने मेरी परमिशन ली है। विज साहब, प्लीज आप बैठें। आप मेरी परमिशन के बगैर ही बोलना शुरू कर देते हैं। Nothing is to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अम्बाला के बारे में भी बता दिया है कि अंबाला के अंदर ग्राम गाजीपुर में मनरेगा के तहत सरपंच मूर्ति देवी को दोषी पाया गया है। उसके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज हो गई है और उससे पैसे की रिकवरी भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने कहा कि हांसी बुटाना लिंक कैनाल के बनाने से कैथल और गुहला चीका के अंदर बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। मैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां गये थे। हकीकत यह है कि बाढ़ के समय में इस नहर ने बहुत पानी लिया जिससे लोग बाढ़ से भी बचे और जमीन की रिचार्जिंग का काम भी हुआ। हमारे विपक्ष के साथी अरोड़ा जी ने बीबीपुर लेक के बारे में जिक्र किया था। इस बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि वह 5000 एकड़ पूरा एरिया है उसमें 500 एकड़ जमीन किसानों से बात करके ली गई है। वहां 4-5 एकड़ चौड़ाई, 10 फिट गहराई करके लेक बनायेंगे। इसके लिए करीबन 117 करोड़ रुपये का बजट में प्रोवीजन किया गया है। मैं समझता हूं कि यह लेक अपने आप में एक ऐतिहासिक होगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कोटला झील की बात है। कोटला झील की टोटल स्कीम 178 एकड़ की है और जिस प्रकार की हमारी स्कीम है उसी हिसाब से बनेगी। (विघ्न) विपक्ष के साथी अपने दिमाग से यह निकाल दें कि यह झील नहीं बनेगी। इसके लिए हमने बजट में पैसे का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, ये संतुष्ट ही नहीं होते। (विघ्न) हमारी सरकार ने वाटर बॉडीज के बारे में चाहे भिंडावास लेक हो, मसाणी बैराज हो, ओटू झील हो, हमने हमेशा इनको बड़ी प्राथमिकता दी है। यह साल हम 'वाटर कंजर्वेशन ईयर' के रूप में मना रहे हैं। विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमने ओटू झील के ऊपर कुछ नहीं किया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने ओटू झील के लिए 67 करोड़ रुपये की लागत की स्कीम बनाई है। ओटू झील से 90 दिन तक सिंचाई हुई जबकि इनके समय में एक दिन भी सिंचाई नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि सरकार पानी की चोरी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम 8 पुलिस स्टेशन कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, जींद, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार और सिरसा में कांस्टीच्यूट कर रहे हैं जो बिजली और पानी की चोरी को रोकेंगे। इनमें टोटल 355 का स्टाफ होगा जिसमें 4 डी०एस०पी०, 1 एस०पी०, 1 डी०आई०जी० और 1 ए०डी०जी०पी० होगा। इसके अतिरिक्त स्पैशल चार्जिज की लोअर लिमिट पांच गुणा अनअथोराईज्ड पानी यूज करने वालों के लिए बढ़ा दी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

में विपक्ष के साथियों द्वारा दादुपुर-नलवी नहर का भी जिक्र किया गया है इस बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनावों को ध्यान में रखते दिनांक 16.11.2004 को दादुपुर-नलवी नहर की आधारशिला रखी थी लेकिन उस समय न तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली गई और न ही इस प्रोजैक्ट के लिए बजट में पैसा ही रखा गया। सर, सर्वप्रथम यह स्कीम सन् 1984-85 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में सत्तासीन थी, उस समय तैयार की गई थी लेकिन 30 साल तक किसी ने इस बारे में कुछ नहीं किया। जब इलैक्शन का समय आया उस समय श्री चौटाला ने इसके लिए महज एक पत्थर लगा दिया और लोगों को मुआवजे के रूप में 1984-1985 के मार्किट रेट के हिसाब से केवल मात्र एक करोड़ रुपये ही दिये। इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इसके ऊपर 151.85 करोड़ रुपये की लागत से इसके फेज़-1 को कम्पलीट किया (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded without my permission. Hon'ble Finance Minister, please continue.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो दादुपुर-नलवी प्रोजैक्ट है इससे प्रदेश का हित जुड़ा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded without my permission. (Interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि दादुपुर-नलवी नहर का फेज-I पूरा हो चुका है और फेज-II पर काम चल रहा है। जो फेज-I है उसकी बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 01 सितम्बर, 2009 को इनागुरेशन की गई। स्पीकर सर, यह प्रोजैक्ट प्रदेश के हित में बहुत महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट है जिसके लिए विपक्ष के साथियों को सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए न कि तरह-तरह से नुक्ताचीनी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में बजट भाषण पर बोलते हुए पॉवर सैक्टर के बारे में कुछ बातें रखी हैं। इन्होंने खेदड़ के पावर प्लांट का भी जिक्र किया है। इस पॉवर प्लांट के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि एच०पी०जी०सी०एल० ने अभी तक इसको अपने चार्ज में नहीं लिया है। शुरुआती तौर पर होने के कारण इसमें अभी कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे कि एक टैक्नीकल प्रॉब्लम 25.01.2011 को आई और उसके बाद 12.02.2011 को भी ऐसा ही हुआ। इस प्लांट की जो भी रिपेयर हुई उसका पैसा इसके कंट्रैक्टर मै० आर०एम० कम्पनी ने ही दिया यानि रिपेयर का सारा काम कंट्रैक्टर ने अपने खर्चे पर करवाया और सरकार का इस मामले में कोई फाईनैंशियल नुकसान नहीं हुआ और न ही सरकार के ऊपर कोई फाईनैंशियल बर्डन पड़ा। एक बात माननीय सदस्य ने इस प्लांट के बैरिंग के खराब होने की कही। इस बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कोई काम शुरू होता है तो कुछ आधारभूत प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। शुरू-शुरू में जो टैक्नीकल प्रॉब्लम्स आती हैं वे इस प्रोजैक्ट में भी हैं। हम भी इस बात को मानते हैं लेकिन इससे

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जो भी रिपेयर का काम हुआ उसे कम्पनी ने अपने खर्चे पर करवाया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : Krishan Lal Ji, let him complete.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने पानीपत पॉवर प्लांट के कोर हैंडलिंग प्लांट के बारे में भी कहा है। सर, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो कम्पनी है इसका नाम टैप्रो है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल पंवार : स्पीकर सर, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Yes, Mr. Panwar, what do you want to say?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसा कि मंत्री जी ने खेदड़ पॉवर प्लांट के बारे में बैरिंग की खराबी से सम्बन्धित बात बताई वह प्राईमरी हैलीएटर है। यह कोई सैकड़ों रुपये का काम नहीं है बल्कि इसकी रिपेयर पर करोड़ों रुपये का खर्च आता है। आप किसी भी थर्मल पॉवर प्लांट को चैक करवा लीजिए आप पायेंगे कि 15 से 20 साल तक किसी भी पॉवर प्लांट में प्राईमरी हैलीएटर कभी भी फेल नहीं हुआ। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह घटिया क्वालिटी का यूज किया गया है जिससे यह बार-बार फेल हो रहा है। (विघ्न)

Mr. Speaker : I am delighted of your technical knowledge. Thank you Mr. Panwar, now, you may sit-down. Hon'ble Finance Minister, please continue.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी रिपेयर पर सारा पैसा कंट्रेक्टर का लगा है और सरकार का एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। सरकार का कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है।

Mr. Speaker : But I am surprised that he has so much knowledge about this.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैप्रो कम्पनी का सवाल है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो टैप्रो कम्पनी है इसमें काफी कमियां पाई गई हैं और उनकी इनऐफिशियेन्सी की वजह से 10.85 करोड़ रुपये रेलवे में डैमेज हुआ जिसके कारण हमने उनकी 6.19 करोड़ रुपये की पेमैंट रोक दी है। इसके अलावा ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमने उनको नोटिस दे दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर कोई डायरैक्ट गलत काम करता है तो वह अपने रिस्क एण्ड कॉस्ट पर करेगा। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि कोयले की स्टॉक पोजीशन बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर 21 दिन का कोयले का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास केवल 7 दिन का स्टॉक बचा है। खेदड़ पावर प्लांट में हमारे पास 6 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप कौन से थर्मल पॉवर प्लांट में रहे हैं?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी थर्मल पावर प्लांट में नहीं रहा हूं लेकिन मुझे इसकी जानकारी है। मंत्री जी जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। नॉर्म के हिसाब से 28 दिन का कोयले का स्टॉक होना जरूरी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने उस कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। उसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी है तथा जो भी गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम किसी को बचायेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में कहा है। इनकी यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास कुल स्टॉक 6 दिन का था। हमारे पास कुल ऐलोकेशन 55.50 लाख टन पर एनम होना चाहिए लेकिन हमें जो मिला वह इसका 50 परसैंट मिला है। यह 4.62 लाख टन पर मंथ होना चाहिए लेकिन हमें 2.10 लाख टन पर मंथ मिल रहा है। इसकी जो एवरेज ग्रोस क्लोरिफिक वैल्यू है वह 2800 Kcal/Kg है जो कि 4000 Kcal/Kg होनी चाहिए। स्पीकर सर, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम 55.5 लाख टन का एक प्राईवेट वॉशिंग प्लांट लगा रहे हैं। इसी प्रकार से हम 6.5 लाख टन इम्पोर्टिड कोल खरीद रहे हैं। इससे इसकी एवरेज ग्रोस क्लोरिफिक वैल्यू भी सुधरेगी और ऐश कंटैंट डाउन आयेंगे तथा इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अगर कोल इंडिया लिमिटेड ने हमें खराब कोयला दिया है तो हम इसको इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से एच०पी०जी०सी०एल० ने सिंगरेणी कालियरीज नाम की कम्पनी के साथ फरवरी, 2011 में राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्लांट के लिए 5 लाख टन उत्तम क्वालिटी का कोयला खरीदने का निर्णय लिया है जिसकी जी०सी०वी० 4300 Kcal/Kg है। अध्यक्ष महोदय, पूअर क्वालिटी का कोयला होने के बावजूद खेदड़ पावर प्लांट की जो हमारी उपलब्धि है वह 68 प्रतिशत पी०एल०एफ० है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे विपक्ष के साथी बार-बार बात उठा रहे हैं कि रिलायन्स की कम्पनी को चेंज करने की अनुमति दे कर सरकार ने गलत काम किया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इनका समझौता डोंगफेंग इलैक्ट्रिक कारपोरेशन चाईना से हुआ था। उसमें एक बी०टी०जी० यानि कि ब्वायलर टर्बाईन जनरेटर लगवाने का समझौता हुआ था लेकिन उनका समझौता नहीं जम पाया। उसके बाद हमारी सरकार ने उनको कम्पनी बदलने की परमिशन दी तथा संघाई इलैक्ट्रिक कारपोरेशन के साथ उनका एग्रीमैंट हुआ। यह एक बहुत ही अच्छी फर्म है और भारत सरकार के माध्यम से 10 हजार मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स पूरे भारत में सैट-अप करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके साथ एग्रीमैंट होने के बाद डोंगफेंग कम्पनी हाई कोर्ट में भी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी गई लेकिन वहां पर इनकी पैटीशन डिसमिस हो गई लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विपक्ष के साथी बार-बार इसी मामले को उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारे यमुनानगर के थर्मल पॉवर प्लांट की दोनों यूनिटों की पी०एल०एफ० 93.25 प्रतिशत तथा 90.39 प्रतिशत है जो कि गर्व की बात है। इसी प्रकार से फरवरी, 2011 में पी०एल०एफ० 96.16 प्रतिशत और 78.98 प्रतिशत है तथा 10 मार्च, 2011 तक यूनिट 1 और यूनिट 2 की पी०एल०एफ० क्रमशः 98.34 परसैंट और 92.59 परसैंट रही है जो कि गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने लाईन लॉसिज की बात की है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनके समय में लाईन लॉसिज 39.8 परसैंट थे जिसको घटाकर हमने 29.05 परसैंट कर दिया है। हमारे टाईम में लॉसिज कम हुए हैं। हमारा जो 600 मैगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट यमुनानगर का चालू हुआ है, 1200 मैगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट खेदड़ में बना है और 500 मैगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट झाड़ली में बना है उसके कारण जो हमारी शॉर्ट टर्म परचेज है, यह कम हुई है जबकि इनके समय में जो शॉर्ट टर्म परचेज हुआ करती थी वह बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। इनके समय में जो पावर जैनरेशन रही है वह 2004-05 में 1547 मेगावाट रही है और हमारे टाईम में यह बढ़कर 3230.8 मेगावाट हो गयी है इसलिए इसकी तो इनको सराहना करनी चाहिए। हमारे खेदड़ और झज्जर में महात्मा गांधी के पावर प्लांट्स भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगे जिसके बाद हम पांच हजार

मेगावाट के बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो पावर टैरिफ के बारे में इन्होंने कहा है कि यह हमने बढ़ा दिया। यह हम नहीं बढ़ाते हैं बल्कि जो हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन यानी एच०ई०आर०सी० है वह समय-समय पर यह रेट बढ़ाता है जबकि ये सरकार की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनके समय में एवरेज टेरिफ इंक्रीज 15 परसैंट थी which has come to nearly 1.4 percent. और मैं समझता हूं कि as compared to that time हमारे टाईम में केवल 6 परसैंट इंक्रीज है जबकि इनके टाईम में यह 15 परसैंट थी।

कर्नल रघबीर सिंह : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आपकी परमिशन से मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि एच०ई०आर०सी० रेट बढ़ाती है। मैं मानता हूं क्योंकि मैं भी एच०ई०आर०सी० का चेयरमैन रहा हूं। यह रेट एच०ई०आर०सी० बढ़ाती है लेकिन हमेशा से विभाग की तरफ से ही इसकी डिमांड आती है। उसकी हियरिंग होती है और उसके बाद ही डिसकोम डिमांड करती है क्योंकि उसका डैफीशिट रह जाता है इसलिए उसके ऊपर वह यह रेट बढ़ाती है। जो सरकार मांगती है वही वह देते हैं। अपनी तरफ से एच०ई०आर०सी० कोई रेट नहीं लगाती है।

श्री अध्यक्ष : आप भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है।

कर्नल रघबीर सिंह : सर, इन्होंने यह नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि एच०ई०आर०सी० रेट बढ़ाती है और मैंने यह कहा है कि एच०ई०आर०सी० कोई रेट नहीं बढ़ाती है।

श्री अध्यक्ष : रेट तो एच०ई०आर०सी० बढ़ाती है।

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लीयर कर देता हूं। सरकार यह रेट नहीं बढ़ाती है। एच०ई०आर०सी० हियरिंग के बाद ही टैरिफ के बारे में डिसीजन करती है। वर्ष 2001 के बाद से यह टैरिफ दस साल तक नहीं बढ़ाया है। अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो 1996-98 में टैरिफ की बढ़ोत्तरी 6 परसैंट हुई थी। दस साल में 15 परसैंट के हिसाब से इजाफा यदि प्रति वर्ष लगाया जाए तो 1.4 परसैंट होता है। हियरिंग के बाद एच०ई०आर०सी० ही रेट का निर्धारण करती है। सरकार इसको बढ़ावा नहीं देती है। सरकार तो तकरीबन 2900 करोड़ रुपये से भी ज्यादा सबसिडी किसानों के लिए दे रही है। रेट को बढ़ाने के लिए सरकार ने सहमति नहीं दी है। सरकार ने तो कहा है कि किसान के लिए हम सबसिडी देंगे। सरकार ने उनको टैरिफ नहीं बढ़ाने के लिए राय दी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट की बात है मेरे पास 73 कम्पनियों के नाम हैं। अगर आप कहें तो मैं इनको सदन के पटल पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप इन्हें सदन के पटल पर रख दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बता रहा हूं कि चेयरमैन, एच०ई०आर०सी० ने 5.10.2010 को एक लम्बी चिट्ठी सरकार को लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि डी०एच०बी०वी०एन० और यू०एच०बी०वी०एन० बंद होने के कगार पर है। यह कम्पनियाँ कभी भी बंद हो सकती हैं। यह चिट्ठी रैगुलेटरी कमीशन की सरकार के पास आयी है। इस चिट्ठी की प्रति चीफ सैक्रेटरी, पी०एस० सी०एम०, पावर, फाईनैंस कमीशन तथा कम्पनियों के एम०डीज० को भेजी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, यह बात तो आप दो तीन दिन से कह रहे हैं इसलिए अब आप इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं?

श्री औम प्रकाश चौटाला : हाँ, मैंने यह बात कही थी लेकिन फिर ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं यह कह रहा हूं कि ये तथ्यों पर आधारित बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बड़े विस्तार से पहले ही बता दिया था इसलिए यह बार बार रिपीट करने की बात नहीं है।

श्री औम प्रकाश चौटाला : मंत्री जी ने खुद इस बारे में कहा है यह चिट्ठी कह रही है कि आपकी दोनों कम्पनियां बंद होने के कगार पर हैं। बहुत ज्यादा लौसिज है लेकिन ये उनको मानकर नहीं चल रहे हैं।

Mr. Speaker : Capt. Sahib, How much time you are going to take to complete it?

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, मैं दस मिनट और लेना चाहूंगा।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : O.K. Is it the pleasure of the House that the time of the Sitting be extended for 10 minutes.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended for 10 minutes.

वर्ष 2011-2012 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ये लाईन लौसिज की बात कर रहे हैं। जो हमारे लाईन लौसिज हैं वह इनके समय के मुकाबले बहुत कम हुए हैं। इनके समय में लाईन लौसिज 36 परसैंट थे और हमारे टाईम में यह 29.5 परसैंट है। यह तो रिकार्ड की बात है। मेरे पास भी यह रिकार्ड है पता नहीं, ये कहां से ले आए हैं। लाईन लौसिज पहले से कम हुए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : विपक्ष के नेता ने यह कहा कि यहां से कंपनियां पलायन कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बार-बार 73 कम्पनियों के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट 9428.96 करोड़ रुपये का हुआ है। (विघ्न) सदन में गलत बयानी करना अच्छी बात नहीं है। जो हमारी रिसीट्स हैं वह 12928 करोड़ की हैं। उन कंपनियों के नाम मैं सदन की टेबल पर रख दूंगा। बोलते हुए यह भी कहा गया कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सर्विस सिलैक्शन कमीशन ने 32721 अपॉइंटमैंट्स कैटेगरीवाइज की हैं। इन्होंने अपने समय में नौकरियां बंद कर दी थीं और कर्मचारियों की रिट्रैंचमैंट भी की गई थी। संपत सिंह जी भी इस बारे में जानते हैं। हमने आकर एम०आई०टी०सी० के कर्मचारियों को नौकरी में वापस लिया और 1700 पुलिस कांस्टेबल्स निकाले गए थे, मुख्यमंत्री जी उनको दोबारा लगाने की सोच रहे हैं। चाहे उन्हें बेलदार के रूप में वापस लें लेकिन उनको नौकरी पर लेने की बात सोची जा रही है। (विघ्न) माईंस के बारे में वैसे तो सारा बता दिया है फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि माईंस में इनकी सरकार के समय

में 2000 से 2004 तक कलेक्शन 536.07 करोड़ रुपये की थी और हमारे समय में 2010-11 में 1005.48 करोड़ रुपये की है। अध्यक्ष महोदय, माईस अब खुल चुकी है। अशोक अरोड़ा जी ने बोलते हुए यह भी कहा कि डी०ए०पी० खाद की कमी है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन डी०ए०पी० की कोई शॉर्टेज नहीं है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी नहीं है। कोई ब्लैक मार्किटिंग भी नहीं हुई है। हां, यह जरूर है कि जब कोई एजीटेशन होते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे राजस्थान में गुर्जर ऐजीटेशन हुआ था उस समय समस्या जरूर आई थी। अब वह समस्या नहीं रही। जहां तक गैस्ट टीचर का मामला है हमने उनका 20 प्रतिशत वेतन बढ़ाया है और उनको मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव व अन्य बहुत सी सहूलियतें प्रदान कर दी हैं। लैक्चरर्स का वेतन बढ़ाकर 16200 रुपये प्रति माह की दर से किया है। मास्टर्स का वेतन 13500 रुपये प्रतिमाह किया है, 11000 रुपया वेतन लैंग्वेज टीचर्स का किया है और जे०बी०टी० टीचर्ज का वेतन 12000 रुपये किया है। इनका वेतन पहले 1.4.09 को बढ़ाया गया था लेकिन अब फिर मुख्यमंत्री जी ने 3 सितम्बर, 2010 को इनका वेतन बढ़ा दिया है।

आवाजें : इन गैस्ट टीचर्स को पक्का कर दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : हम वही काम कर सकते हैं जो कानून के दायरे में हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहा गया कि सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। यह बात सही है और इसका कारण यह है कि ओरिजिनल बजट के अंदर 6 प्रतिशत डी०ए० का प्रोविजन बजट में था लेकिन बाद में डी०ए० 18 परसैंट हो गया और उसका प्रोपर प्रोविजन बजट में था नहीं। इसके अलावा काफी सारी रिक्रूटमैंट्स भी हुई है। एजूकेशन डिपार्टमैंट में भी हुई है और दूसरे डिपार्टमैंट्स में भी हुई है। बजट ऑन लाइन करने के बाद कंटिजैंसी फंड के द्वारा जितने भी इम्प्लाईज हैं, उन सबकी सैलरी आज के दिन बकाया नहीं है। उन सबकी सैलरी अब दे दी है। एक इन्होंने यह कह दिया कि हमने एशियन गेम्स के लिए पैसा नहीं दिया। हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी से हमने इसके लिए 7.35 करोड़ रुपये की राशि लोन के रूप में ली थी वह पैसा भी हमने अपने ऐस्टीमेट्स के तहत वापस कर दिया है। संपत सिंह जी ने बात रखी थी कि 685 परसैंट की अर्बन डिवैल्पमैंट में इन्क्रीज क्यों हुई, सर, इसका कारण यह था कि जब रिसेशन आई थी तब लाइसैंस फीस मात्र 133.70 करोड़ रुपये रह गई थी अब वह बढ़कर 2010-11 में 1050 हो गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि इकोनोमी आगे बढ़ी हुई है, इसलिए ठीक हो गई है। बिजली जैनरेशन 2004-05 में 175 लाख यूनिट पर डे थी जो बढ़कर 395 लाख यूनिट पर डे हो गई है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने बहुत सारी आलोचनाएं भी की हैं। मैं समझता हूं कि बदलते परिवेश में हरियाणा राज्य के प्रत्येक वर्ग के नागरिक की तरफ हमने पूरा ध्यान रखा है और उनके जीवन को सुखद बनाने का प्रयास किया है। विपक्ष जो एक प्रहरी की भूमिका निभाता है और जो बजट की खामियां उजागर करता है उसके लिए मैं समझता हूं कि विपक्ष पूर्ण रूप से असफल रहा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छे सुझाव देने चाहिए थे जो इन्होंने नहीं दिए। बजट में सिंचाई, सड़क और कृषि पर हमने विशेष ध्यान रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो इलैक्ट होकर तो आये हैं लेकिन वे पूरे बजट के दौरान इस सदन में नहीं आये और पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर लेकर घूम रहे हैं। एक विधान सभा मैम्बर जिस हल्के से भी चुनकर आता है उसके लिए उन्होंने एक शब्द भी यहां आकर नहीं कहा। (शोर एवं व्यवधान) कमाल की बात है कि वे ट्रैक्टर लेकर घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमने इस बजट में पूरी कोशिश की है, यह आम आदमी का बजट है। हमने समाजिक क्षेत्र पर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

विशेष ध्यान दिया है चाहे वह सिंचाई सैक्टर हो या दूसरे सैक्टर्ज हों, हमने प्रदेश में चहुंमुखी विकास लाने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा :

जिन्दगी उर नूर होती जा रही है,
हर खुशी से चूर होती जा रही है।
वादियां खामोश से आई सदा,
बेबसी काफूर होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, हम बेबस नहीं हैं हमारे द्वारा बनायी गयी योजनाएं प्रदेश को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जा रही हैं। आने वाले वर्ष में हमारा प्रदेश चहुमुखी विकास और सफलता के नये मिसाल कायम करेगा। मैं विशेष रूप से हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने जो इस बजट के बारे में अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। हम कोशिश करेंगे कि हम प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर बढ़ायें। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।

वर्ष 2011-2012 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2011-2012 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding ₹ **31,19,55,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 1 - **Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding ₹ **60,27,25,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 2 - **Governor and Council of Ministers.**

That a sum not exceeding ₹ **122,20,26,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 3 - **General Administration.**

That a sum not exceeding ₹ **761,17,84,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 4 - **Revenue.**

That a sum not exceeding ₹ **117,85,18,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 5 - **Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding ₹ **3292,58,21,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 6 - **Finance.**

That a sum not exceeding ₹ **255,61,21,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 7 - **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding ₹ **1059,78,53,000 for revenue expenditure** and ₹ **1573,88,45,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 8 - **Building & Roads.**

That a sum not exceeding ₹ **6801,91,74,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 9 - **Education.**

That a sum not exceeding ₹ **222,46,92,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 10 - **Technical Education.**

That a sum not exceeding ₹ **82,94,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 11 - **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **10,02,35,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 12 - **Art & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **1368,18,20,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 13 - **Health.**

That a sum not exceeding ₹ **80,63,69,000 for revenue expenditure** and ₹ **500,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 14 - **Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **1114,55,03,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 15 - **Local Government.**

[श्री अध्यक्ष]

That a sum not exceeding ₹ **31,41,92,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 16 - **Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **67,54,63,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 17 - **Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **140,57,42,000 for revenue expenditure** and ₹ **42,75, 83,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 18 - **Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **339,77,94,000 for revenue expenditure** and ₹ **2,83,85,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 19 - **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **1850,04,05,000 for revenue expenditure** and ₹ **2,86,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 20 - **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **524,78,50,000 for revenue expenditure** and ₹ **50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 21 - **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **60,43,93,000 for revenue expenditure** and ₹ **20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 22 - **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **212,21,99,000 for revenue expenditure** and ₹ **4183,31,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 23 - **Food & Supplies.**

That a sum not exceeding ₹ **1226,62,66,000 for revenue expenditure** and ₹ **443,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 24 - **Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **78,16,35,000 for revenue expenditure** and ₹ **2,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 25 - **Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **15,07,59,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 26 - **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding ₹ **915,68,09,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 27 - **Agriculture.**

That a sum not exceeding ₹ **372,82,49,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 28 - **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding ₹ **24,82,79,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 29 - **Fisheries.**

That a sum not exceeding ₹ **233,35,58,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 30 - **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding ₹ **3,64,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 31 - **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding ₹ **1158,66,48,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 32 - **Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding ₹ **195,67,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **13,81,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 33 - **Co-operation.**

That a sum not exceeding ₹ **1272,20,43,000 for revenue expenditure** and ₹ **163,60,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 34 - **Transport.**

That a sum not exceeding ₹ **2,30,22,000 for revenue expenditure** and ₹ **20,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 35 - **Tourism.**

[श्री अध्यक्ष]

That a sum not exceeding ₹ **1621,86,47,000 for revenue expenditure** and ₹ **95,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 36 - **Home.**

That a sum not exceeding ₹ **24,52,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 37 - **Elections.**

That a sum not exceeding ₹ **925,81,39,000 for revenue expenditure** and ₹ **991,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 38 - **Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding ₹ **60,92,04,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 39 - **Information & Publicity.**

That a sum not exceeding ₹ **3342,83,82,000 for revenue expenditure** and ₹ **984,10,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 40 - **Energy & Power.**

That a sum not exceeding ₹ **24,30,05,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 41 - **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **244,64,74,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 42 - **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding ₹ **84,02,87,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 43 - **Prisons.**

That a sum not exceeding ₹ **37,98,73,000 for revenue expenditure** and ₹ **17,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 44 - **Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **956,90,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 45 - **Loans & Advances by State Government.**

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2011-2012 will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding ₹ **31,19,55,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 1 - **Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding ₹ **60,27,25,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 2 - **Governor and Council of Ministers.**

That a sum not exceeding ₹ **122,20,26,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 3 - **General Administration.**

That a sum not exceeding ₹ **761,17,84,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 4 - **Revenue.**

That a sum not exceeding ₹ **117,85,18,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 5 - **Excise and Taxation.**

That a sum not exceeding ₹ **3292,58,21,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 6 - **Finance.**

That a sum not exceeding ₹ **255,61,21,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 7 - **Planning and Statistics.**

That a sum not exceeding ₹ **1059,78,53,000 for revenue expenditure** and ₹ **1573,88,45,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 8 - **Building & Roads.**

That a sum not exceeding ₹ **6801,91,74,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 9 - **Education.**

[श्री अध्यक्ष]

That a sum not exceeding ₹ **222,46,92,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 10 - **Technical Education.**

That a sum not exceeding ₹ **82,94,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 11 - **Sports & Youth Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **10,02,35,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 12 - **Art & Culture.**

That a sum not exceeding ₹ **1368,18,20,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 13 - **Health.**

That a sum not exceeding ₹ **80,63,69,000 for revenue expenditure** and ₹ **500,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 14 - **Urban Development.**

That a sum not exceeding ₹ **1114,55,03,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 15 - **Local Government.**

That a sum not exceeding ₹ **31,41,92,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 16 - **Labour.**

That a sum not exceeding ₹ **67,54,63,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 17 - **Employment.**

That a sum not exceeding ₹ **140,57,42,000 for revenue expenditure** and ₹ **42,75, 83,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 18 - **Industrial Training.**

That a sum not exceeding ₹ **339,77,94,000 for revenue expenditure** and ₹ **2,83,85,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 19 - **Welfare of SCs & BCs.**

That a sum not exceeding ₹ **1850,04,05,000 for revenue expenditure** and ₹ **2,86,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 20 - **Social Security & Welfare.**

That a sum not exceeding ₹ **524,78,50,000 for revenue expenditure** and ₹ **50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 21 - **Women & Child Development.**

That a sum not exceeding ₹ **60,43,93,000 for revenue expenditure** and ₹ **20,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 22 - **Welfare of Ex-servicemen.**

That a sum not exceeding ₹ **212,21,99,000 for revenue expenditure** and ₹ **4183,31,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 23 - **Food & Supplies.**

That a sum not exceeding ₹ **1226,62,66,000 for revenue expenditure** and ₹ **443,50,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 24 - **Irrigation.**

That a sum not exceeding ₹ **78,16,35,000 for revenue expenditure** and ₹ **2,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 25 - **Industries.**

That a sum not exceeding ₹ **15,07,59,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 26 - **Mines & Geology.**

That a sum not exceeding ₹ **915,68,09,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 27 - **Agriculture.**

That a sum not exceeding ₹ **372,82,49,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 28 - **Animal Husbandry & Dairy Development.**

That a sum not exceeding ₹ **24,82,79,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 29 - **Fisheries.**

[श्री अध्यक्ष]

That a sum not exceeding ₹ **233,35,58,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 30 - **Forests & Wildlife.**

That a sum not exceeding ₹ **3,64,45,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 31 - **Ecology & Environment.**

That a sum not exceeding ₹ **1158,66,48,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 32 - **Rural & Community Development.**

That a sum not exceeding ₹ **195,67,00,000 for revenue expenditure** and ₹ **13,81,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 33 - **Co-operation.**

That a sum not exceeding ₹ **1272,20,43,000 for revenue expenditure** and ₹ **163,60,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 34 - **Transport.**

That a sum not exceeding ₹ **2,30,22,000 for revenue expenditure** and ₹ **20,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 35 - **Tourism.**

That a sum not exceeding ₹ **1621,86,47,000 for revenue expenditure** and ₹ **95,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 36 - **Home.**

That a sum not exceeding ₹ **24,52,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 37 - **Elections.**

That a sum not exceeding ₹ **925,81,39,000 for revenue expenditure** and ₹ **991,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 38 - **Public Health & Water Supply.**

That a sum not exceeding ₹ **60,92,04,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 39 - **Information & Publicity.**

That a sum not exceeding ₹ **3342,83,82,000 for revenue expenditure** and ₹ **984,10,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 40 - **Energy & Power.**

That a sum not exceeding ₹ **24,30,05,000 for revenue expenditure** and ₹ **1,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 41 - **Electronics & IT.**

That a sum not exceeding ₹ **244,64,74,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 42 - **Administration of Justice.**

That a sum not exceeding ₹ **84,02,87,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 43 - **Prisons.**

That a sum not exceeding ₹ **37,98,73,000 for revenue expenditure** and ₹ **17,00,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 44 - **Printing & Stationery.**

That a sum not exceeding ₹ **956,90,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2011-12 in respect of charges under Demand No. 45 - **Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.30 A.M. tomorrow, the 15th March, 2011.

*19.38 बजे (The Sabha then *adjourned till 10.30 A.M. on Tuesday, the 15th March, 2011.)

48759—H.V.S.—H.G.P., Chd.